राजस्थान विधान सभा

अठारहवीं बैठक, गुरुवार, दिनांक २२ मार्च, सन् १९५६ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ११.१० बजे प्रारम्भ हुई।

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष—प्रश्न, श्री भोपालसिंह।

प्रश्न संख्या ९९

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या १००

बीकानेर पशु-चिकित्सा महाविद्यालय से पशु चिकित्सालय तक छात्रों के आवागमन हेतु बस व्यवस्था

श्री प्रभूदयाल—क्या कृषि मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) बीकानेर पशु चिकित्सा महाविद्यालय से पशु चिकित्सालय तक छात्रों के आवागमन हेतु क्या बस आदि की कोई व्यवस्था है ?

(ख) अगर हां, तो बजट में कितना प्रोवीजन रखा गया है ? यदि नहीं तो क्यों नहीं।

श्री रामनिवास मिर्धा—(कृषिमंन्त्री) (क) नहीं।

(ख) बजट में कोई प्रोवीजन नहीं है, जल्दी व्यवस्था कर दी जावेगी।

श्री प्रभुदयाल—कब तक और किस तरह, किस रूप में ?

श्री रामनिवास मिर्धा—इसके लिए अलग से सप्लीमेन्टरी डिमान्ड बो ली जावेगी।

प्रश्न संख्या १०१

१ जनवरी, १६५५ के पश्चात् सरवाड़ तहसील में चोरियां एवं बरामद शुदा माल

श्री चांदमल मेहता—क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(१) १ जनवरी, ५५ के बाद सरवाड़ तहसील में कुल कितनी चोरियां हुईं और उनमें कितने रुपयों का माल चोरी गया ?

(२) उक्त चोरियों में, कितनी चोरियों में कितने रुपयों का माल बरामद कराया गया ?

(३) ऐसी कौन कौन चोरियां हैं जिनमें कोई बरामदगी नहीं हुई है ?

श्री रामकिशोर व्यास—(१) १ जनवरी, १६५५ के बाद सरवाड़ तहसील में २० चोरियां हुईं, जिनमें ३६५८—२—० पाई का माल चोरी गया।

(२) उक्त चोरियों में से ४ चोरियों का रुपया ३२१, का माल, बरामद किया गया।

(३) निम्नलिखित चोरियों में कोई बरामदगी नहीं हुई

१. एफ. आई. आर.	नम्बर १ दिनांक	१०-१-५५
२. ,,	२ ,,	१४-१-५५
३. ,,	७ ,,	२८-२-५५
४. ,,	८ ,,	२८-२-५५
५. ,,	२० ,,	१६-६-५५
६. ,,	२२ ,,	१७-७-५५
७. ,,	२५ ,,	२७-७-५५
८. ,,	२८ ,,	१६-१०-५५
६. ,,	५ ,,	२३-२-५५
१०. ,,	१० ,,	२६-३-५५
११. ,,	१२ ,,	१-४-५५
१२ ,,	१४ ,,	१-५-५५
१३, ,,	१५ ,,	२-५-५५

[श्री रामकिशोर व्यास]

१४.	,,	१७	,,	२४–५–५५
१५.	,,	२५	,,	१२–८–५५
१६.	,,	३०	,,	२०–११–५५

श्री चांदमल मेहता—इतनी तादाद में चोरियों कि कोई बरामदगी नहीं हुई, उसका क्या कारण है ?

श्री रामकिशोर व्यास—वे ट्रेस अप नहीं हुई हैं, उनके प्रूफ नहीं मिले हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि वहां के सब इन्सपेक्टर पुलिस प्रूफ मिलते हुए भी बरामदगी करने में असमर्थ रहे हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—इसका तो मैं निवेदन नहीं कर सकता हूं। लेकिन मैं खुद महसूस करता हूं कि जो बरामदगिये हुई हैं वे कम हैं, उनको हिदायत कर दी जायगी कि ज्यादा से ज्यादा करें।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार ने सरवाड़ तहसील में कोई जांच की ? वहां जो चोरियां हुई हैं उनकी ज्यादा बरामदगियां नहीं हुई हैं, उनके क्या कारण हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—अलग तरीके से जांच करने का मौका नहीं मिला है।

श्री चांदमल मेहता—क्या मंत्री महोदय की यह जानकारी में है कि इस सब इन्सपेक्टर के खिलाफ कुछ शिकायतें मंत्री महोदय के पास आ चुकी है कि उसने गड़बड़ की है और वह पूरी तरह से साबित है ?

श्री रामकिशोर व्यास—उसके खिलाफ मैंने एनक्वायरी का ऑडर दे दिया था शायद वह आपको याद होगा।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि एन्क्वायरी का ऑडर देने के बाद भी उसके संबंध में जांच नहीं हुई और कागजात अभी दबे हुए हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—नहीं जांच हुई है। वह आई. जी. पी. साहब के यहां है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह समझा जाय कि जांच होने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास—मुझे पूरी जानकारी इस विषय में नहीं है। जांच का क्या नतीजा हुआ वह आने पर मालूम होगा।

श्री चांदमल मेहता—क्या मंत्री महोदय भविष्य में ऐसी व्यवस्था करेंगे कि इस प्रकार की चोरियां होती हैं और माल की बरामदगी नहीं होती है उसके सम्बन्ध में भविष्य में अच्छी तादाद में बरामदगियां हो सकें ?

श्री रामकिशोर व्यास—मैंने खुद ने कहा कि इसमें कमी है।

श्री चांदमल मेहता—क्या कोई इस तरह का नियम बनाया गया है कि अमुक पर्सेन्टेज में बरामदगियां होनी आवश्यक मानी जायेंगी ?

श्री रामकिशोर व्यास—ऐसा रूल नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या ऐसा भी रूल है कि कोई सब इन्सपेक्टर अधिक तादाद में, अधिक पर्सेन्टेज में बरामदगियां करते तो अच्छे रिमार्क्स शीट में दिये जाते हैं ?

श्री हिम्मतसिंह अटरू—क्या जो चोरियां होती हैं, वे सिम्पल फेक्ट हैं या बर्गलरी भी हैं !

श्री रामकिशोर व्यास—१० बर्गलरी और १० आॅर्डीनरी।

प्रश्न संख्या १०२

पशु चिकित्सालयों के बजट में आवारा बीमार पशुओं के लिये व्यवस्था

श्री प्रभुदयाल—क्या कृषि मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(क) राजस्थान में पशु चिकित्सालयों के बजट में आवारा बीमार पशुओं के लिये प्रोवीजन हर एक अस्पताल का अलग अलग कितना है ?

(ख) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामनिवास मिर्धा (कृषि मंत्री)—(क) कोई प्रोवीजन आवारा पशुओं के लिए नहीं रखा हैं।

(ख) आवारा बीमार पशुओं की चिकित्सा अन्य बीमार पशुओं के समान हो जाती है, जिससे अलग धन राशि नियुक्त करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

श्री प्रभुदयाल—आवारा बीमार पशुओं को अस्पताल में ले जाते हैं, तो उनके लिए प्रोवीजन की व्यवस्था क्यों नहीं होती है ? क्या सरकार उसकी आवश्यकता नहीं समझती ?

Page No 5

श्री रामनिवास मिर्धा—सरकार के पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, कि जिससे कि वे आवारा पशुओं को इकट्ठा करके अस्पताल में रख सकें और ट्रीटमेंट करें जो, बीमार होते हैं और बीमारी फैलने की स्थिति होती है, उनका इलाज किया जाता है।

श्री प्रभुदयाल—जो आवारा होते हैं और बीमार होते हैं उनकी रक्षा करने की क्या सरकार अपनी जिम्मेवरी नहीं समझती ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

श्री श्रीदास गोयल—क्या डेडीकेटेड बुल्स ओकरान के लिए कोई व्यवस्था है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—किन की ?

श्री श्रीदास गोयल—डेडीकेटेड बुल्स के लिए चिकित्सा की व्यवस्था है या नहीं ?

श्री रामनिवास मिर्धा—ज्यादातर डेडीकेटेड बुल्स का इन्तजाम ग्राम पंचायतें और म्युनिसिपल कमेटीज की देख रेख में होता है। ऐसी स्थिति नहीं होती है, क्योंकि आवारा पशुओं को खाने को मिल जाता है।

श्री प्रभुदयाल—क्या सरकार भविष्य में ऐसा करने का विचार रखती है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—फिलहाल तो नहीं।

प्रश्न संख्या १०३

राजस्थान के प्रथम श्रेणी के पशु चिकित्सालयों में एक्सरे मशीन-विशेषतया बीकानेर में

श्री प्रभुदयाल—क्या कृषि मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) राजस्थान में फर्स्ट क्लास पशु चिकित्सालयों में कहां कहां एक्सरे मशीनें हैं ?

(ख) क्या बीकानेर पशु चिकित्सालय में एक्सरे मशीन है ?

(ग) क्या यह सही है कि उस मशीन के न होने से यहां काफी कैसेज बिगड़ चुके हैं ?

(घ) क्या सरकार यहां एक्सरे मशीन लगाने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री रामनिवास मिर्धा (कृषि मंत्री)—(क) जयपुर में।

(ख) हां।

(ग) नहीं।

(घ) इसके लिए कालेज को एक्सरे मशीन दिये जाने का इन्तजाम हो चुका है।

श्री प्रभूदयाल—क्या सरकार वहां अस्पताल में मशीन लगाने का विचार रखती है?

श्री मिर्धा—अस्पताल में फिलहाल कोई एक्सरे की मशीन लगाने का विचार नहीं है लेकिन जो कालेज में एक्सरे की मशीन लगाई जायगी, उसका उपयोग अस्पताल वाले भी कर सकेंगे।

श्री प्रभुदयाल—क्या सरकार और और जगह भी जहां फर्स्ट क्लास अस्पताल हैं, वहां २ मशीनें लगाने का विचार रखती है?

श्री मिर्धा—फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है।

प्रश्न संख्या १०४

राजस्थान में सहायक रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव विभाग के स्थानों की संख्या, वेतन, लेन्गथ ऑफ सरविस आदि

श्री चांदमल मेहता—क्या मन्त्री सरकारी विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(१) राजस्थान में एसिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, कोऑपरेटिव विभाग, के कितने स्थान स्वीकृत हैं?

(२) उक्त स्थानों पर कौन २, कब २ से किस २ वेतन पर काम कर रहे हैं व प्रत्येक की योग्यता व लेन्गथ ऑफ सर्विस कितनी है?

श्री खेतसिंह—(उप मंत्री)—(१) रजिस्ट्रार, कोऑपरेटिव विभाग, के निजी सहायक के सहित कुल दस सहायक रजिस्ट्रारों के स्थान हैं।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

Page No 7

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि चालू वर्ष में जिन व्यक्तियों को असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार बनाया गया है, उनमें ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनको सहकारी विभाग के बारे में कोई ज्ञान नहीं है।

श्री खेतसिंह—आपके पास सूची भेज दी गई है, उसके अन्दर साफ लिखा है कि वह सब ट्रेन्ड हैं। उनकी क्वालिफिकेशन देखकर बातें करें।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि श्री गोविन्दकांत शर्मा सहकारी विभाग का ए. बी. सी. भी नहीं जानते हैं ?

श्री खेतसिंह—यह गोविन्द कान्त पहले एम्प्लाईमेंट एक्सचेंज आफिसर, कोटा, थे। इनका सरविस रेकार्ड अभी तक हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन इनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है।

श्री चांदमल मेहता—जो इन्सपेक्टर ट्रेन्ड हैं और जिनके बारे में पब्लिक सर्विस कमीशन ने तय किया है कि अमुक २ व्यक्तियों को असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार बनाया जाय तो फिर श्री गोविन्द कांत को असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार बनाये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री खेतसिंह—कौन से इन्सपेक्टर ट्रेन्ड हैं, आप नाम बताइये तो मैं आपको बतलाऊंगा।

श्री मेहता—ऐसा मालूम होता है कि आपको अपने विभाग की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है।

१० इन्सपेक्टटर ऐसे हैं जिनके बारे में पब्लिक सरविस कमीशन ने लिखा है कि इनको असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार के पद पर लिया जाय, उनको न लेकर श्री गोविन्द कांत को असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार क्यों बनाया गया है।

श्री खेतसिंह—श्री गोविन्द कांत उसी ग्रेड के आफिसर हैं और ये ट्रेनिंग पा रहे हैं, इस लिए उनको लिया गया है।

श्री चांदमल मेहता—आपने कहा कि वे ट्रेनिंग पा रहे हैं, तो क्या जाने से पहले ट्रेनिंग पा रहे थे ?

श्री खेतसिंह—नहीं अब पा रहे हैं।

श्री मेहता—क्या यह सही है कि इनके लिए जाने का मूल कारण यही है, कि ये एक मन्त्री महोदय के सुपुत्र हैं ?

Page No 8

श्री खेतसिंह—यह कोई सवाल नहीं है।

प्रश्न संख्या १०५

बीकानेर पशु चिकित्सालय में ऊंटों को धूप व बारिश से बचाने के हेतु छप्पर की व्यवस्था

श्री प्रभुदयाल—क्या कृषि मन्त्री निम्नप्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या बीकानेर पशु चिकित्सालय में बीमार ऊंटों को धूप व बारिश से बचाने के लिए छप्पर आदि की कोई व्यवस्था है ?

(ख) अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(ग) क्या सरकार इस ओर शीघ्र ही कदम उठायेगी ?

श्री रामनिवास मिर्धा (कृषि मन्त्री)—(क) अलग व्यवस्था नहीं है परन्तु बारिश और धूप से बीमार ऊंटों को ड्रेसिंग शैड में बांध दिया जाता है।

(ख) अब अलग व्यवस्था करने के लिये ५,००० रु० की मंजूरी दे दी गई और कार्य शीघ्र ही पूर्ण हो जायगा।

(ग) जी हां।

श्री प्रभुदयाल—यह इसी साल तक पूरा हो जायगी या आगे और समय लगेगा ?

श्री मिर्धा—५ हजार रुपये एक्जीक्यूटिव इन्जीनीयर, बिल्डिंग्स एण्ड रोड्स को दे दिये गये हैं और आशा की जाती है कि जल्दी ही काम हो जायगा।

श्री प्रभुदयाल—क्या यह सही है कि एग्जीक्यूटिव इन्जीनीयर की डिले की वजह से छप्पर नहीं बन रहा है।

श्री मिर्धा—शीघ्र ही बन जायगा। डिले की वजह हो ऐसी बात नहीं है।

श्री प्रभुदयाल—क्या कोई शिकायत आपके पास इस प्रकार की आई है कि एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर की वजह से इतनी देर हो रही है ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट। श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या १०६

तालाब बारणी-सागर, ग्राम केबानिया (त० अराई) का जीर्णोद्धार

श्री चांदमल मेहता—क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) तालाब वारणी सागर ग्राम केबानियां (तहसील अराई) कब टूटा ?

(ख) उक्त तालाब के पीछे कितनी भूमि है ?

(ग) चालू फसल में उक्त तालाब से कितनी भूमि की सिंचाई की गई है ?

(घ) उक्त तालाब की मरम्मत कराने के लिये कब कब आवेदन पत्र पेश हुए और उन पर क्या कार्यवाही की गई—

श्री रामनिवास मिर्धा (सिंचाई मन्त्री)—सिंचाई विभाग के मातहत इस नाम का कोई तालाब तहसील अराई में नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—यह किस विभाग के मातहत है ? सिंचाई विभाग को यह भी जानकारी है क्या ?

श्री रामनिवास मिर्धा—इस तालाब के मातहत १०० एकड़ जमीन है। पहले यह जागीर में था और अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मातहत है।

श्री अध्यक्ष—श्री छतरसिंह।

प्रश्न संख्या १०७

श्री अध्यक्ष—श्री छीतरसिंह।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या १०८

चालू वर्ष में अमोनियम सलफेट के क्रय विक्रय की दरें

श्री चांदमल मेहता—क्या कृषि मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

[श्री चांदमल मेहता]

(क) चालू वर्ष में कुल कितना अमोनियम सल्फेट किस किस रेट पर खरीद किया गया और किस २ जिले में किस किस रेट पर बेचा गया ?

(ख) किशनगढ़ में अमोनियम सल्फेट किस रेट पर बेचा गया ?

(ग) कृषि विभाग को अमोनियम सल्फेट के क्रय विक्रय पर क्या हानि व लाभ चालू वर्ष में हुआ ?

श्री रामनिवास मिर्धा (कृषि मन्त्री)—(क) चालू वर्ष में कोई अमोनियम सलफेट नहीं खरीदा गया।

(ख) अमोनियम सलफेट सारे राजस्थान में रु० ३४५ प्रति टन के हिसाब से बेचा जाता है।

(ग) इसका उत्तर प्रश्न (ख) अन्तर्हित है।

(घ) अमोनियम सलफेट हानि व लाभ सम के सिद्धान्त पर बेचा जाता। है अतः कृषि विभाग को न हानि, न लाभ होता है।

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, 'क' का यह जवाब नहीं मिला कि किस किस जिले में किस २ रेट पर बेचा ?

श्री रामनिवास मिर्धा—सारे राजस्थान में एक ही रेट पर बेचा जाता है।

श्री चांदमल मेहता—किस २ जिले में अब के कितना बेचा गया ?

श्री रामनिवास मिर्धा—यह जानकारी आपने चाही नहीं। रेट के बारे में पूछा था इसलिए जवाब दे दिया।

श्री चांदमल मेहता—जो अलमोनियम सल्फेट खरीद हुआ था। वह किस भाव का था, यह कह जाता है कि नो प्रोफिट नो लोस पर बेचा जाता है, तो खरीद हुआ तो किस रेट पर खरीद हुआ ?

श्री रामनिवास मिर्धा—खरीद हुआ, वह रेट मेरे पास अभी नहीं है। डिस्ट्रीब्युशन चार्जेज एड करके भाव में डिफरेन्स रखा जाता है, जिस भाव से खरीदा और जिस रेट से बेचा उसमें ताकि भिन्न २ जगहों के लिए राजस्थान में भिन्न रेट्स न हों।

Page No 11

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जो रेट बढ़ाकर रखी गई है वह इतनी ज्यादा है कि अगर उसको नो प्रोफिट नो लोस न होकर गड़बड़ी होती है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—तसल्ली कराली गई थी।

श्री चांदमल मेहता—कब और किस अधिकारी द्वारा कराली गई थी ?

श्री रामनिवास मिर्धा—जब रेट फिक्स की गई थी कराली गई थी कि मुनाफा होगा या नो प्रोफिट नो लोस पर बिक सकेगा।

श्री चांदमल मेहता—यह कितने साल पहले बिका था ?

श्री रामनिवास मिर्धा—यह जो ज्यों २ सिन्धरी फर्टीलाइजर से मिलता है उसका हिसाब करके हर कन्साइन्मेन्ट को दे दिया जाता है।

श्री चांदमल मेहता—भाव कम बेशी होने से होता है, या ज्यादा होता रहता है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—दो साल पहले ३८०) की रेट थी और वही हमारे यहां भी थी। बाद में वह घटा दी गई तो हमने भी उसको ३४५ कर दिया।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १०६

सरकार की बोरिंग मशीनें एवं सार्वजनिक कार्यों के लिए देनेकी दरें

श्री केसरीसिंह—क्या कृषि मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) सरकार के पास कितनी बोरिंग मशीने हैं और वे अभी कहां २ काम कर रही हैं ?

(ख) सरकार इनको सार्वजनिक कार्यों में मुफ्त देती है अथवा फीस लेती है ?

(ग) घरू उपयोग के लिये सरकार किस दर से फीस लेती है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—(कृषि मंत्री) (क) इस समय बोर्ड के पास कुल ६ मशीने उपलब्ध है। जिनमें से दो मशीने खराब हैं बाकी मशीनें निम्नलिखित स्थानों पर कार्य कर रही हैं:—

१. जयपुर

२. गोहाला (नीम का थाना)

[श्री रामनिवास मिर्धा]

३. बाड़मेर

४. सानाही (पाली)

(ख) मशीनें नियत नियमों के अनुसार निर्धारित दरों पर दी जाती हैं।

(ग) घरू उपयोगों के लिये यह नियम लागू हैं।

श्री केसरी सिंह—ये मशीनें कब से खराब हैं ?

श्री रामनिवास मिर्धा—दो मशीनें जब अन्डरग्राउन्ड वाटर बोर्ड ने ट्रान्सफर की तब से है। दूसरी मशीनें पहले से खराब हैं और उनको रिपेयर करने के लिए उनके मैन्यूफेक्चरर्स और ओरिजिनल डिलरर्स को लिखा लेकिन स्पेयर पार्टस् आसानी से नहीं उपलब्ध हो रहे हैं।

श्री केसरीसिंह—क्या यह सत्य है कि ये आये तब से खराब हैं ?

श्री रामनिवास मिर्धा—आये तब से नहीं थे।

श्री केसरीसिंह—इन मशीनों ने कितने साल ठीक तरह से काम किया ?

श्री रामनिवास मिर्धा—हर एक मशीनों के बारे में बता नहीं सकता कि कितनी पुरानी है, किस मोडल की है। करीब करीब सब को यह हालत है।

श्री अध्यक्ष—कितने साल अच्छी तरह से काम किया ?

श्री रामनिवास मिर्धा—यह जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री केसरी सिंह—किस दर पर दी जाती हैं ?

श्री रामनिवास मिर्धा—३० पर फुट के हिसाब से खोदते हैं। उसके बाद अगर खास पाइप लगाना है तो उस के लिए रेट अलग है और इसी तरह से कोपर पाइप लगाना है तो उसकी रेट अलग है।

श्री केसरीसिंह—क्या ये मशीनें जब से आयी हैं तो वहीं काम कर रही हैं जहां आपने बताया ?

श्री रामनिवास मिर्धा—मैं निश्चित तो नहीं कह सकता हूं। जब एक जगह काम खत्म हो जाता है तो दूसरी जगह जाती है।

Page No 13

श्री केसरीसिंह—क्या उन मशीनों को बूंदी डिस्ट्रिक्ट में भेजने का इरादा है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—अगर मांग हुई और उपलब्ध हुई तो जरूर आवेगी।

श्री केसरीसिंह—क्या बूंदी से मांग हुई थी ?

श्री रामनिवास मिर्धा—ऐसी जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री दिलीपसिंह ऑफ बाठरड़ा—कितनी एप्लीकेशन्स पर एक मशीन भेजी जा सकती है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—जहां से मांग आती है तो इन्जीनियर को भेजते हैं और वह देखते हैं कि यहां उपयुक्त होगा या नहीं और यदि आस पास के इलाकों को भी जरूरत हो तो इन सारी बातों को देख कर अगर मशीन स्पेयर हो तो भेज दी जाती है।

श्री दिलीपसिंह—कितने कुओं के ऊपर दी जा सकती है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—कोइ निर्धारित नहीं है। एक कुए पर भी भेजी जा सकती है।

श्री केसरीसिंह—मांग का तरीका क्या है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—बाकायदा रूल्स हैं, फार्म्स हैं और उनके हिसाब से अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड को एप्लाई कर सकते हैं।

श्री केसरीसिंह—यह कलेक्टर के मार्फत या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के मार्फत ?

श्री रामनिवास मिर्धा—यह पहले एग्रीकल्चर विभाग के पास थीं जो कि अब अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड को ट्रान्सफर कर दी गई हैं। चाहे एग्रीकल्चर डि० को या वाटर बोर्ड डिपार्टमेंट को एप्लाई कर दें।

प्रश्न संख्या ११०

श्री अध्यक्ष—श्री विशम्भरनाथ जोशी।

(अनुपस्थित)

(यह प्रश्नोत्तर कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १११

श्री अध्यक्ष—श्री भोपालसिंह जी।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये।)

प्रश्न संख्या ११२

श्री शम्भूसिंह

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

(कृपया यह प्रश्नोत्तर आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ११३

श्री भोपालसिंह

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ११४

श्री भोपालसिंह

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री चांदमल मेहता

प्रश्न संख्या ११५

१ जनवरी १६५५ के पश्चात् सरकारी विभाग में नियुक्तियां, उनके नाम, योग्यता, लेंग्थ ऑफ सर्विस एवं उनके हेतु आमंत्रित आवेदन पत्र

श्री चांदमल मेहता—क्या मंत्री, सहकारी विभाग, निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(श्री चांदमल मेहता)

(१) १ जनवरी, १९५५ के बाद सहकारी विभाग, में कुल कितनी नई नियुक्तियां की गई ?

(२) जिन व्यक्तियों की नई नियुक्ति की गई उनके नाम, योग्यता व लेंग्थ ऑफ सर्विस क्या है ?

(३) १ जनवरी, १९५५ के बाद जिन स्थानों पर नई नियुक्तियां की गई क्या उनके लिए कोई आवेदन पत्र आमन्त्रित किए गए थे ?

(४) यदि हां; तो किस किस पोस्ट के लिए और कब कब ?

(५) नई नियुक्तियां किस आधार पर किसके द्वारा की गई हैं ?

श्री खेतसिंह (उपमंत्री)—(१) १३१.

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(३) सूची के खाना न० ६ में इसका उल्लेख कर दिया गया है ।

(४) इसका उत्तर ऊपर दिया जा चुका है ।

(५) सूची के खाना न० ७ में इसका उल्लेख कर दिया गया है ।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिए)

श्री चांदमल मेहता—जिन व्यक्तियों की नई नियुक्तियां की गई और जिसका पी. एस. सी. के मार्फत सिलेक्शन हुआ उनकी नियुक्तियां बिना आवेदन पत्र के आमन्त्रित किए क्यों की गई ?

श्री खेतसिंह—उनके अपोइन्टमेंट टेम्परेरी किए गए और उनको फिर पी. एस. सी. के सामने भेजा गया ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने नहीं भेजा गया ।

श्री खेतसिंह—हां, कुछ टेम्पोरेरी आदमी ऐसे है जो पी. एस, सी के सामने नहीं गये हैं । उनका अपोइन्टमेन्ट टेम्परेरी है ।

श्री चांदमल मेहता—ऐसे व्यक्तियों का अपोइन्टमेन्ट टेम्परेरी कितने समय के लिये किया गया था ?

श्री खेतसिंह—शुरू में छः महीने के लिये किया गया था ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि ऐसे व्यक्ति इसमें मौजूद हैं जिनका छः महीने से अधिक समय बीत गया है और अब तक वे पी. एस. सी से कन्फर्म नहीं हुए हैं ?

श्री खेतसिंह—कुछ आदमियों की आवश्यकता के माफिक आगे भी कुछ अर्से के लिए मियाद बढ़ाई।

श्री चांदमल मेहता—क्या टेम्परेरी अपोइन्टमेन्ट के लिए आवेदन पत्र मंगाना सरकार आवश्यक नहीं मानती ?

श्री खेतसिंह—अगर कहीं ज्यादा जरूरत पड़ती है तो टेम्परेरी अपोइन्टमेंट आवेदन पत्रों के बगैर ही कर सकते हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जिन वर्षों में आमतौर पर इन्सपेक्टर और सहायक इन्सपेक्टरों को छोड़ कर बाकी दूसरे व्यक्तियों को बगैर आवेदन पत्र मांगे ही अपोइन्ट किया गया ?

श्री खेतसिंह—ऐसी बात नहीं।

श्री किशनलाल शाह—क्या टेम्परेरी व्यक्ति आगे के लिए प्रोब्लम नहीं बनते ?

श्री खेतसिंह—ऐसी बात नहीं है। उन सबको पी. एस. सी के सामने भेजते हैं। उनमें जो उपयुक्त होता है वह सिलेक्ट हो जाता है और बाकी नये रिक्रूट किये जाते हैं।

श्री किशनलाल शाह—क्या यह वास्तविक है ?

श्री खेतसिंह—मैं तो इसे सही नहीं समझता। क्योंकि टेम्परेरी अपोइन्टमेंट जरूरत पड़ने पर करने पड़ते हैं और बाद में वे पी. एस. सी के सामने जाते हैं।

श्री किशनलाल शाह—क्या केडर और अपोइन्टमेंट पहले से ही निश्चित किये जाते हैं और उसके माफिक व्यक्तियों का चुनाव क्या पर्सन्स के दृष्टिकोण को सामने रख कर करती है ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—जहां अवधि बढ़ायी गई टेम्परेरी अपोइन्टमेंट्स करने के बाद तो वह कुल कितनी बढ़ा दी गई है ?

श्री खेतसिंह—तीन तीन महीने की और बढ़ायी गई है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं टोटल पूछ रहा हूं। छः महीने से तीन महीने बढ़ा कर अब तक कितना लोंगेस्ट पीरियड कन्टीन्यू किया जा रहा है ?

Page No 17

श्री खेतसिंह—टोटल पीरियड अभी नौ महीने के अन्दर है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि टेम्परेरी अपोइन्टमेन्ट का अधिकार सरकार को केवल मेक्सिमम छः महीने है तो उससे ज्यादा कन्टीन्यू करने का क्या कारण है ?

श्री खेतसिंह—इसके लिये पब्लिक सर्विस कमिशन का एप्रूवल ले लेते हैं और ज्यों ज्यों जरूरत होती है एक्सटेन्शन करते रहते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि इन एपोइन्टमेंटों को ६ महीने पूरे होने पर भी लगातार सिमिलर पोस्टों में लगातार उनको एडजस्ट करके अवधि बढ़ाई जाती है ?

श्री खेतसिंह—नहीं।

श्री अध्यक्ष—It isa diherent thing as to whether there is a breach of Iaw of not-

श्री हरिकृष्ण व्यास—Because thesame person has continued for more than six months without the Sanction of the Public service Commi-ssion.

श्री अध्यक्ष—Only the facts could be disclosed no the floor of the House. whether there is abreach of law of not, it isa different atfair.

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह बात सही है कि यह जो एक्सटेन्शन किया गया है उसमें पब्लिक सर्विस कमिशन की मन्जूरी ले ली गई है ?

श्री खेतसिंह—६ महीनों में कोई आवश्यकता नहीं पड़ी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—६ महीनों से ज्यादा समय, किसी को रिटेन करने का जब मौका आता है तो आपने फरमाया कि पब्लिक सर्विस कमिशन की मन्जूरी लेते हैं। क्या इस सम्बन्ध में आपने पब्लिक सर्विस कमिशन का एप्रूवल लिया ?

श्री खेतसिंह—हां एप्रूवल लेली गई थी।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ११६

अलवर शहर पुराने पोलो मैदान के निकटस्थ डेरी फार्मों की भूमि श्री शोभाराम एम. पी अलवर को देना

श्री भवानीसहाय शर्मा—क्या कृषि मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(क) अलवर शहर के पुराने पोलो ग्राउन्ड के पास कृषि व डेयरी फार्म कितने समय से चले आ रहे थे ?

(ख) क्या यह फार्म बन्द करके यह सरकारी जमीन श्री शोभाराम एम. पी. अलवर को पट्टे पर दे दी गई है ? यदि हां, तो वह जमीन कितनी बीघा है और कितने समय के लिये दी गई है ?

(ग) क्या यह सच है कि अलवर में शरणार्थियों तथा लैंड लैंस टोनेन्ट्स को १६ बीघा से अधिक जमीन अलोट नहीं होती है ?

(घ) यदि हां तो फिर श्री शोभाराम को इस नियम के विरूद्ध अधिक जमीन क्यों दी गई है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—(क) भूतपूर्व अलवर राज्य के समय से ।

(ख) कृषि फार्म बन्द कर दिया गया है और भूमि राजस्व विभाग (रेवेन्यू) को सौंप दी गई है ?

(ग) इसका कृषि विभाग से कोई संबंध नहीं है ।

(घ) प्रश्न ही नही उठता ।

श्री भवानीसहाय शर्मा—मैंने पूछा उसका कोई जवाब नहीं । मैंने नाम बताया श्री शोभाराम को दी गई, इसका कोई उत्तर नही ?

श्री रामनिवास मिर्धा—चूंकि कृषि फार्म बन्द हो गया था इस जमीन की हमको जरूरत नहीं थी हमने वह राजस्व विभाग को सुपुर्द कर दी और यह राजस्व विभाग के ध्यान में होगा कि किसको दी और क्यों दी ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह जमीन कब ट्रान्सफर की गई ?

श्री रामनिवास मिर्धा—इसके बारे में मेरे पास डिटेल्स सूचना नहीं है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या इसके बारे में गत वर्ष सरकार को लेना तय हो गया था इसलिये इस पर बहुत कुछ कार्य करने की मंजूरी हो चुकी थी ?

श्री रामनिवास मिर्धा—यह मेरी जानकारी में नहीं है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—पहले इसको ट्रान्सफर करने के बारे में यह कहा गया कि हम इस जमीन को फार्म के लिये आवश्यक मानते हैं।

श्री रामनिवास मिर्धा—इस जमीन को फार्म के लिये आवश्यक नहीं मानते हुए ही ट्रान्सफर की गई थी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरा प्रश्न यह नहीं है। मेरा प्रश्न यह है कि इस जमीन को रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ट्रान्सफर करने से पहले इस जमीन पर काफी काम किया गया था ?

श्री रामनिवास मिर्धा—ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह जमीन फार्म के लिये आवश्यक नहीं है, इसका निर्णय कब हुआ ?

श्री रामनिवास मिर्धा—मैंने कहा कि अभी तक निश्चित तिथि तो मेरे पास नहीं है, अगर आप पूछेंगे तो जानकारी प्राप्त करके बता दूंगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह निर्णय ट्रान्सफर की एप्लीकेशन आने के बाद में किया गया ?

श्री रामनिवास मिर्धा—अगर आप इसमें इतना इन्ट्रेस्ट लेते हैं तो मैं जानकारी प्राप्त करके बता दूंगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि इसका ट्रान्सफर और रेवेन्यू विभाग में लेने के आर्डर एक ही दिन हुए ?

श्री रामनिवास मिर्धा—कृषि के बारे में तो मैं बता सकता हूं रेवेन्यू के बारे में नहीं बता सकता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या वहां के कलेक्टर ने कुछ रिकमन्डेशन भेजी थी ?

श्री रामनिवास मिर्धा—मैं तो कृषि विभाग की बात बता सकता हूँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि राजस्व विभाग ने उसको कृषि विभाग के पास भेजा था ?

श्री रामनिवास मिर्धा—यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ११७

बसवा तहसील में सावां नदी पर ग्राम गादरवाड़ा के निकट बांध योजना को

स्थगित करने सम्बन्धी

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—क्या सिंचाई मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—(अ) बसवा तहसील में सांवा नदी पर ग्राम गादरवाड़ा के निकट जो बांध बनाने की योजना सिंचाई विभाग ने सर्वे इत्यादि के बाद तैयार की थी वह अचानक क्यों ठप्प करदी गई है ?

(ब) क्या इस योजना के स्थान पर सिंचाई विभाग ने कोई दूसरी योजना इस तहसील की जमीन की सिंचाई की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये तैयार की है ?

(स) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(द) क्या सरकार इस गादरवाड़ा बांध योजना को शीघ्र क्रियान्वित करने अथवा इसके बजाय सांवा, पलासन या बाणा नदियों में से किसी भी नदी पर तहसील बसवा के लिये एक दूसरे बांध का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश प्रदान करेगी ?

श्री खेतसिंह (उपमंत्री)—(अ) गादरवाड़ा बांध बनने से बाण गंगा नदी के पानी में, जिससे भरतपुर के इलाके में सिंचाई होती है, कमी पड़ जावेगी।। अतः इस बांध की योजना नामंजूर करनी उचित समझी गई है।

(ब) नहीं।

(स) इस इलाके में सिंचाई के लिये कोई अन्य उपयुक्त मौका अब तक नहीं मिला है जहां सिंचाई विभाग योजना बना सके।

(द) उपरोक्त उत्तर (अ) व (स) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—क्या इस बात का सर्वे या केल्कुलेशन कराया गया कि कितना पानी की आवश्यकता है और कुल कितना पानी सोरसेज से जाता है ?

श्री खेतसिंह—इस सम्बन्ध में पहले भी प्रश्न पूछा गया था। जब जांच कराई गई और इससे यह नतीजा निकला कि इस पानी को रोकने से भरतपुर में सिंचाई बन्द हो जावेगी।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—जो जांच कराई गई उसके आधार पर कितने पानी की आवश्यकता महसूस की गई। अगर इस सम्बन्ध में आपके पास कोई किसी प्रकार के अंक हों तो बताइये ?

श्री खेतसिंह—फिगर्स तो हमारे पास नहीं हैं।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—फ़िगर्स के वगैर आप कैसे कह सकते हैं ?

श्री खेतसिंह—डिपार्टमेन्ट में इसके फिगर्स हैं। मगर इस समय आंकड़े हमारे पास नहीं हैं।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—क्या आपने फिगर्स देखे हैं ?

श्री खेतसिंह—जी हां, मेरे पास ऐसी सूचना है जिससे मैं कह सकता हूं।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—यह कहा गया कि वहां दूसरे साधन उपलब्ध नहीं होंगे। क्या यह इरिगेशन पोइन्ट ऑफ़ व्यू से सर्वे कराया गया था ?

श्री खेतसिंह—पूरी सर्वे तो नहीं कराई गई है क्योंकि इतना स्टाफ़ नहीं है। लेकिन जल्दी से जल्दी सर्वे पूरी करा लेंगे। इंजीनियर मुकर्रर हो चुका है ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—किस साल में इंजीनियर मुकर्रर किया गया था।

श्री खेतसिंह—इसके लिये मेरे पास तारीख नहीं है।

श्री रामनिवास मिर्धा—अभी हमने दो नये इंजीनियरों को नियुक्त किये हैं और उसमें से एक का हैड क्वार्टर जयपुर रखा गया है। हम सर्वे करवाएंगे जब किसी का कोई सजेशन या रिक्वेस्ट होगी।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ११८

श्री लक्ष्मणसिंह

(कृपया प्रश्नोत्तर आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ११९

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित, कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या १२०

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित, कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ११०

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी

प्रश्न संख्या ११०

राजस्थान सरकार के स्वयं के डेरी व ग्रास फार्म्स एवं उन पर व्यय तथा उनसे आय

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—Will the minister for Agriculture please state:—

(a) What is the total number of farms owned and managed by the Government in Rajasthan ?

(b) How many of these are dairy farms and how many are grass farms ?

(c) What has been the total amount of expenditure incurred on, and the total amount of income derived from, each of these farms by the Government during each of the last three fiscal years ?

(d) Is it a fact that a majorty of these farms have been running in loss during the last two fiscal years ?

(e) What action is contemplated against the departmental officers responsible for the management of the farms thus running in loss ?

(f) What steps does the Government propose to take to remedy the present unecnomic working of these farms ?

श्री रामनिवास मिर्धा—(क) १५ कृषि फार्म ; ३ पशु नस्ल सुधार।

(ख) एक भी नहीं।

(ग) सूची संलग्न है।

(घ) नहीं, कृषि क्षेत्रों की आय व्यय के आंकड़ों की संलग्न तालिका से सिद्ध होगा कि गत दो वर्षों में अधिकांश फार्मों की आय उत्तरोतर बढ़ रही है।

[श्री रामनिवास मिर्धा]

(ङ) यह सब कार्य पर्यवेक्षण के लिये हैं और लाभ की दृष्टि से नहीं चलाये जाते हैं इस लिये ऐसा प्रश्न नहीं उठता।

(च) अनुसंधानिक कार्यों के लिये इस तरह के पर्यवेक्षण फार्म अनिवार्य हैं। फिर भी जहां तक सम्भव है इन फार्मों को लाभप्रद बनाने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री गुरुदयाल सिंह सन्धु—इन फार्म्स में कैसा एक्सपेरिमेन्ट होता है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—एक्सपेरिमेन्ट्स कई तरह के होते हैं। बाजरा, बारले आदि के बीज होते हैं उनको नये नये ढंग से एक्सपेरिमेन्ट किया जाता है।

श्री गुरुदयाल सिंह सन्धु—गंगानगर जिले में जो फार्म्स चल रहे हैं उनमें कैसा एक्सपेरिमेंट हो रहा है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—मैं निश्चित तो नहीं कह सकता कि कैसा कैसा एक्सपेरिमेन्ट वहां होता है लेकिन यह कह सकता हूँ कि वहां के फार्म अच्छी तरह से चल रहे हैं।

श्री गुरुदयाल सिंह सन्धु—क्या यह फार्म घाटे में चल रहा है और बीज सप्लाई नहीं कर रहे हैं ?

श्री रामनिवास मिर्धा—यह बात बिल्कुल गलत है।

श्री गुरुदयाल सिंह सन्धु—क्या सरकार जांच कराने के लिये तैयार है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री विशम्भरनाथ जोशी—प्रश्न के (क) भाग के उत्तर में यह कहा गया कि एक भी ऐसा फार्म नहीं है। क्या राजस्थान में ग्रास फार्म और डेरी फार्म एक भी सरकार की तरफ से नहीं चल रहा है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—ग्रास फार्म के बारे में वन मन्त्रीजी बतायेंगे कि क्या स्कीम है। लेकिन डेरी फार्म सरकार की तरफ से चलाने की अभी आवश्यकता नहीं समझी गई। अलबत्ता जो ऐसे फार्म चलाना चाहते हैं उनको लोन दिया जाता है।

श्री विशम्भरनाथ जोशी—क्या ग्रास फार्म्स नहीं है सरकार के पास ?

श्री रामनिवास मिर्धा—यह फोरेस्ट से तालुक रखता है।

प्रश्न संख्या ११२

राजस्थान में भूस्वामी संघ का आन्दोलन कितने समय से चल रहा है

श्री शंभुसिंह—क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे

(क) राजस्थान में भूस्वामी संघ का आन्दोलन कितने समय से चल रहा है व उसमें कितनी कितनी गिरफ्तारियाँ हुई और किस किस जेल में कितने कितने बन्दी रखे गये हैं:—

(ख) उपरोक्त आन्दोलन के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा कहां कहां लाठी चार्ज हुआ और उसमें कितने कितने सत्याग्रही हताहत हुए ?

(ग) सत्याग्रहियों में से कितने भूख हडताल पर हैं।

(घ) क्या यह सच है कि कतिपय सत्याग्रहियों का निधन भी हुआ है ? यदि हां तो उनके नाम क्या क्या है और वे किस किस तारीख व स्थान पर दिवगत हुए :

श्री रामकिशोर व्यास—(गृह मंत्री) इस प्रश्न का पूरा उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है इसलिये कुछ समय बाद इसका उत्तर दे दिया जायगा।

श्री शंभूसिंह—उत्तर कब तक प्राप्त हो जायगा ?

श्री रामकिशोर व्यास—नेक्स्ट टर्न तक।

प्रश्न संख्या ११८

कलेक्टर्स कार्यालयों में रिन्युअल हेतु दिये गये आर्म्स लाइसेंस की रसीदें

श्री लक्ष्मणसिंह—क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या आर्म्स के जो लाइसेन्स रिन्यूअल के वास्ते कलक्टरों के दफ्तर में दिये जाते हैं उनकी छपी हुई दफ्तर की मोहर शुदा रसीद नहीं दी जाती है ?

Page No 25

[श्री लक्ष्मणसिंह]

(ख) अगर नहीं, तो क्या सरकार भविष्य में पक्की रसीदें देने का आदेश देगी ?

(ग) क्या उपरोक्त लायसेन्स का रिन्यूअल होकर लौटाये जाने का कोई निर्धारित समय है ?

श्री रामकिशर व्यास—(गृह मंत्री :)

(क) जी नहीं । और न इन्डियन आर्म्स रूल्स में कोई ऐसी व्यवस्था ही है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता । भविष्य में इस विषय में समुचित व्यवस्था करदी जायगी ?

(ग) इन्डियन आर्म्स रूल्स में इस तरह का कोई निर्धारित समय नहीं है । गत वर्ष सरकार ने जो आदेश प्रसारित किये उनके अनुसार लाइसेन्स प्रतिवर्ष १५ फरवरी तक रिन्यू कर दिये जाने चाहिये ।

श्री जसवन्तसिंह—क्या यह सही है कि आर्म्स रिन्यूअल फीस भरदी गई और गवर्नमेन्ट् से रिन्यूअल २–३ महीनों तक नहीं आया इस के दर्म्यान में पुलिस आर्म्स मंगाने के लिये जल्दी कर रही है ?

श्री रामकिशोर व्यास—रिन्यूअल के लिये एप्लाई करने के बाद नहीं लेने चाहिये ।

श्री जसवन्तसिंह—रिन्यूअल के लिये एप्लाई कर दिया और उस बीच में ही जबर्दस्ती ले रहे हैं ।

श्री रामकिशोर व्यास—ऐसा करना नहीं चाहिये जानकारी प्राप्त करेंगे । ऐसा हो रहा है या नहीं इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे ।

श्री अध्यक्ष—Application for renewal is equal to grant of a licence ?

श्री जसवन्तसिंह—I know, but our objection is that arms are forciby taken from the licence-holders.

श्री श्री दास गोयल—निर्देशित समय के बाद लाइसेन्स रिन्यूअल के लिये एप्लाई करते हैं तो क्या आर्म्स जब्त किये जाते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—इसके लिये पेनल्टी है । निर्देशित समय के बाद में करते हैं तो पेनल्टी ले ली जाती है ।

Page No 26

अल्प काल सूचना प्रश्नोत्तर

दिनांक १५ मार्च, १९५६ जोधपुर व जयपुर की नगरपालिकाओं द्वारा लगाये गये चुंगी कर सम्बन्धी

श्री भैंरूसिंह (डि. नं० १६)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(क) क्या यह सही कि दिनांक १५–३–५६ से जोधपुर व जयपुर नगरपालिकाओं के प्रशासकों द्वारा चुंगी कर लगाया गया है ?

(ख) यदि हां, तो क्यों ?

(ग) सरकार इन दोनों नगरपालिकाओं के चुनाव होने तक इस चुंगी कर को स्थगित कर सकती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(घ) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा इस प्रकार का चुंगी कर लगाने का फैसला इसके पूर्व भी किया था ? यदि हां, तो कब कब और क्यों स्थगित किया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)

(क) जी हां।

(ख) क्यों कि दोनों नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति इतनी निर्बल हो गई थी कि वे सरकारी सहायता तथा ऋण के बिना अपना दैनिक व्यय भी चला सकने में सर्वथा असमर्थ थीं और राजस्थान की सब म्युनिसिपेलिटियों में सिर्फ दो ही ऐसी थीं जिनमें चुंगी नहीं थी ?

(ग) जी नहीं। उपरोक्त स्थिति के कारण चुंगी कर अब और स्थगित नहीं किया जा सकता।

(घ) जी हां। जयपुर में म्युनिसिपल कौंसिल, जयपुर के प्रस्ताव के अनुसार सरकार ने दिनांक १०–१२–५२ तथा १०–७–५३ को चुंगीकर लगाने की स्वीकृति प्रदान की। तत्पश्चात उक्त कौंसिल ने १–६–५३ से यह कर लागू करने की घोषणा की। कार्यवाही वसूली शुरु होते ही जनता ने रोष प्रगट किया और सरकार ने विचार विनिमय के पश्चात कुछ वस्तुओं पर चुंगी की दर कम की तथा कुछ को इससे मुक्त किया। किन्तु जब इससे भी जनता को संतोष न हुआ तो उनकी मांग के अनुसार तारीख १२–६–५३ को एक कमेटी दरों की छानबीन के लिये नियुक्त की जिसने अपनी सिफारिशें १६–३–५६ को प्रेषित कीं। तदनुसार प्रशासन की सिफारिश पर १८–८–५५ को चुंगी कर लगाने की स्वीकृति दी जिस पर प्रशासक ने १२–११–५५ से कर लगाने

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

की घोषणा तारीख ४–१०–५५ को जारी की। उक्त घोषणा के प्रकाशन होने पर जनता में फिर असन्तोष बढ़ा और अनेक व्यापार मंडलों के प्रतिनिधि आकर सरकार से मिले। इस पर सरकार ने दिनाक ११–११–५५ को एक २१ सदस्यों की कमेटी चुंगी कर के दरों की जांच के लिये नियुक्त की और चुंगी कर स्थगित कर दिया गया। उसकी रिपोर्ट पर अभी चुंगी कर लागु किया गया है।

जोधपुर में चुंगी कर लगाने के विषय में तारीख २७-१०-५० को प्रशासक, म्युनिसिपल बोर्ड, जोधपुर ने प्रपोजल सरकार के पास भेजा। इसकी स्वीकृति दिनांक १६-२-५१ को दी गई जिसके अनुसार चुंगी २८-७-५१ को लागू होने को थी। इसी बीच में निर्वाचन के पश्चात् नवनिर्वाचि बोर्ड ने कार्य भार संभाल लिया और उक्त बोर्ड ने किसी न किसी कारण से इस कर की वसूली आरम्भ नहीं की और बाद में एक प्रस्ताव भी पास कर दिया कि वह कर न लगाया जावे जिसका उसे अधिकार न था।

सरकार के निरन्तर लिखते रहने पर भी बोर्ड ने चुंगी वसूली की कार्यवाही नहीं की अतः तारीख २१-१०-५३ की विज्ञप्ति द्वारा की विज्ञप्ति द्वारा १६-२-५१ के आदेश को आंशिक निरस्त किया गया।

बोर्ड ने तारीख ३१-७-५४ के चुंगी कर लगाने का प्रस्ताव पास करके पुन; सरकार की स्वीकृति के लिये भेजा जिस की तारीख १२-२-५५ को सरकार ने स्वीकृति दी। इसकी वसूली १-८-५५ से शुरू होनी थी परन्तु बोर्ड ने इसकी वसूली की कोई कार्यवाही नहीं की और टालते रहे। बोर्ड के कार्यकाल की अवधि समाप्त होने पर प्रशासक नियुक्त किया गया। उसने स्वीकृत चुंगी कर की वसूली के लिये तारीख १५-३-५६ नियत की। इस सिलसिले में जोधपुर में हड़ताल हुई और विपक्षी राजनैतिक दल जिसमें साम्यवादी भी सम्मिलित हैं चुंगी कर के दरों का विरोध कर रहे हैं कि यह दर जयपुर के चुंगी, कर की दरों के समान ही होनी चाहिये।

सरकार इस पर विचार कर रही है किन्तु चुंगी कर की वसूली स्थगित करने के लिये तैयार नहीं हैं।

(लिखित उत्तर उपलब्ध नहीं हुआ)

श्री भैंरूसिंह—इन दोनो नगरपालिकाओं के चुनाव कब तक होनेवाले हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जयपुर के चुनाव के लिय जो तारीख हैं वह ३ जून को होने का ख्याल है। ऐसा ख्याल है कि ८ अप्रेल को जो इलक्टोरल रोल्स हैं वे पब्लिश कर दिये जायगें।

श्री भैंरूसिंह—क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि जयपुर और जोधपुर नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति २ साल से खराब है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इससे भी पहले से खराब है।

श्री भैंरुसिंह—यदि २ साल से पहले से खराब है तो ४ महीनों के लिये जनता की आवाज पर भी टैक्स क्यों नहीं रोका जाता ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जनता की आवाज खराब नहीं हैं, जनता तो चाहती है।

श्री भैंरुसिंह—अभी आपने फरमाया कि जनता हड़ताल कर रही है तो फिर यह किस बात की द्योतक है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—हड़ताल जनसंघ के प्रयत्नस्वरुप है ।

श्री जसवन्तसिंह—यह हड़ताल जनसंघ द्वारा की जा रही है या पब्लिक द्वारा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जोधपुर में जो हड़ताल हो रही है उसमें कुछ पोलिटिकल पार्टीज हिस्सा ले रहीं हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह हड़ताल कौनसी तारीख को शुरु हुई।

श्री बद्रीप्रसादगुप्ता—१४ तारीख को शुरु हुई।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि ओक्ट्रोय का इंसीडेन्स ओफ टेक्सेशन जयपुर में कितना है और जोधपुर में कितना है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैं सारे राजस्थान का लाया हूं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरे प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जयपुर में इन्सीडेन्स ओफ टेक्सेज चुंगी लगाने का ५ रु० १० आ० है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ओक्ट्रोय का पूछ रहा हूं । only of octroi.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अकेले ओक्ट्रोय का मेरे पास नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह बता सकेंगे कि ओक्ट्रोय की संभावित आमदनी जयपुर में कितनी कूंती जा रही है और जोधपुर में कितनी कूंती जा रही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जयपुर और जोधपुर में कुछ फर्क जरूर है लेकिन और टेक्स जो जयपुर में लगे है वे जोधपुर में नहीं है इसलिये ओक्ट्रोय जयपुर में कम है । जयपुर सिटी में मौजूदा दर पर चुंगी लगाने पर भी जोधपुर में १ रु० पर केपिटा कम रहने वाला है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरे प्रश्न का उतर नहीं आया अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि संभावित आमदनी चुंगी कर से जयपुर में कितनी कूंती गई हैं और जोधपुर में कितनी कूंती गई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यहां पर जयपुर में ४ लाख और जोधपुर में ७ लाख ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या माननीय मंत्री महोदय के यह ध्यान में है कि आबादी की दृष्टि से दोनों शहरों में फर्क होते हुए भी जोधपुर में ७ लाख और जयपुर में ४ लाख यह किस प्रकार से जस्टिफिकेशन किया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जयपुर में चार लाख हाउस टेक्स के और वसूल होते हैं। बहुत से टेक्स ऐसे हैं जिनकी फहरिश्त तो मेरे पास हैं अगर माननीय सदस्य चाहे तो पढ़कर सुना सकता हूं, वे टेक्स जोधपुर में नहीं है । अगर आप चाहते हैं कि ओक्ट्रोय नहीं लगाई जाय तो आप घाटा पूरा कर दीजिये हमें टेक्स लगाने से कोई मतलब नहीं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जब जोधपुर म्युनिसिपल बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर ने घोषणा की बाद में जोधपुर की जनता की ओर से सरकार के पास कई रिप्रेजेन्टेशन आये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—चुंगी कर की घोषणा के बाद चेम्बर ओफ कोमर्स का रिप्रेजेन्टेशन एडमिनिस्ट्रेटर के पास आया कलेक्टर और कमिश्नर के पास आया उसमें उन्होंने दो तीन दरों के लिये लिखा था कि इसमें संशोधन कर दिया जाय जैसे चान्दी आदि उस पर हमने कहा कि हम इसको रिवीजन करने को तैयार हैं अगर उसमें यह उसको हटाने का तय होगया तो उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया जायगा ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जब यह नोटिफाइ किया गया कि १५ मार्च से इस शिड्यूल के मुताबिक टेक्स वसूल किया जायगा तो उस अर्से के बीच में यानि १५ मार्च के पहले कोई रिप्रेजेन्टेशन सरकार के पास आये क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने निवेदन किया चेम्बर आफ कोमर्स का रिप्रेजेन्टेशन कलेक्टर और कमिश्नर के पास आये उसके अलावा एक्शन कमिटी का रिप्रेजेन्टेशन भी मेरे पास आया और वे मुख्य मंत्रीजी से भी मिले थे ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इन रिप्रेजेन्टेशन पर विचार करके जिस प्रकार जयपुर शिड्यूल को रिवाइज करने के लिये एक कमेटी नियुक्त की थी तो क्या वैसी कमिटी जोधपुर के लिये नियुक्त करने का प्रयत्न किया गया या नहीं ?

Page No 30

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जिस शर्त पर जयपुर में कमिटी नियुक्त की थी उस शर्त पर आज भी सरकार जोधपुर में कमेटी नियुक्त करने को तैयार है। लेकिन एक्शन कमेटी के सदस्य यह नहीं चाहते।

श्री हरिकृष्ण व्यास–जब हड़ताल शुरू नहीं हुई उससे पहले क्या सरकार ने इस प्रकार का प्रयत्न किया, बाद में रिप्रेजेन्टेशन का जिक्र आता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—प्रयत्न करने का सवाल ही पैदा नहीं होता क्यों कि आपत्ति किसी ने नहीं की।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ओक्ट्रोय लागू की तिथी निश्चत करने के बाद यानि १५ मार्च की तारीख जो चुंगी वसूल करने की नीयत की गई थी उससे पहले जोधपुर की जनता के प्रतिनिधियों ने, अलग अलग संस्थाओं ने इस सिलसिले में रिप्रेजेन्टेशन किये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जो रिप्रेजेन्टेशन्स आये उनका तो मैंने निवेदन कर दिया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इन रिप्रेजेन्टेशन्स के पहुँचने के बाद सरकार ने क्या कोई कमिटी नियुक्त करने के बारे में विचार किया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जिस प्रकार की शर्तें जयपुर के लिये थीं उनमें गवर्नमेन्ट के अफसर मौजूद थे और भी सदस्य थे। उसी प्रकार की शर्तें यहां पर भी मन्जूर हैं तो गवर्नमेन्ट को कमिटी नियुक्त करने में कोई आपत्ति नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया कि बांकी टेक्सशन के न होते हुए भी जोधपुर में ओक्ट्रोय इनसीडेन्स सात लाख तक जाता है क्या इसको न्याय पूर्ण कहा जाय ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता— यह अवश्य और जरूरी है कि टेक्सेशन लगने चाहियें अगर बजट के घाटे को पूरा करना हो। मैं यह मानता हूं कि अगर जनता की कमाई का पैसा अपने आराम के लिये कोई खर्च करता है तो वह अन्याय पूर्ण है किन्तु जब जनता का पैसा जनता के आराम के लिये खर्च किया जाने के लिये यह लगाया गया है तो इसको न्याय पूर्ण ही कहा जायगा। आप अपना घाटा पूरा कर लीजिये हमें किसी प्रकार का टेक्स लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह मेरा और आपका प्रश्न नहीं है सरकार और इस सदन का है, मैं फिर अपने प्रश्न को दोहराता हूं मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकें तो दें का अक्ट्रोय का जहां तक ताल्लुक है ओक्ट्रोय का इन्सीडेन्स जोधपुर में जो सात लाख का है क्या सरकार उसको न्याय पूर्ण मानती है, स्पेसिफिक उत्तर दें।

श्री अध्यक्ष--There cannot be any question on which opinion of the Government is invited.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I only want to know whether Government has given consideration to this aspect of the question. ?

श्री अध्यक्ष—No, on only information can be sought on the point as to what is the state of affairs, factual state.

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि पोनेदो लाख की आबादी वाले शहर से सात लाख की ओक्ट्रोय की वसूली ठीक है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--जोधपुर के अलावा भी दूसरे शहर ऐसे हैं जिन पर परकेपिटा चुंगी कर ज्यादा है।

श्री वेदपाल त्यागी—क्या सरकार यह चाहती है कि ओक्ट्रोय की दर बढ़ाने के बाद हाउस टेक्स नहीं लगायेगी और हाउस टेक्स चुंगी से वसूल कर लिया जायगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह तो प्रस्ताव बोर्ड में आगया यह गवर्नमेन्ट मन्जूर कर रही है ऐसी बात नहीं है। गवर्नमेन्ट ने तो बोर्ड के आदेश के मुताबिक किया। इलेक्टेड बोर्ड चाहे तो इसको रिवाइज कर दे। गवर्नमेन्ट से लोन के रूप में और कर्मचारियों की तनखा चुकाने के लिये पैसा न ले तो हमें कोई एतराज नहीं!

श्री भैंरूसिंह—क्या यह सही है कि जोधपुर में हाउस टेक्स इम्पोज नहीं किया जायगा ?

श्री अध्यक्ष—It is a different matter. No supplementry concerning, this.

The Hon'ble Minister might give long replies, causing implications but then it should relate to this main question.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—हाउस टेक्स नहीं ओक्ट्रोय ड्युटी शुरू की है।

श्री अध्यक्ष—It is not an affair of the Government, but of the Munioipal Board.

श्री भैंरूसिंह (१६)—क्या यह सही है कि सरकार को यह संभावना है कि चुनी हुई म्युनिसिपैलिटी इस प्रकार का टेक्स इम्पोज नहीं करेगी इसलिये उसके आने से पहले ही यह लागू कर दिया जाय ?

Page No 32

श्री हरिकृष्ण व्यास—Have the public of Jodhpur made representations to the Government against this duty ?

श्री अध्यक्ष—Order !

श्री हरिकृष्ण व्यास—Is the Government aware ?

श्री अध्यक्ष—It does not relate to the facts of the case.

श्री भैंरूसिंह—जब कि चार ही महीने बाकी हैं म्युसिसिपलिटी के इलेक्शन के, तो चार महीने पहले टेक्स का इम्पोज करना, क्या सरकार को डर है कि चुनी हुई नगरपालिका के आने पर यह टेक्स नहीं लग सकेगा इसलिये यह टेक्स अभी से चालू कर दिया जाय ?

(उत्तर प्राप्त नहीं होने पर)

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह हड़ताल जब से शुरू हुई अब तक चालू है या खत्म होगई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जहां तक मेरी इत्तला है हडताल चालू है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सरकार के ध्यान में है कि जोधपुर नगर की सभी संस्थाओं ने, चेम्बर ओफ कोमर्स ने और सब पार्टीज ने एक मत होकर यह राय जाहिर की है कि इस टेक्स पर पुनर्विचार किया जाय ?

श्री अध्यक्ष—Why not give a cut motion on L. S. G, Instead of making a debate on this question for twenty minutes. Then every thing would be clear. We can take it even now, provided the debate is cut-short.

श्री हरिकृष्ण व्यास—इनको मालूम है या नहीं, यह पूछ रहा हूं।

श्री भैरूं सिंह—सरकार के किस अधिकारी द्वारा यह जांच की गई कि जयपुर और जोधपुर की नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति खराब है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इसके आंकडे हर साल बजट में आते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या म्युनिसिपल रेवेन्यू और स्टेट रेवेन्यू के रिएलोकेशन के बारे में कोई जांच कराई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मथाई कमीशन की रिपोर्ट मौजूद है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि म्युनिसिपल रेवेन्यू और स्टेट रेवेन्यूज के संबन्ध में राजस्थान में लगातार मांग उठी है और म्युनिसिपल कमेटीज के सभापतियों ने उठाई है और माननीय मंत्री महोदय खुद जब कि एक म्युनिसिपेलिटी के चेयरमेन थे इस प्रकार की आवाज उठाई थी, आज तक उस पर विचार नहीं हुआ ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—यह जो आपका प्रश्न है इससे ताल्लुक नहीं रखता फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिये निवेदन कर दूं कि मथाई कमीशन की रिपोर्ट मौजूद है और बिल भी हाउस के सामने आ रहा है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार आज की स्थिति को देखते हुए और जनमत को देखते हुए इस पर फिर से विचार करने के लिये तैयार है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने निवेदन किया कि सरकार हर वक्त विचार करने को तैयार है आप लोग विचार करने को तैयार नहीं इसी से हड़ताल चल रही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जो डेपुटेशन संबन्धित मंत्री महोदय से और मुख्य मंत्री से मिलने आया उन्होंने इस बात की स्वीकृति दे दी थी, रिड्यूस्ड रेट्स से ओक्ट्रोय वसूली का हुक्म देदें तो आज ही हड़ताल बन्द हो सकती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह ठीक है कि डेपुटेशन आया था और उन्होंने यह कहा था कि जयपुर के रेट जोधपुर के लिये लागू कर दिये जायं। हमने उनसे कहा कि बिना कानूनी जांच कराये ऐसा नहीं किया जा सकता। जयपुर के रेट्स वहां लागू करना कानूनी जायज हैं या नहीं, यह बात देखने की थी। आप खुद भी थे उसमें, फिर भी आप इनफोरमेशन सीक कर रहे हैं यह ब्रेक डाउन आप ही की तरफ से हुआ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह तो जुदा जुदा राय का सवाल है, मेरा प्रश्न यह है कि इस संबन्ध में प्रस्ताव सरकार के सामने आया था या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम भी इसमें लिया गया इसलिये मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। वह डेपुटेशन मुझ से भी मिला, मुझसे मिलने पर मैंने उनसे निवेदन किया कि जो ओक्ट्रोय लागू की गई है उसका कम्पेरिजन केवल जयपुर जोधपुर में नहीं हो सकता। ओक्ट्रोय दूसरी जगह राजस्थान में भी लगे हुए हैं उनके कम्पेरिजन के साथ इसको सोचें। जयपुर में ओक्ट्रोय का इन्सीडेन्स कम होने का कारण और उस पर पुनर्विचार करने के लिये हम तैयार हैं यह बात रखी गई थी। पहले इस्ट्राक कॉल ओफ करली जाय उस बीच जो ओक्ट्रोय अभी लगी हुई है वह लागू रहेगा और जो निर्णय लागू किया जायगा उसको रिट्रोसपेक्टिव इफकेट दिया जायगा और जो कुछ आज ज्यादा दिया जा रहा है वह वापिस मिल जायगा।

Page No 34

श्री रावत शम्भुसिंह—क्या यह सही है कि किन्हीं मंत्री महोदय की तरफ से प्रतिनिधि मंडल को यह उत्तर दिया गया था। हम तो रेंट्स वगैरह के झगड़ों में पड़ना नहीं चाहते आप तो हमें लम्पसम उगाकर देदें।

श्री अध्यक्ष—Order please!

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस पर बहस के लिये समय रखा जाय।

जन-लेखा तथा प्राक्कलन समितियों १९५६–५७ के निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष—मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि दिनांक १९ मार्च, सन् १९५६ को किये गये चुनावों के फलस्वरूप जनलेखा सीमिति तथा प्राक्कलन समिति के लिये निम्न सदस्य निर्वाचित घोषित किये जाते हैं :—

जनलेखा समितिः

(१) श्री कुम्भाराम आर्य

(२) श्री दुर्लभसिंह

(३) श्री द्वारकादास पुरोहित

(४) श्री नाथूराम मिर्धा

(५) श्री भैरूंसिंह (१६)

(६) श्री मथुरादास माथुर

(७) श्री सज्जनसिंह

(८) श्री श्रीदास गोयल

(९) श्री हरिकृष्ण व्यास

(१०) श्री हिम्मतसिंह (६१)

प्राक्कलन समितिः

(१) श्री गुलाबचन्द कासलीवाल

(२) श्री जवानसिंह

(३) श्री तेजमल बापना

(४) श्री धर्मपाल

(५) श्री भीमसिंह

(६) श्री भैरूंसिंह (११)

(७) श्री भोपालसिंह (२०)

Page No 35

[श्री अध्यक्ष]

(८) श्री मंगलसिंह (६४)

(६) श्री मोतीलाल चौधरी

(१०) श्री रामकरण जोशी

(११) श्री रावत शम्भूसिंह

(१२) श्री लाल बहादुर

(१३) श्री वेदपाल त्यागी

(१४) श्री शिवदानसिंह

(१५) श्री हरिदेव जोशी

जनलेखा समिति का कार्यकाल दिनांक २५ मार्च, सन् १९५६ से तथा प्राक्कलन समिति का कार्यकाल दिनांक २६ मार्च, १९५६ से आरम्भ होगा और दोनों समितियों के जो चैयरमेन जो चले आ रहे हैं वे काम करेंगे।

(विराम)

Yes Demand No: 54, MajorHead 37-Education shri Hari Krishna vyas.

मांग संख्या ५४-शिक्षा

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय अध्यक्ष, मैं केवल यह निवेदन करना चाहता था कि कल एप्रोप्रियेशन बिल लिया जाने वाला है तो आज गिलोटिन एप्लाई होकर सारी डिमान्ड आज स्वीकार कर ली जावे और इन्ट्रोडक्शन ऑफ एप्रोप्रियेशन बिल आज ही हो जावे जिसमे टेकनिकल डिफिकल्टी फिर न रहे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कल एक-दो बजे एप्लाई कर देना साहब।

श्री अध्यक्ष—I have given assurance that the Appropriation Bill will not be discussed.........

श्री हरिकृष्ण व्यास—थोडासा करेंगे, घटे आध घंटे तक तो करेंगे साहब।

अध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग पर कल कटौती के प्रस्ताव का उल्लेख करते हुए मैंने चर्चा शुरु की थी और पांच बज जाने के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई इसलिये वह कार्य मैं अब शुरू कर रहा हूँ।

मैं कल जिक्र इस बात का कर रहा था अध्यक्ष महोदय, कि जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें विद्यार्थियों से ट्यूशन फीस के अलावा जो दुसरें रूप में फीसें ली जाती हैं उनका हिसाब-किताब

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

रखने की कोई व्यवस्था नहीं हैं और मैंने जयपुर के अन्दर इस राजस्थान के सबसे बड़े कालेज, महाराजा कॉलेज का उल्लेख किया था। मैं आपकी सूचना के लिये बताऊं कि महाराजा कॉलेज में आज कई वर्षों से यूनियन फीस के नाम से एक फीस ली जाती है और इतने वर्ष हो गये बड़े प्राचीन संस्था के बहुत बुजुर्ग प्रिन्सिपल महोदय के बहुत ही काबिल नेतृत्व में आज तक उस संस्था में यूनियन के विधान नाम की चीज भी तैयार नहीं हो पाई है। जो यूनियन फीस का पैसा लिया जाता है वह खर्च प्रिन्सिपल महोदय की आज्ञानुसार होता है। उसका हिसाब कोई प्रोफेसर, जिनको कह देते हैं, वह रखता है और विद्यार्थियों की यूनियन के नाम से जो फीस ली जाती है उसकी भी देखभाल का जिम्मा कोई बनी-बनाई संस्था के रूप में काम करने वाली यूनियन के हाथों में नहीं, बल्कि स्थिति तो यह है कि इस वर्ष जो कि अलग अलग क्लासों के प्रतिनिधि हैं उन्होंने मिलकर एक विधान बनाया था अपनी यूनियन का। सन् १९५६ के इस युग में जब कि कांग्रेसवाद से निकल कर समाजवाद की चर्चा शुरु हो गई है उस ढांचे के जोरदार घोटाले में राजस्थान की राजधानी जयपुर में और राजस्थान की प्रीमियर शिक्षण संस्था महाराजा कॉलेज में इस कारण कि उन्होंने यूनियन का कोई विधान क्यों बना लिया, विद्यार्थियों को चार्ज शीट दिया जा रहा है कि तुमने अपनी यूनियन का विधान क्यों बनाया? तुम विधान बनाने वाले कोन हो? तुम विधान के बारे में बातचीत करने वाले कौन हो? यह स्थिति आज है।

मैं इस पर इस विषय की तफसील में न जाकर इतना ही उल्लेख करूंगा की यूनियन के पैसे के नाम पर दी हुई फीस जिसका खरचा करने के लिये यूनियन मोजूद नहीं, उसका विधान नहीं और यूनियन के नाम पर सारे का सारा पैसा कानूनी अथवा गैर कानूनी तरीके से खर्च करने का अधिकार का प्रयोग उस संस्था के अधिकारीवर्ग, प्रिन्सिपल या दूसरे प्रोफेसर किया करते हैं। यह नमूना है शिक्षण संस्थाओं का और दूसरी ओर नमूना है कि इस फीस के बारे में कितनी खबरदारी बरती जाती है।

बीकानेर की एक बात अर्ज करूं जो कि मेरा खयाल है सीमाओं से भी पार चली गई है। बीकानेर की गर्ल्स स्कूल में जो बस फीस ली जाती हैं स्टूडेन्टस से वह सारा का सारा पैसा वसूल होकर उस संस्था के प्रिन्सिपल महोदया के पास पहुंचा दिया जाता था।

और वर्षानुवर्ष वह इसी प्रकार से चलता रहा। पूरे तीन साल हो गये, अध्यक्ष महोदय, लेकिन उस स्कूल का आज तक किसी ने हिसाब का आडिट नहीं किया, और आडिट करने वाले लोग जब जाते थे तो शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारी तक इस बात के लिये संस्था के प्रन्सीपल महोदया या हैड मिस्ट्रेस महोदया को मदद करते थे कि उस स्कूल के हिसाब का आडिट न हो। और अभी अभी जब कि आडिट हुआ तो मालूम हुआ कि चार हजार रुपये जो कि विद्यार्थियों से बस के चार्जेज के रूप में लिए गये थे उनका पता नहीं। उनका हिसाब कोई दर्ज नही है, उनके विभाग के रेकार्ड के अन्दर कोई उल्लेख नहीं है। वह मामला अब भी विचाराधीन चल रहा है,

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

और मैंने सुना है कि इस सम्बन्ध में उस संस्था को अधिकारी महोदय ने एक पत्र ऐसा लिखा है यह कहते हुये कि रुपया वापिस मेरे से ले लीजिये। मैं देने को तैयार हूँ और केवल इस बिनाह पर उस मामले को भी अब ठंडा मोटा करके वैसे ही रखने की कोशिश की जा रही हैं, क्योंकि उसमें परोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपका प्रोत्साहन देने का हाथ था। यह तो कुछ चन्द मिसालें हैं और यदि इन पर जांच की जाय अथवा इस पर गौर किया जाय तो ऐसी राजस्थान के कौन २ सी बीसों मिसालें और उपलब्ध हो सकती हैं कि जिनमें विद्यार्थियों के वसूल किए हुए पैसों को ठीक तौर से खर्च करने की न व्यवस्था है और न ही हिसाब की किसी प्रकार से जांच पड़ताल आज की जाती है।

मेरा दूसरा कटोती का प्रस्ताव, अध्यक्ष महोदय, जो हैं उसका संबन्ध है उन शिक्षण संस्थाओं से जिनको कि सरकारी सहायता प्रदान की जाती है, इस प्रश्न पर कुछ वादविवाद इस सदन में हो चुका है सप्लीमेंट्री डिमान्डस के सिल सिले में, और मेरी यह कोई इच्छा नहीं है कि वाद विवाद को फिर से दोहराने का प्रयत्न किया जाय, लेकिन उस दिन जो वाद विवाद हुआ उसको आगे बढ़ा कर उसके कन्टीनुएशन के तौर पर अर्ज करूंगा कि जिन शिक्षण संस्थाओं को सहायता दी जाती है उनके हिसाब किताब के जांच की आज तक कोई समुचित व्यवस्था न हुई है और न की गई है। इतना ही नहीं लेकिन वहां जो काम करने वाले मुलाजिम हैं वहां जो टीचर्स हैं, वहां जो लेक्चरर्स हैं, तथा वहां दूसरे मुलाजिम हैं उनके लिये मैं तो यहां तक कहूँगा कि उनके नाम पर तनख्वाहों के रूप में जितनी रकम हिसाब के अन्दर आती हैं बहुत उन्हें उससे कहीं कम तनख्वाह मिलती है। यू० पी. सरकार ने ऐसी गम्भीर स्थिति को देखते हुए कुछ कदम उठाया। उन्होंने देखा कि जिन २ संस्थाओं को सरकारी मद से सहायता मिलती थी वह अमूनन कम खर्च करते हैं। कहीं पर देखा कि अमुक व्यक्ति को १००रु तनख्वाह दी जाती है और १००रु की रसीद लेली जाती है लेकिन असल में उनको ६० रु पकड़ा दिये जाते हैं। तो यू. पी. सरकार ने इस पर यह कदम उठाया कि एक कानून बना दिया कि उन शिक्षण संस्थाओं को जिनको कि सरकारी सहायता मिलती है उनको अपने मुलाजिमों को तनख्वाह देने का तरीका बदलना पड़ेगा। वह तरीका उन्होंने इस प्रकार बदला कि ट्रेजरी के जरिए उनको पेमेंट मिला करेगा। और इस छोटे से परिवर्तन के कारण मेरी ऐसी मान्यता है कि वहां काम करने वाले मुलाजिमों की हालत में बहुत कुछ सुधार हुआ। एक तो उन संस्थाओं के उच्चाधिकारियों के पास जाकर जिनके हाथ में कि सारी की सारी गड़बड़ियां होती हैं और उन्हें ऊंची नीची रसीद लिखाने की नौबत आये और दूसरी ओर किसी २ व्यक्ति के नाम पर या बैंक के नाम पर ये आर्डर उसको मिला हुआ है तो उसको पे बराबर मिल जाय और उस पे से वापिस रुपया वसूल करने की कोशिश हो इसमें काफी फर्क हो जाता है। यहां न सिर्फ जांच ही की जा रही है बल्कि पिछले सेशन में इस सदन में इस आशय का सुझाव मैंने दिया था, अध्यक्ष महोदय, और तब यह कहा गया था कि उस पर विचार किया जायगा। एक साल हो गया विचार करते २ एक वर्ष का अरसा गुजरने के बाद भी आज भी यह हालत है इन शिक्षण संस्थाओं में काम करने वाले लोगों, कि उनके स्वार्थों की रक्षा के लिए, उनके हितों के लिए इस प्रकार के कदम

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

उंठाने की ओर सरकार अग्रसर नजर नहीं आती है। मैं नहीं सारी दुनियां जानती है कि इन संस्थाओं के जिनको कि सरकारी एड दी जाती है हिसाब किताब की क्या हालत है ? क्योंकि इस प्रश्न पर कुछ वाद विवाद पहले हो चुका है इसलिये सदन का और समय नहीं लेते हुये मैं उस दूसरे अपने कटौती के प्रस्ताव के बारे में जो कुछ बातें करना थी उन्हें यहां प्रस्तुत किया, ऐसा मानकर आगे बढ़ता हूँ।

मेरा दूसरा प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीयकरण का। पुस्तकों के छपवाने और उनके वितरण में जो गड़बड़ियां हुई हैं उसके बारे में। वैसे तो अधूरे रूप में या अधकचरे रूप में समझिये यह प्रश्न इस सदन के सामने काफी अरसे से चल रहा है। मुझे याद है कि एक प्रश्न मैंने इस सिलसिले में मार्च १९५४ के बजट अधिवेशन के समय पूछा था और उसका उत्तर मिला था ऐसा मुझे याद है। उसमें यह कहा गया था कि इसकी जांच की जा रही है और जल्दी ही जांच पूरी हो जायगी। इसी आशा से मैं बैठा था कि अब जांच पूरी होगी, अब निर्णय होगा, लेकिन १९५५ और १९५६ के मार्च का महीना तो आगया लेकिन अभी तक तो इस संबंध जांच पूरी होने की सूचना नहीं मिली है। और कोई ऐसी वैसी बात होती तो शायद बार बार उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन बात बहुत गम्भीर है और गहन है, अध्यक्ष महोदय, और वह यह है कि जब राजस्थान सरकार ने पाठय पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय किया उस समय कुछ पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण करके सरकार द्वारा निकालने का अथवा छपवाने का निर्णय सरकार ने किया पहले का निर्णय ८ पुस्तकों के संबंध में था। बाद में कुछ पब्लिशर्स की पुस्तकें और रिजेक्ट हो जाने के कारण उनमें ६ और जोड़ी गई और इस प्रकार से १४ पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, पुस्तकों के रूप में सरकार द्वारा यह प्रकाशित की जायगी १४ पुस्तको में से, अध्यक्ष महोदय, ६ पुस्तकें को राजस्थान के राजकीय मुद्रणालय में छापी गई, गवर्नमेंट प्रेस में छापी गई, और ८ पुस्तकें दूसरे किसी प्रेस में छपवाने के लिए सरकार ने निर्णय किया।

अब इन ८ पुस्तकों का हाल शुरू होता है। टेन्डर मांगे जाते हैं और १० दिन के या ८ दिन के अन्दर अन्दर टेन्डर का उत्तर मांगा जाता है। लेकिन इतनी कम अवधि होने के बावजूद भी कई कई जगहों से टेन्डर आये। जयपुर से भी आये, आगरे से भी आये और दिल्ली से भी आये। और जब उन टेन्डरों को खोला गया तो यह मालूम हुआ कि दिल्ली की एक कम्पनी, कपूर ब्रदर्स थी उनका टेन्डर सबसे कम गिना जाय ऐसी स्थिति सामने नजर आई। पौने सात पाई पर फार्म हर प्रकार की पुस्तकों के लिए उनकी रेट थी। उन्होंने जो लिखा था कि यह रेट हमारी तब लागू होगी कि यदि प्रत्येक पुस्तक की ५ हजार से अधिक प्रतियां छपवाई जायं, लेकिन राजस्थान सरकार के काम करने का तरीका अपना एक मौलिक तरीका है और राजस्थान सरकार के अधिकारियों ने जब दुर्बीन लगाई इन कागजों के ऊपर तो यह पौने सात पाई पर फार्म की जो रेट है वह रेट न मालूम उन्हें दृष्टि गोचर हुई या नहीं या ओझल हो गई वह रेट आंखों के सामने से और एक राजस्थान प्रिंटिंग प्रेस है जयपुर में, जिसके बारे में मेरी जानकारी यह है

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

कि वह कम से कम डा० जेकिल और मि० हाइड के रूप में कभी राजस्थान प्रिन्टिंग प्रेस और कभी नवयुग प्रिन्टिंग प्रेस के रूप में सामने आता है। तो वह राजस्थान प्रिन्टिंग वर्क्स नाम का प्रेस है। उसने ७।। पाई, ८।। पाई, ८।।। पाई और १० पाई पर फार्म की अलग अलग पुस्तकों की रेट्स दीं तो सरकार ने टेन्डर खोलने के बाद उनको बुलाया, उनसे नेगोशियेशन्स किये, उनसे कहा देखो भाई ये रेट्स ज्यादा है कम करना ज्यादा अच्छा रहेगा और अचानक हुक्म निकला कि प्रत्येक पुस्तक का प्रबन्ध करो, आर्डर निकला १० हजार, १५ हजार, २० हजार और २५ हजार और अगर १० हजार, १५ हजार, २० हजार और २५ हजार का प्रन्टिंग आर्डर था तो एक कपूर प्रेस का ६।।। पाई था और दूसरे और राजस्थान प्रिन्टिंग प्रेस, बड़ी भारी रेट्स सामान्य पुस्तक के लिए ८।।। पाई, ७।। पाई साइन्स की पुस्तक के लिए और ८।। पाई ड्राइंग की पुस्तक के लिए और इस रेट पर गवर्नमेंट का आर्डर दे दिया। पहला प्रश्न तो यह उठता है कि व्यक्ति विशेष की बात को जाने दीजिये, क और ख की बात को जाने दीजिये, इसको अलग भी रख लें जो लोएस्ट टेन्डर था उसको भी मंजूर नहीं किया और राजस्थान प्रिन्टिंग वर्क्स का टेन्डर था उसको अलग रख दिया और तीसरी पाली वाली पंचायत का फार्मुला निकाल लिया और वह भी ७।। पाई होजाय तो उससे ज्यादा उसको ७।। पाई के बजाय ८।। पाई का आर्डर प्लेस कर दिया गया है। आर्डर प्लेस किया गया है और माननीय मित्र सोचते होंगे कि इररेगुलेरिटी हो गई होगी, हो जाती है कभी कभी किन्तु यह तो इररेगुलेरिटी एक नहीं है यहां तो इररेगुलेरिटी का कोम्बिनेशन होता है जहां तक राजस्थान प्रिन्टिंग वर्क्स का सवाल हैं, इररेगुलरेटी समुह के रूप में सामने आती है। आर्डर प्लेस करने में, टेन्डर इन्वाइट करने में और प्रिंटिंग पूरा हुआ और बिल पास हुआ तो ड्राइंग की पुस्तक की ८।। पाई से सरकार ने छपाई मंजूर की और मंजूरी थी उसके बावजूद भी उसको ६५० रुपये और जोड़ दिये, हरे पीले नीले ब्लाक बनाये इसलिए ज्यादा खर्चा हो गया। इसको मैं दोष नहीं देता हूं अध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रिन्टिंग वर्क्स है उसका तो धन्धा ही है, पुस्तकें ही नहीं और भी हो, सरकार से ज्यादा पैसा वसूल करना यह उन्होंने काम बना रखा है। लेकिन सरकार को ध्यान देना आवश्यक है। अगर एक इररेगुलेरिटी हो तो दूसरी बात है लेकिन बहुत हैं। रेट्स ज्यादा थीं और फिर प्रिन्टिंग का बिल पास करते वक्त ६५० और दे देना। इसमें गवर्नमेंट की मंजूरी नहीं ली गई और डेढ़ साल से यह मामला जांच पड़ताल में लटक रहा है। मैं नहीं समझ सका कि इसमें कौनसी बड़ी जांच पड़ताल की जा रही है इस सम्बन्ध में फाइल है, कागज है, टेन्डर है, बिल है, और बगैर सरकार मंजूरी के जो ओवर पेमेंट किया गया ड्राइंग की पुस्तक के सम्बन्ध में, वह ओवर ड्राइंग वापिस वसूल करके सरकार के हाथ किसने बांध रखे हैं लेकिन यह हुआ नहीं। किताबें छप गई यह तो छपाई का कांड है जिसका मैंने जिक्र किया। यह बाबूजी की (अश्रव्य) का अध्याय है। खत्म नहीं होता है। किताबें छपवायीं और अब वितरण का क्या तरीका है ?

मैं संक्षेप में कह दूं, उस वितरण के सिलसिले में यह स्थिति है कि जब वितरण के ठेके की नोबत आयी तो पहले डा० जेकिल और मि० हाइड थे और अब बन गये हैं एलीयन पीपरमेन।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

इट इज़ ए लिटरेरी करेक्टर। यह एलियन पीपरमेन का दिल्ली से जयपुर में प्रकाश एन्ड कंपनी के नाम से प्रादुर्भाव हुआ और बाकी का ठेका भी उनके हाथ पहुंच गया। दो और कंपनियां हैं, राजस्थान पुस्तक मंदिर, राजस्थान प्रिन्टिंग प्रेस, फरमाबरदार नवयुग प्रेस, किताबों के डिस्ट्रिब्यूटर्स हुए प्रकाश एन्ड कम्पनी और मेरा ऐसा ख्याल है कि औथर्स का नाम आयगा तो दो चार और रजिस्टर होने वाले हैं, ऐसी मेरे पास सूचना है। तो इस प्रकाश एन्ड कंपनी को ठेका मिला और मिला इसलिए कि एक दो परसेन्ट कमीशन की बात थी। लेकिन इसमें एक दो की बात नहीं रही अध्यक्ष महोदय, प्रिन्टिंग वर्क्स को ६॥। पाई के बजाय ७॥ कर दी थी और वही किताब बाजार में बिकी थी जिसकी रेट थी १६ पाई क्योंकि उसमें सरकार की रोयल्टी का पैसा था, सरकार को मुनाफा हुआ था २० हजार का वह भी तो इसी में से था, फिर बाकी आता कहां से। इस प्रिन्टिंग वर्क्स और डिस्ट्रिब्यूटर्स के एक हो जाने का नतीजा क्या हुआ, नतीजा यह हुआ कि सवा, डेढ़ रुपये का खर्चा और करना पड़ा आर. पी कुम्भारे के नाम की एक रबर स्टाम्प की सील और बनानी पड़ी और सील लग कर वे किताबें प्रेस से बाजार में पहुँचने लगीं। सरकार को तो ६॥। पाई मिली और बाजार में बिकी वह १६ पाई में। माननीय मुख्य मंत्री जांच करायें कि दस पन्द्रह हजार पुस्तकों का ऑर्डर था, गवर्नमेंट प्रेस में किताबें कब और कितनी बिकी, दूसरी कंपनियों ने काफी बेची लेकिन राजस्थान प्रिन्टिंग वर्क्स की किताबें जो सन् १९५२ में उस कक्षा के स्टुडेन्ट्स की संख्या से १॥ हजार, २ हजार, २॥ हजार कम बिकी। वह किताब विभाग में नहीं पहुँची और बाजार में पहुँची, ६॥। पाई सरकार को थी लेकिन उसको बाजार में १६ पाई पर बेचा गया और इस तरह से डा० जेकेल एन्ड मिस्टर हाइड से एलीयन पीपरमेन बन गये। इन्होंने ७ पाई के बजाय १६ पाई वसूल कर ली और उसके लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। एक साल बीत जाने के बाद पिछले वर्ष फर्वरी में फिर टेन्डर नोटिस निकाला वितरण के सिलसिले में किसी और दूसरे को मुकर्रर करना था, टेन्डर नोटिस निकला और टेन्डर नोटिस आज निकला ख्याल कर लीजिये १६ तारीख को निकाला और १८ तारीख को बुला कर कहा जाता है प्रकाश एन्डकम्पनी और राजस्थान प्रिन्टिंग वर्क्स को कि आपने पहले जिम्मा लिया इसलिए इसको नहीं छोड़े। सोना में सुगन्ध, नेकी और पूछ पूछ। सात पाई से १६ पाई लेने का मौका मिलता रहा लेकिन आज तक जांच नहीं हुई।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष पदासीन)

एक और कांड हुआ है उसकी तफसील में मैं नहीं जाऊंगा। उसका उल्लेख इतना ही कर दूंगा कि पहले वर्ष में किताब खरीदी गई जिसका २६ परसेन्ट सरकार का कमीशन मंजूर हुआ और किसी टाइपिस्ट ने २६ का २५ कर दिया और नवयुग प्रेस के श्रीमानजी को राजस्थान पुस्तक मंदिर के नाम से आर्डर मिला और राजस्थान पुस्तक मंदिर को २६ हजार का आर्डर मिला वह २५ परसेन्ट पर और पेमेन्ट हुआ २२॥, व १२॥ और ७॥ रु० के हिसाब से। किसी की सेंकशन नहीं किसी की ऑथोरिटी नहीं। कहा यह गया कि समय की कमी थी लेकिन १७ मार्च सन् ५४ का सरकार का ऑर्डर है और २५ मार्च को भेजने की शर्त है और उन्होंने २६, २७ तारीख को डिलीवरी दी। गवर्नमेन्ट के आर्डर उल्लंघन किया और पैसे दिये उसकी रिकवरी का पता नहीं। या तो पूरा

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

यकीन करके घोषणा करें कि इस में गड़बड़ नहीं हुई है या नवयुग प्रेस को ओवर पेमेन्ट हुआ है। उसकी वसूली का नोटिस दें और इसके लिये कार्यवाही करें। आप इसकी जांच करलें, विभागीय कागजों से पूरी तसल्ली करलें और मेरी बात सही निकले तो कार्यवाही करें। मैं और तफसील में न जाकर एक चीज का जिक्र करूंगा क्यों कि शिक्षा विभाग का प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण चीज से ताल्लुक है। जो परंपरा पड़ी है उसका छोटा सा नमूना अभी तक मेरे सामने आया। जब चारों ओर यह हाल था कि जयपुर के डिप्टी डाइरेक्टर की तरफ से फरवरी ५६ में एक सर्कूलर निकला कि भारत सरकार के जितने भी प्रकाशन हैं उनको १० परसेन्ट कमीशन पर जयअम्बे प्रेस से मंगा लिया जाय रंगा भाई की प्रेस डाइरेक्टर ओफ पब्लिकेशन से उसी समय सर्कूलर निकलता है कि सवा ३३ परसेन्ट से हमसे मंगाइये। होम सेक्रेटरी की तरफ से यह निकलता है। इसी सरकार के दो अंग, भारत सरकार देने वाली, शिक्षा विभाग का १० परसेन्ट का ओर्डर अभी कायम है और अब भी स्कूलों से कहा जाता है कि तुम इन से लो। क्या उनकी मोहर लगी है या छाप लगी है कि डाइरेक्टर ओफ पब्लिक रिलेसन्स के सर्कूलर के बाद भी क्या उनको पूछा गया कि आप को यह स्वप्न कैसे आया, ३३ परसेन्ट के बजाय १० परसेन्ट का हिसाब कहां से लगाया इसका जवाब दीजिये। कम से कम यह तो कहें कि इस सर्कूलर को तो रद्द करो। पर वह आज तक जारी है। दूसरा या तीसरा सर्कूलर और निकालदें लेकिन जो निकल गया है वह कैंसिल नही होगा। ऐऐ ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हैं लेकिन समय की कमी के कारण क्या कहूं?

श्री उपाध्यक्ष—संक्षेप में कहिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस विषय में मेरे तीन कट मोशन्स खत्म हो गये। कंटिन्युएशन में चल रहा हूँ। अभीएक बचा है, टेक्स्ट बुक के संबंध में, आप आज्ञा दें तो कुछ कहूं। लेटर का मामला चल रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—समय हो गया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—रिप्लाई में उल्लेख कर दूंगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—रिप्लाई में कैसे करेंगे?

श्री हरिकृष्ण व्यास—टेक्स्ट बुक्स सिलेक्शन के मामले में अमुक अमुक लोगों के पास जा सकते हैं। आज नेशनेलाइजेशन के नाम से बोर्ड बना है कि लेखक लोग अर्जी देकर अपने नाम का रजिस्ट्रेशन करा लें। लेखक तो राजस्थान में बहुत होंगे। चिट्ठी लिखने वाले भी लेखक हैं, संपादक के नाम चिट्ठी लिखने वाले भी लेखक हैं। तो लाखों लेखकों का रजिस्ट्रेशन हो सकता है, मुख्य मंत्रीजी को जानकारी अच्छी तरह से है इसलिये उत्तर दे देंगे।

अन्त में सबसे गम्भीर बात मैंने रिजर्व करके रखी थी और उसका संबन्ध राजस्थान के लाखों लोगों के जीवन से है। मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि स्कूलों में फीस बढ़ाने से आमदनी होती है.

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

इसके सम्बन्ध में आंकड़े देखे तो पता चला कि पिछले वर्ष सेकेन्ड्री स्कूलों में फीस से ४।(सवाचार) लाख रुपयों की आमदनी हुई। उसमें कुछ कमी हो जायगी क्योंकि सरकार ने हाल ही में २५०)रु० माहवार से कम तनख्वाह पानेवाले सरकारी कर्मचारियों के लड़के-लड़कियों की फीस माफ कर दी है तो सवा चार लाख के बजाय चार लाख या पौने चार लाख रु०की आमदनी उस हिसाब से रह जायगी, अलबत्ता कम जरूर होगी। लेकिन इस वक्त सरकार उम्मीद लगा रही है कि इस साल आमदनी होगी सेकन्डरी स्कूलों से १२। (सवा बारह लाख) लाख रुपयों की। अब वे कितनी फीस बढ़ाने वाले हैं? इससे गार्जियन्स का क्या हाल होगा? वे गार्जियन्स जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनका क्या हाल होगा? नतीजा यह होगा कि ३ रु० फी विद्यार्थी सेकन्डरी और प्राइमरी एजुकेशन पर फीस पड़ जायगी। भोपाल रियासत में १४ साल तक के बच्चों के लिये फ्री एण्ड कम्पलसरी एज्युकेशन है। और ४—५ वर्षों की बात राजस्थान के वित्त मंत्रीजी कह रहे थे ५० हजार पहले होता था। पिछले साल ३ हजार का है रिवाइज़्ड एस्टीमेट्स में ३ लाख ५६ हजार का अन्दाजा लगाया था। अब अ.आ. पढ़ने वाले और ५० रु० माहवार पानेवाले गार्जियन्स पर रु० दो रु० का बोझ और लादेंगे इसलिये कि इससे हमारे यहां शिक्षा की उन्नति हो रही है। दूसरे राज्यों के मुकाबले में, कालेजों को छोड़िये, प्राइमरी और मिडिल स्कूलों को देखें तो राजस्थान में, मुख्य मंत्रीजी और शिक्षा मंत्रीजी जो एक ही हैं, आंकड़े प्रस्तुत करें सदन में, प्राइमरी और मिडिल स्कूलों तक आज जो फीस लगाने का इरादा है, उनसे कई गुना यहां ज्यादा है। भोपाल का मैंने उदाहरण दिया, मध्यप्रदेश के आंकड़े मेरे पास मौजूद हैं लेकिन हमारे यहां ३ लाख ५६ हजार का अनुमान लगाया गया। सारी दुनियां के मुकाबले में कहीं ज्यादा। वित्त मंत्रीजी ने यह तो कहा होगा कि राजस्थान के लोगों को पर केपिटा इन्कम कितनी है। यू. पी. में अभी सम्पूर्णनंदजी ने आंकड़े प्रस्तुत किये थे, राजस्थान में भी आंकड़ा मौजूद होगा, भारत सरकार के पास भी मौजूद है। पर केपिटा इन्कम के लिहाज से राजस्थान का नम्बर नीचे से तीसरा चौथा आयगा, इससे अधिक नहीं आयगा। बड़े बड़े राज्यों के मुकाबले में बम्बई, यू. पी., मद्रास आदि के मुकाबले में राजस्थान का कहीं नम्बर नहीं आने वाला है, इतना ही नहीं, बल्कि बात हम करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण की। पर यह दृष्टिकोण कम से कम शिक्षा विभाग में तो लावें। एक ओर तो यह कह रहे हैं और दूसरी ओर दूसरे राज्यों का मुकाबला करने वाले हैं। यह भूल गये कि सन् ५१ में राजस्थान ने फाइनेन्स विभाग को मेमोरेन्डम दिया था उसमें कहा था कि आज राजस्थान सरकार की आमदनी होती है उसमें से टेक्सेशन की आमदनी दूसरे राज्यों के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। बम्बई राज्य में टेक्सेशन की आमदनी ७१ परसेन्ट थी और राजस्थान में ७२ परसेंट थी। राजस्थान सारे हिन्दुस्तान में पहला राज्य था जिसकी आमदनी का ७२ परसेंट भाग टेक्सेशन से आता है। जहां पर टेक्सेशन का बोझ पहले से ही इतना ज्यादा हो और पर केपिटा आमदनी के लिहाज से दूसरे राज्यों से बहुत पिछड़ा हुआ हो उस क्षेत्र में और फीस लगाना कहां तक उचित है? पिछड़े हुए क्षेत्र में सुविधाएं नहीं मिलतीं तो यह नहीं कि सुविधाएं बढ़ाई जांय। किंतु राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी को गरीब लोगों की फटी जेब दिखती है। मामूली आदमी की जेब में अन्नी दुअन्नी या रुपिया दो रुपिया किसी तरह से बचा कर रखने की नौबत आ जाय तो उसको लूटने की कोशिश की जाती है। यदि किसी गरीब आदमी के चार बच्चे पढ़ रहे हों और

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

किसी को मिडिल और किसी की मेट्रिक करना हो तो वह कैसे करा सकेगा जबकि आपने तीन गुना, चार गुना छः गुना या दस गुना फीस बढाई हो और प्राइमरी में तो १२ गुना फीस बढ़ाकर आप आमदनी करना चाहते हैं तो यह दकियानुसी-नीति, प्रतिक्रियावादी नीति राजस्थान के लोगों के ऊपर लगा कर के खिलवाड़ करना चाहते हैं। यह उनको मारने वाली नीति है। इस नीति को सदन में किसी को मंजूर नहीं करना चाहिए। इसकी सूचना देने के लिये, सदन को जानकारी देने के लिये मैंने यह कटोती का प्रस्ताव रखा है।

श्री चांदमल मेहता—माननीय उपाध्यक्ष, शिक्षा की मांग पर मेरे ६ कटोती के प्रस्ताव हैं और इन ६ प्रस्तावों में से दो प्रस्ताव पाठ्यपुस्तकों से संबन्धित हैं। पहले मैं पाठ्य पुस्तकों के संबन्ध में कहना चाहता हूं। उपाध्यक्ष, राजस्थान शिक्षा की दृष्टि से दूसरे प्रान्तों के मुकाबले में काफी पिछड़ा हुआ है और इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिये हमारी सरकार प्रयत्नशील हैं लेकिन जिस प्रकार जहां कहीं स्कूलें खोल कर सरकार शिक्षा में तरक्की करने की कोशिश करती है उसी तरह से पाठ्य पुस्तकों का चुनाव करने में बहुत पिछडी हुई है। और मैं तो यह कहूंगा कि इस प्रकार की पाठ्य पुस्तकों को रख कर दो कदम शिक्षा के विकास में पीछे हटती जा रही है। मुझे पाठ्य पुस्तकों को देखने का मौका मिला है और उन्हें देख कर मैं उस नतीजे पर पहुँचा हूं कि वे पाठ्य पुस्तकें वास्तव में उन लेखकों की लिखी हुई हैं या नहीं जिनके नाम उन पर दिये गये हैं क्योंकि जब हम उनके नाम देखते हैं तो काफी योग्य आदमी के नाम मालूम होते हैं मगर जब हम पुस्तक को देखते हैं तो मालूम होता है कि उनको लिखने वाला कोई नया व्यक्ति है जो शिक्षित नहीं है, उतना ही नहीं पुस्तकों को देखने से ऐसा दिमाग में आता है कि छानबीन करने वालों में भी ऐसे आदमी हैं जो इसकी परवाह नहीं करते या जानबूझ कर ऐसी किताबों को प्रोत्साहन देते हैं मैं खास करके एक पुस्तक की चर्चा करूंगा। अगर मैं इसका जिक्र नहीं करूंगा तो माननीय शिक्षा मंत्री यह कहेंगे कि महेज आलोचना करने की नियत से ऐसा किया गया है और आलोचना करने की आदत है। यदि मैं खास तौर से इसकी विशेष चर्चा नही करूं तो यहीं जबाब मिलता है।

पुस्तक का नाम है (प्रारंभिक वाणिज्य ज्ञान) जो ६ वीं क्लास के लिये लिखी गई है। जिनके लेखक है बी. डी. भार्गव, एम. ए., बी. कोम, एफ. आर. ई. एस. (लंदन) और बी. एन. खन्डेलवाल एम. ए., एम. कॉम। यह उनके लेखक हैं। उनके नाम देखने से निश्चित होता है कि शायद यह जिन नामों से प्रकाशित हुई है उनके नामों को देख कर ही यह किताब पास की गई है। अगर आप इस पुस्तक के किसी भी पेज को देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि इस पुस्तक में कितनी गल्तियें हैं। आप पहले पेज से लगाकर १०६ पेज को देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि ८० प्रतिशत पेज इस पुस्तक के आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें भाषा संबन्धी, लेखन और व्याकरण संबन्धी अशुद्धियें हैं। ये तो आपको ८० प्रतिशत मिलेंगी। एसी तो बहुत सारी बातें है लेकिन इस पुस्तक में जिनके द्वारा वाणिज्य ज्ञान सिखाया जाता है, छोटे छोटे लडकों को, जरा आप उसकी तरफ ध्यान दें। आप जरा उनके पेज ६ पर देख लें जहां मिश्रष्गुणा भाग का तरीका दिया हुआ है

[श्री चांदमल मेहता]

और जहां २१ रु. १० आ. को ५ रु० १३ आ० से गुणा करने की बात बताई गई हैं। सब से पहले २१ रुपये को ५ से गुणा करेंगे फिर १० आने को ५ से गुणा करेंगे। गुणा करने पर हर एक पावली में ४ का भाग लगेगा। इसी प्रकार १३ आने को २१ से गुणा करेंगे और फिर १० आने को १३ आने से गुणा करेंगे। १० और १३ को गुणा करने से जो फल निकलता है वह पुस्तक में ८ रुपये २ आने लिखा है। वास्तव में वहां पर ८ आने और १।। पाई होना चाहिये। जहां आठ आने और डेढ पाई होता है वहां पर वाणिज्य ज्ञान में ८ रुपये और दो आने बताया है। तो वास्तव में वाणिज्य ज्ञान को सीखनेवाले किस तरह से फायदा उटा सकते हैं, इस पुस्तक में सारी जगह ऐसी भयंकर भूलें हैं।

आगे चला जावे। जहां दूसरे अध्याय में तोल के संबंध में तोला, माशा और रत्ती का जिक्र किया गया हैं वहां पर दो तोले १।। माशे. १।। रत्ती, १ चावल के सवाल का हिसाब बताया गया है और यह बताया जाता है कि तोले को भाव से गुणा करो तो तोले का मूल्य निकल आवेगा, आगे माशे के लिये क्या कहते है। कहते हैं दर से और माशे से गुणा करने पर उत्तर आता है मगर यह कुछ पता नहीं कि यह उत्तर कैसे आएगा। सिर्फ लिखते हैं दरों से और माशे से गुणा करने से उत्तर आ जाता है।

अगर मैं सारी बातों की चर्चा करूं तो मैं दूसरी बातों से महरुम रह जाऊंगा जो मुझे कहनी जरूरी है। माननीय उपाध्यक्ष, यह पुस्तक १९५४, ५५ में छपी है और अभी चालू है। जहां राजस्थान में इस तरह की पुस्तक चालू हो उससे क्या शिक्षा का विकास होगा ? मेरे खयाल में यह पुस्तक ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखी गई है जिसकी कहीं न कहीं पहुंच है और उस पर ऐसे व्यक्ति का नाम दे दिया गया है जिसके जरिये यह मालूम हो सके कि यह लेखक बहुत योग्य व्यक्ति है। मगर यह पुस्तक उस लेखक की, जिसका कि नाम इस पुस्तक पर लिखा गया है, नहीं है क्योंकि यह लेखक इस तरह का पढ़ा-लिखा है कि इस प्रकार से कभी भी नहीं लिख सकता से जिस तरह से कि लिखा गया है। इसलिए मैं माननीय उप-मंत्राणी से व शिक्षा विभाग के मंत्री से निवेदन करूंगा कि पुस्तकों के सिलेक्शन के संबंध में योग्य आदमी रखें जावें और अगर योग्य आदमी आपके पास नहीं हों तो बुलाये जावें और अगर योग्य आदमियों के होते हुए भी वे किसी प्रकार से किसी दूसरे लोगों के दबाव से इस तरह की पुस्तकों को सिलेक्ट करते हैं तो इससे लड़कों का कभी भला नहीं होगा और मैं तो यह कहूँगा कि इस खामी को निश्चित तौर से दूर किया जाना चाहिए।

दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि पाठ्य पुस्तकों की सूची बहुत देरी से प्रकाशित की जाती है। आम तौर से फरवरी में इसकी सूची प्रकाशित कर दी जानी चाहिए जिससे कि मालूम हो सके कि आयन्दा साल में कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ाई जावेंगी। मगर राजस्थान में पिछले वर्षों में देखने में आया है कि जुलाई में क्लासेज चालू हो जाती हैं और लड़कों के पास पुस्तकें पढ़ने

[श्री चांदमल मेहता]

को नहीं मिलनी क्योंकि जो किताबें पढ़ने के लिये बताई जाती है वह बहुत देरी से बताई जाती हैं और उनका प्रकाशन ठीक समय पर नहीं होता और लोगों को पुस्तकें मिलती नहीं और इसका नतीजा यह होता है कि ब्लेक मार्केट होता है। इसलिये यह इन्तजाम होना चाहिये कि पुस्तकें कौनसी क्लास में अगले साल पढ़ाई जावेंगी, लड़कों को जल्दी बतला दी जावें। अप्रेल में इम्तहान हो जाते हैं और अगर कोई व्यक्ति गर्मी की छुट्टियों में पढ़ना चाहे तो पढ़ नहीं सकता। मैं समझता हूं कि इसमें भी कुछ गड़बड़-घोटाला जरूर है क्योंकि पाठ्य पुस्तकें जो जारी होती हैं उनके लिए पहले तो कह दिया जाता है कि जारी रहेगी और अन्त में जब जुलाई का महीना आता है तो फौरन कह दिया जाता है कि वे ही पुस्तकें चालू रहेंगी और कभी कभी उनमें फेर-फार हो जाता है और इस के पीछे कोई न कोई राज अवश्य छिपा होता है। अगर माननीय मंत्री महोदय इसके बारे में जांच करेंगे तो उनको मालूम हो जावेगा। मैं समझता हूँ कि इसमें दो राज हो सकते हैं :

एक तो यह है कि जिन जिन पुस्तकों को तब्दील करने की बात सोची जाती है, उनसे अगर कुछ मिल जाता है तो उनको तब्दील नहीं किया जाता और उस विचार को तब्दील कर दिया जाता है और वे ही पुस्तकें रख दी जाती हैं।

दूसरी बात यह है कि प्रकाशन पर्याप्त मात्रा में नहीं होता और होता है तो ऐसे समय में जब कि समय बहुत कम रह जाता है। इसलिये लोगों को ब्लेक मार्केट करने के लिए मौका मिल जाता है। पिछले समय में भी ऐसा ही हुआ था।

दूसरा कट मोशन पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में है। इस संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इसके लिए कोई निश्चित नीति को अपनाया जावे और इसके लिए योग्य व्यक्तियों का बोर्ड बनाना चाहिये और उनके सामने तजवीज आनी चाहिये। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिये कि जिस तरह को पुस्तक की चर्चा मैंने माननीय उपाध्यक्ष, अभी की है।

अब तीसरी कटौती का प्रस्ताव जो है वह इन्टर कोलेज में साइन्स की क्लासेज़ खोलने के बारे में है। इसके लिए मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिये, इसके लिए आपका ध्यान ए. आई. सी. सी. की बैठक जो अजमेर में हुई थी उस समय पंडित नेहरू ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हमें क्लर्क पैदा नहीं करने हैं, क्लर्कों की काफी संख्या है। हमें पैदा करने है टेक्नीशियन्स, इन्जिनियर्स, ओवरसियर्स, और टेकनिकल मेन।

यह विचार था क्योंकि उनके इस विचार को कार्यान्वित करना आवश्यक है। इस लिहाज से यह मैं आवश्यक समझता हूँ कि राजस्थान में जितने भी इन्टर कॉलेज हैं सब में विज्ञान की कक्षाएं चालू की जायं। आम तौर पर सब जगह विज्ञान की क्लासेज़ नहीं हैं। इस वजह से स्थानीय बच्चे जो विज्ञान की तरफ रूचि रखने वाले होते हैं या ज्यादा खर्च करके दूसरे स्थानों पर जाकर विज्ञान की शिक्षा हासिल नहीं कर सकते हैं वे उच्च शिक्षा से महरूम रह जाते हैं इसलिए मेरा यह निवेदन है कि राजस्थान के इन्टर कॉलेजेज़ में विज्ञान की क्लासें अवश्य खोली जांय।

[श्री चांदमल मेहता]

चौथा मेरा कटौती का प्रस्ताव है शिक्षा विभाग में प्रोमोशन, नियुक्ति आदि में जो पक्षपात किया जाता है इस संबंध में। उपाध्यक्ष महोदय, यह ऐसा महकमा है जिसमें अधिक से अधिक मिनिस्टरों को ओब्लाइज किया जा सकता है, यह एक ऐसा विभाग है कि इसमें काफी बेकार आदमियों को काम मिल सकता है। इस विभाग के डाइरेक्टर महोदय का यह काम है कि नई नियुक्ति अगर किसी जगह पर करनी हो तो सारे मिनिस्टरों के कमरों में जायेंगे और सब से पूछेंगे कि किस किस व्यक्ति को नियुक्त करना है। जिस तरह से मिनिस्टर महोदय का इशारा होता है उसी इशारे को पूरा करना डाइरेक्टर महोदय अपना कर्तव्य मानते हैं। एक तरह से तो यह बात ठीक ही थी क्योंकि उनका कनफोर्मेशन नहीं हुआ था, वे चाहते थे कि किसी तरह कनफार्मेशन हो जाय, इसलिये यह सब कार्य करते थे। एक दफा तो यहां तक हो गया था कि इनको हटाने तक की बात हो गई थी। तो इसके सिवाय उनके पास कोई चारा नहीं था कि वे मंत्रियों को खुश करें। जो जो भी नियुक्तियें होती हैं शिक्षा विभाग में शिक्षा विभाग के इन्स्पेक्टर्स की मीटिंग्ज होती हैं और उनमें यह निर्णय कर दिया जाता है कि मैट्रिक ग्रेड के, इन्टर ग्रेड के नये अध्यापकों को न लिया जाय। उसके बाद भी नियुक्तियां होती रहती हैं। जो अध्यापक पहले से नौकर हैं उनको प्रोमोशन दिया जायगा, इस प्रकार का निर्णय हो जाने के बाद भी नई नियुक्तियां होती रहती हैं क्योंकि किसी की नियुक्ति किसी मंत्री के दबाव से होती है और किसी की बड़े आदमियों के दबाव से होती है। अध्यक्ष महोदय, मैं नाम भी बतलाऊंगा। इस संबंध में मैं सवाल भी पूछ चुका हूँ और मुख्य मंत्री स्वयं बता चुके हैं कि स्थायी तौर पर ऐसे व्यक्तियों की नियुक्तियां हुई हैं। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर आपको मैट्रिक, इन्टर ग्रेड अध्यापकों की नियुक्ति ही करनी है तो जूनियर वेकेन्सीज हों, उस पर नियुक्त किया जाय। पुराने आदमियों का चान्स मार कर नये आदमियों को नियुक्त करना सरासर गलत है।

किशनगढ इन्स्पेक्टर्स के मातहत जो नियुक्तियां हुई हैं उनमें भी कई प्रकार की गड़बड़ियां हुई हैं वे अपनी ओर से सिफारिश करते हैं कि अमुक अमुक अध्यापक को मेट्रिक, इन्टर ट्रेन्ड ग्रेड दिया जाय लेकिन उनकी सिफारिश को नहीं माना। बल्कि डाइरेक्टर महोदय ने आदेश दे दिया कि फलां फलां आदमी को उन उन जगहों पर नियुक्त कर दिया जाय, फौरन उनकी नियुक्ति हो जाती हैं। उस पर डाइरेक्टर महोदय के खिलाफ कोई एक्शन नहीं। इसलिए हमको शक होता है जब इस प्रकार की गड़बड़ियां सामने आती हैं तो। हमें शुबहा होता है कि इसके पीछे राज क्या हैं। यह बात साफ है कि इन नियुक्तियों के पीछे किसी न किसी व्यक्ति का इशारा जरूर रहता है! ऐसी नियुक्तियां इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स किशनगढ़ के मातहत ही हुई हो, यह बात नहीं। दूसरे जयपुर के इन्स्पेक्टर्स आफ स्कूल्स हैं उनकी मातहत भी ऐसी नियुक्तियां हुई हैं। ऐसे अध्यापक जिनकी नौकरी को १५ साल हो गये इन्टर ट्रेन्ड हैं किन्तु उनको मिडिल ग्रेड मिल रही है। इनको मौका नहीं मिलता क्योंकि नये अध्यापक नियुक्त किये जा रहे हैं इस प्रकार की गड़बड़ियां जो शिक्षा विभाग में हो रही हैं उनको ठीक किया जाना चाहिये।

[श्री चांदमल मेहता]

एक और मेरा कटोती का प्रस्ताव है अध्यपकों के फिक्सेशन के बारे में। वैसे ही अध्यापकों को बहुत कम तनख्वाह मिलती है इस लिए उनके फिक्सेशन के मामले को पेंडिंग पड़ा रखना बड़ी भारी भूल है।

(घंटी)

श्री सभापति—आप संक्षेप में कहिये।

श्री चांदमल मेहता—इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जब मैं दूसरी बार चुन कर आया था उसके बाद से मैंने यह प्रश्न तीन बार उठाया था। पहले जब इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था उस समय जो शिक्षा मन्त्री थे उन्होंने कहा कि हमने इसके लिये बोर्ड नियुक्त कर दिया है वे भी मन्त्री चले गये। उसके बाद दूसरे शिक्षा मन्त्रीजी आये उनको भी मैंने वही प्रश्न तीन बार पूछा इस सेशन से पूर्व वाले बजट सेशन में हमारे आज के शिक्षा मन्त्रीजी जबाब देते हैं कि अगले अधिवेशन के पहले पहल फिक्सेशन का मामला तय कर दिया जायगा। लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि अब यह जबाब दिया गया है कि अप्रेल तक अवश्य कर देंगे। मैं नहीं समझ पाया कि जो फिक्सेशन कई अरसे से पेंडिंग है और जिसके बारे में तीन चार बार आश्वासन भी दिया गया है उसके बाद भी कार्यवाही नहीं होना केवल दुर्भाग्य के सिवाय कुछ नहीं कहा जा सकता। आज हमारे मन्त्री महोदय आश्वासन दे देते हैं किन्तु उनको कार्यान्वित नहीं करना चाहते। मैं जहां तक आश्वासन के पूरा न किये जाने का कारण जान सका हूँ वह यह है कि इस विभाग में अव्यवस्था है, कार्य की शिथिलता है। मैं आशा करूंगा कि अभी हमारे मुख्य मन्त्री ने जो अन्तिम आश्वासन दिया है कि अप्रेल के अन्दर हम पूरा फिक्सेशन कर देंगे वह अवश्य पूरा होगा। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार पहले दिये गये आश्वासनों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया इस प्रकार इस आश्वासन का तो नहीं होगा ?

अब मेरा एक कटोती का प्रस्ताव है अध्यापकों के वेतन के बारे में। उपाध्यक्ष महोदय, अध्यापकों को वेतन बहुत कम दिया जाता है। अब कुछ वृद्धि की गई है। मन्त्री महोदय ने कुछ प्रान्तों के नाम बताये कि उन प्रान्तों के मुकाबले में हमारे यहां की तनख्वाह तो ग्रेड ज्यादा है। मैं उन्हीं प्रान्तों की तनख्वाहों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उन्होंने मध्य भारत की चर्चा की थी। वहां भी ग्रेड्स रिवाइज हुई हैं। मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ कि उन्होंने अभी १० रूपये की तरक्की दी है उन अध्यापकों को जो नीचे की ग्रेड में रहते थे। मैं यह भी निवेदन कर दूं कि मध्य भारत ने यह भी तै किया है कि उनको दो तीन ग्रेड एक साथ दे दी जांय। यह जो कुछ कह रहा हूँ मैं राष्ट्रदूत में अभी पांच छ रोज पहले मध्य भारत की रिवाइज्ड ग्रेड जो छपी थीं उसके आधार पर कह रहा हूं। यह मैं नहीं कह सकता कि ये जो छपीं हैं वे गलत हैं या सही हैं।

[श्री चांदमल मेहता]

पर जो छपी हैं और जिस पत्र में छपी हैं वह में सदन के सन्मुख रखने को तैयार हूँ।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ध्यान मैं इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जहां दूसरी जगह अध्यापकों को ४० रुपये दिये जाते हैं वे मिडिल ग्रेड के हैं। हमारे यहां मिडिल ग्रेड जरूर है पर लिये जाते हैं मेट्रिक ग्रेड के। जब मेट्रिक ग्रेड के अध्यापक को लेते हैं और फिर दूसरी स्टेटी से मुकाबला करते हैं तो हम इस में अपने को एक कदम पीछे ही पाते हैं। तो जहां तक अध्यापकों के वेतन का प्रश्न है इस बारे में ठीक सुधार किये जावेंगे और इन तथ्यों के सामने माननीय मुख्य मन्त्री जी अपनी जिद्द पर कायम नहीं रहेंगे। एक लोअर डिविजन क्लर्क के समकक्ष तो कम से कम आप एक अध्यापक को रख दें।

(घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, घंटी दुबारा आ गई। इसलिये अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए मैं यही निवेदन करूंगा कि जो मन्त्री महोदय कहते हैं तो वे पाठ्य पुस्तकों के बारे में निश्चित कदम उठावें और वेतन स्तर पर भी विचार किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

(भाषण अनुमोदित होकर प्राप्त नहीं हुआ)

श्री उपाध्यक्ष—श्री जवानसिंह (अनुपस्थित)

श्री सन्तोषसिंह—माननीय उपाध्यक्षजी, मेरे कटौती के प्रस्ताव का यह मतलब है कि गांवों में पाठशाला खोलने की जब प्रार्थना की जाती है तो सरकार यह कहती है ....

श्री मानसिंह महार—माननीय सदस्य जरा अपना प्रस्ताव पढ़कर सुना दें।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा-कि पाठशाला के लिए मकान तुम दो, आधा हिस्सा गांव वाले दें आधी मदद सरकार देगी। पर बड़े बड़े शहर जो हैं, जैसे जयपुर, जोधपुर या बीकानेर इनमें बड़े बड़े कालेजों और हाई स्कूलों का निर्माण होता है वहां सरकार किसी से पैसा नहीं मांगती। तो गांव वालों के साथ यह सोतेला व्यवहार सरकार का क्यों है ? तो मेरा निवेदन करना यही है कि जहां भी सरकार पाठशाला खोले वहां सारा पैसा अपने पास से खर्च करे ?

दूसरा मेरा यह कहना है कि जहां दूसरी जगह कहीं भी लडकियों की पाठशालाओं में फीस नहीं लगती वहां हमारे यहां राजस्थान में लड़कियों से भी फीस का लिया जाना उचित नहीं है।

[श्री सन्तोषसिंह]

प्रश्नों के जवाब में सरकार कहती भी है कि फीस नहीं ली जाती, पर वास्तव में ली जाती है। कहीं कहीं बस का किराया इन दो सालों में इतना बढ़ा दिया गया है कि गरीब लडकियों के लिये देना मुश्किल है। यह भी हुआ कि एक मील का और दो मील का बस का एक ही किराया कर दिया है। कोई फरक नहीं रक्खा गया।

तो माननीय उपाध्यक्षजी, मैं प्रार्थना करूंगा कि वह बस की फीस कम की जावे और लडकियों की फीस हटा दी जावे।

बजट से मालूम हुआ कि एक लडकियों का कालेज जयपुर में, एक बीकानेर में खोले जाने की बात है, जोधपुर में कोई नहीं खोला जा रहा है। जो कालेज मौजूद है वह छोटा है। एक एक कमरे में कम से कम ७०,७० लडकियां बैठती हैं। जो छात्रावास बनाया गया है वह भी कम है। सरकार की तरफ से तीन किराये के मकान लिये हुए हैं। १५ सौ रुपया माहवार का किराया देना पड़ता है तो प्रार्थना करूंगा कि यह पन्द्रह सौ रूपया किराया का न देकर अगर वहां सरकार अपना छात्रालय बना दे तो यह खर्चा बच जावेगा हमेशा के लिये और विद्यार्थियों को भी हमेशा के लिए आराम हो जावेगा। कम से कम ४०० लडकियों के लिये छात्रावास बन जावे तो अच्छा है।

गांवों के लिये सरकार कहती है कि मकान मास्टरनियों के लिए रहने को और स्कूल के लिए दिया जावे तो वहां सरकार स्कूल खोल सकती है। पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करूंगा कि इससे लड़कियों की पढ़ाई में रुकावट ही आवेगी। जब कि उनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। यहां तो वैसे भी मां बापों का ध्यान लड़कियों को पढ़ाने का कम रहता है। पर लड़कियों को पढ़ाना बहुत जरूरी है और सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिये। तो ये सारी बातें कहकर अपना कटोती का प्रस्ताव पेश करते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ माननीय शिक्षा मन्त्रीजी से कि वे इसे मान लें।

श्री उपाध्यक्ष—श्री भोपालसिंह।

श्री भोपालसिंह—मेरा भी इस पर एक कटोती का प्रस्ताव है। मैं अर्ज करूंगा कि गांवों में जो शिक्षा दी जाती है सरकार कह तो यह रही है कि हम शिक्षा पर बहुत खर्च कर रहे हैं पर गांवों में जो पैसा खर्च किया जाता है आधा सरकार खर्च करती है और आधा हम गांव वालों को करना पड़ता है जबकि शहरों में सारा का सारा पैसा स्वयं खर्च करती है और वह रूपया लाखों की तादाद में होताहै। तो यह गावों के लिये और नीति और शहरोंके लिये दूसरी नीति यह अलग अलग नीति क्यों बरती जाती है गांवां में भी सरकार को स्वयं को सारा खर्चा करना चाहिये और गरीब लोगों से चन्दा लेकर स्कूलों का निर्माण करने की नीति छोड देनी चाहिये।

[श्री भोपाल सिंह]

साथ ही मैं यह निवेदन करूं कि गांवों में जो शिक्षा दी जावे उसमें ज्यादातर महाजनी पढ़ाने की व्यवस्था की जानी चाहिये। वहां हरेक आदमी ग्रेजुएट तो होता नहीं, वहां अधिकतर महाजनी विद्या से काम पड़ता है तो यही शिक्षा वहां के लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है। पहले की पुरानी पाठशालाओं में महाजनी पढ़ाने वाले अनुभवी शिक्षक ही रहते हैं। पर जब से सरकार ने उन पाठशालाओं का संचालन अपने हाथ में लिया है अनुभवहीन अध्यापक वहां भेजे जाते हैं जो महाजनी नहीं जानते तो उनके स्थान पर पुराने अनुभवी महाजनी विद्या को जानने वाले शिक्षक ही रक्खे जाने चाहिये। इससे विद्यार्थियों को अधिक हित होगा।

एक बात और यह कहनी है कि इन अध्यापकों का वेतन कम है और कम वेतन में अच्छे आदमी नहीं मिल पाते। नतीजा यह होता है कि गांवों में स्कूलें जम नहीं पाती वहां की व्यवस्था खराब होने से और अच्छे अध्यापकों के अभाव में बच्चे पढ़ने को कम आते है। गांव के लोग अकसर यह देखा करते हैं कि मास्टर कैसा है। जब वे देखते है कि मास्टर यह अच्छा नहीं है तो पुराने मास्टरों को रख कर शिक्षा दिलाते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि अच्छी तनख्वाह उनको दी जावे और गांवों में पुराने अनुभवी मास्टर भेजे जावें जिससे कि हमारी स्कूलें वहां अच्छी जम सकें।

मेरे गांव के पास पालडी ग्राम है। वहां स्कूल है। वहां मास्टर नहीं था। मिनिस्टर साहब ने कहा कि भेजा गया है। तो अब गया होगा। पर इस तरह से वहां पहले भी दो तीन बार हो चुका है। मिडिल स्कूल का भवन निर्माण किया गया है, अच्छा भवन हैं वह। पर इसमें भी मास्टर दो चार दिन रहते हैं और फिर छोड जाते हैं। तो इस तरह से लड़कों का पढ़ने का समय खराब होता है ऐसा नहीं होना चाहिये। फिर यह स्कूल अच्छा है, करीब दो सौ ढाई सौ लडके है; तीन चार गांव आसपास लगते है। पर इसमें अभी मास्टर दो ही हैं। एक शायद भेजा गया होगा तो तीन हो जावेंगे। पर इसमें यह बात यह नीति निर्धारित कर देनी चाहिये कि इतने लड़कों पर इतने अध्यापक होंगे ताकी पढाई का काम अच्छी तरह चल सके, नहीं तो एक साथ हाहू होती है।

तीसरी बात यह मैं अर्ज करूंगा कि डेगाना तहसील हैडक्वार्टर हो गया है और वहां एक मिडिल स्कूल है। वहां लड़कों की काफी संख्या है इसलिए तमाम हमारी तहसील के ग्रामवासियों का यह निवेदन है कि वहां पर एक हाई स्कूल बनाया जाना उपयुक्त होगा।....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—कहां ?

श्री भोपालसिंह :—डेगाना जो कि तहसील का हैडक्वार्टर है। वहां के मिडिल स्कूल का हाई स्कूल होना जरूरी है। हमलोगों को गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया था कि १० हजार रूपये गांव वाले दें तो हाई स्कूल खोलने के लिए तैयार है। उन १० हजार में से ६ हजार तो गांव वालों ने इकट्ठे कर लिये थे और ४ हजार के लिए निवेदन किया था कि इकटठे कर लेगें हमारे यहां

[श्री भोपालसिंह]

हाई स्कूल बना दिया जाय, मगर वहां हाई स्कूल नहीं बनाया गया और दूसरी जगह खोल दिया गया। इसलिए मेरा यह खास निवेदन है कि इस साल वहां हाई स्कूल जरूर खोला जाय।

दूसरे, मेड़ता में एक हाई स्कूल है और उसके आस पास करीब करीब २० मिडिल स्कूल हैं तो तमाम स्कूलों के लड़के वहां जाकर शिक्षा पाते हैं इसलिए वहां पर प्रवेश नहीं मिलता है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि वहां जगह बढ़ाई जाय और मकान बनाया जाय ताकि सब तहसीलों के लड़के वहां जाकर शिक्षा प्राप्त कर सकें इसलिए मेरा खास निवेदन है कि इसमें चन्दा इकट्ठा करने की बात को न देख कर सरकार की तरफ से वहां पर भवन निर्माण किया जाना चाहिए।

मैं निवेदन करूंगा कि मेड़ता में लड़कियों की एक स्कूल है वह अभी भी किराये के भवन में लगी हुई है। सरकार की तरफ से पैसा लगाकर वहां पर भवन निर्माण किया जाय और लड़कियों के लिए अच्छी स्कूल बनाई जाय।

शिक्षा के अन्दर, चूँकि अब हमारा हिन्दुस्तान आजाद हो गया है, धार्मिक शिक्षा होना जरूरी है। इसलिए धार्मिक शिक्षा का यहां पर प्रचार किया जाय। यह मैं खास तौर से शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे जरूर इसमें धार्मिक शिक्षा का प्रचार करें तो बहुत अच्छा है।

गिरवा नाम का तहसील डेगाना में एक गांव है जहां कि १० हजार रूपये लोग देने को तैयार हैं उन्होंने मिडिल स्कूल की मांग रखी है कि हमारे यहां मिडिल स्कूल बनाया जाय। १० हजार रूपये देंगें और कुछ सरकार इमदाद करे तो वहां मिडिल स्कूल हो सकता है। लड़के ज्यादा होते हैं और गांववाले काफी रूपया देने को तैयार हैं तो सरकार को वहां मिडिल स्कूल खोलना चाहिए।

यह कह कर मैं अपने कटमोशन को प्रस्तुत करता हूँ। आशा है सरकार ध्यान देकर अच्छा आश्वासन देगी।

श्री सभापति—श्री अवनिकुमार मुकर्जी।

(अनुपस्थित)

श्री भैंरूसिंह—(वि० सं० १६)

माननीय चैयरमेन महोदय, शिक्षा विभाग के सम्बन्ध में अपने कटौती प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के बारे में इजाजत मांगता हूँ और वह कटौती का प्रस्ताव सदन में इसलिए प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि राजस्थान के शिक्षा विभाग में यदि ठीक ढंग से देखा जाय तो यह पता लगेगा कि

[श्री भैरूसिंह]

इस विभाग में या इस विभागके द्वारा जिनको हम पढ़ाते हैं, जिनको पढ़ाने के लिए मुकर्र किये गये हैं या इन दोनों की जो व्यवस्था कर रहे हैं वे तीनों ही इस विभाग की अव्यवस्था के कारण दुखी हैं। छात्रों में जाकर पूछिये तो पता लगेगा कि उनमें भी पूर्णतः असंतोष है। यदि शिक्षकों से जाकर पूछा जाय तो उनमें भी पता लगेगा कि पूर्णतः असंतोष है, और यदि सरकार के अधिकारियों के पास भी पहुंचा जाय तो वे भी इस प्रकारके लगते हैं, कि जैसे कि शायद इस विभाग की व्यवस्था उनके काबू की चीज न हो। इन तीनों चीजों के बारे में विस्तार से न जाते हुए यदि सूक्ष्म रूप से देखा जाय तो निश्चित रूप से पता लगेगा कि हमारी राजस्थान की सरकार अभी तक जिस प्रकार की हम अपेक्षा करते थे उस प्रकारकी सहूलियतें छात्रों को न दे सकी है। छात्रोंके ऊपर फीसें लगातार न बढ़ाई जांय, पढ़ाने का प्रबन्ध अच्छा हो, शिक्षक वैल क्वालिफाइड मिलें और शिक्षा की अन्य सामग्री सुलभता से उनको उपलब्ध हो, इस बारे में राजस्थान सरकार का काफी अभाव प्रतीत होता है। मैं इन बातों की ओर संकेत करते हुए यह चाहूंगा कि इन सभी बातों की सदन में थोड़ी थोड़ी चर्चा की जाय।

जहां तक पढ़ने की किताबों का प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने गत वर्ष में कुछ पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण किया। राजस्थान सरकार ने यह निर्णय लिया, शायद इस ख्याल से कि टेक्स्ट बुक्स के सिलेक्शन में और टेक्स्ट बुक्स के वितरण में और छात्रों तक उनके पहुँचनेमें किस प्रकारकी गड़बड़ियां होती हैं, इसलिए यह उचित होगा कि उनका राष्ट्रीयकरण किया जाय ताकि समयपर पुस्तकें छपें तथा उनके पास पहुंच जांय और उनके वितरणमें जितनी सहूलियत प्रदान कर सकें उतनी सहूलियत प्रदान की जांय। लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि जिन पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण किया गया वे पुस्तकें समय पर उपलब्ध नहीं होती हैं, वे पुस्तकें गलतियों से भरी हुई हैं और तथ्य से विपरीत हैं। मैं आपके सामने एक पुस्तक का उल्लेख करूंगा और वह पुस्तक है, माननीय सभापति जी, एक अंग्रेजी की, जिसका नाम न्यू इण्डिया इंगलिश रीडर, रीडर थर्ड, और इसके लिखने वाले हैं डा० उमरावबहादुर एम. ए. पी. एच. डी.। इस किताब की कीमत है १५ आने नो पाई। इस किताब में गांधीजी का एक लेसन (lesson) है। मैं समझता हूँ कि राजस्थान का कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो कि गांधी जो से अपरिचित हो, गांधीजी के नाम से अपरिचित हो और गांधी जी के पिताजी के नाम से अपरिचित हो। राजस्थान में ही नहीं भारतवर्ष में भी ऐसा अभागा नहीं होगा। उस अभागे का नाम यदि दृष्टिगोचर होता है तो इस किताब में हमें मिलता है। जिस किताब में लिखा था—

"Mohandas Karam Chand Was Born on October 2, 1869 at Porbunder in Kathiawar. His Father's Name Was Mohandas Gandhi."

मैं समझता हूं कि सब लोग जानते हैं कि गांधीजी के पिता का नाम क्या था और गान्धीजी का, स्वयं का नाम क्या था, लेकिन इस किताब में गान्धीजी का खुद का नाम उनके पिता

[श्री भैरूसिंह]

के नाम के स्थान पर रखा है और उनके पिता का नाम स्वयं के नाम के स्थान पर रखा है। यह राजस्थान सरकार की शिक्षा का एक तरीका है। राजस्थान सरकार द्वारा अच्छे २ नेताओं के जीवन के सम्बन्ध में ज्ञान कराने का किस प्रकार का तरीका है। यह पुस्तक एक अंग्रेजी की राष्ट्रीयकरण की हुई पुस्तकों में से है और इसके ऊपर डाइरेक्टर ऑफ एजूकेशन की मोहर लगी हुई है और राजस्थान के स्कूलों की क्लासेज़ में पढ़ाई जाती है। इतना ही नहीं, यह माना जा सकता है कि गलती से ऐसा छप सकता है, लेकिन गलती से छपने के बाद भी यदि गलती की ओर सरकार का ध्यान माननीय सदस्य आकर्षित करें तो ध्यान आकर्षित करने के बाद सरकार का कर्तव्य हो जाता है कि छपने की भूल हुई है, छपवाने वाले की भूल हुई है, लिखने वाले ने भूल करदी, सिलेक्शन करने वाले ने भूल करदी, लेकिन अब आवश्यकता है कि उसका सुधार करें, । लेकिन आज तक पोजीशन यह है कि इस नाम के लिए कोई भी किसी अधिकारी ने सूचना देने के बाद भी, उनका ध्यान आकर्षित करने के बाद भी सुधार हुआ हो ऐसा मुझे लगता नहीं है, और आज के दिन भी यह किताब राजस्थान की क्लासेज में पढ़ाई जा रही है।

यदि एक किताब का ऐसा हो, कि गांधीजी के जिक्र में ऐसा हो गया हो तो उस किताब के पढ़ाने वाले, मैं समझता हूं, शायद गलती न करें, लेकिन यदि दूसरी किताबों को उठाकर देखें तो जो एक किताब संस्कृत में लिखी गई है और संस्कृत की कक्षा ६ के लिए है। उसमें एक पाठ है पेज ५८ पर, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि भगवान राम और सीता का आपस में संवाद हो रहा है। वह संवाद किस बात के लिये हो रहा है, शबरी के आश्रम के लिए। मैं समझता हूं कि अधिकांश व्यक्ति रामायण पढ़े हुए हैं, उनको रामायण का ज्ञान है, किसी को इस बात का ज्ञान नहीं हो तो वे यहां सदन की लाइब्रेरी में से रामायण लेकर पढ़ें और देखें कि शबरी के आश्रम के बारे में और शबरी के विषय में राम और सीता का संवाद होता है। वह रामायण में कहां है ? रामायण उठाकर आप देख लीजिये लाइब्रेरी में से, संस्कृत के अच्छे से अच्छे पंडितों से पूछें कि भगवान राम और सीता के बीच कभी शबरी के बारे में कोई संवाद हुआ है। वह कभी भी नहीं हुआ है। पर यहां पर यह बताया जाता है। इसमें शबरी के आश्रम में आने जाने के बारे में भगवान राम और सीता के बीच संवाद हो रहा है। वह संस्कृत का ज्ञान कराने के लिये छात्रों को पढ़ाते हैं। वह किस प्रकार की किताबें छात्रों को पढ़ने के लिए दे रहे हैं ?

दूसरा उल्लेख दे रहा हूं कि किताबें समय पर मिलती है या नहीं। जुलाई, ५५ से राष्ट्रीयकरण किया गया और पुस्तकें छात्रों को हमने पढ़ने के लिए दीं और गजट में प्रकाशित कराया। गजट में प्रकाशित कराते समय कुछ पुस्तकों के बारे में ऐसा निर्णय दिया कि इन पुस्तकों को अभी नही पढ़ाया जाय, यह पुस्तकें सरकार के विचाराधीन हैं। उन पुस्तकों में से २ पुस्तकों का मैं अर्ज करूंगा। दोनों पुस्तकें सामाजिक अध्ययन की हैं, कक्षा ३ और ८ के लिए। यह दोनों किताबें जोधपुर के लिये निर्धारित की गई थीं। जुलाई के गजट में प्रकाशित होता है कि राष्ट्रीयकरण किया गया और पुस्तकों की सूची किस २ क्लास में पढ़ाई जायंगी और कौन २ सी तारीखों से वे किताबें

[श्री भैरूसिंह]

पढ़ाई जायंगी निकाली गई। जुलाई के महीने में इस प्रकार की सूची गजट में प्रकाशित होती है, उसमें यह लिखा रहता है कि दोनों पुस्तकें अभी तक सरकार के विचाराधीन हैं। इस विचाराधीन होने की सूरत में जो उनके प्रकाशक हैं, वे प्रकाशक चिट्ठियां देते हैं कि यह जो सरकार ने इन दो पुस्तकों के बारे में अन्डर कन्सीडरेशन का किया है वह गलत है। सरकार के सामने जो दो किताबें विचाराधीन थीं वे इसलिए नहीं पढ़ाने दी गई कि वे सरकार के विचाराधीन हैं। जुलाई के महीने में पुस्तक विक्रेताओं ने शिकायत की थी, जब वह पत्र उन्होंने पेश किया, डिप्टी डायरेक्टर ने वापिस लिखा कि सरकार के अन्डर कन्सीडरेशन हैं और ज्योंही निर्णय होगा उसकी सूचना दे दी जायगी। लेकिन बदकिस्मती से अक्टूबर तक सूचना नहीं आयी कि जो किताबें अन्डर कन्सीडरेशन थीं उनका क्या हुआ? अक्टूबर में फिर पुस्तक विक्रेताओं ने, जब छात्रों की पुस्तकों के लिए बाद आ जाने से, ख्वाहिश जाहिर की तो फिर सूचना मैं समझता हूं कि नवम्बर दिसम्बर में जाती है कि जो दो पुस्तकें अन्डर कन्सीडरेशन में थीं जिनका पढ़ना रोका गया था वे पढ़ाई जांय और यह रखा कि ये अक्टूबर के महीने से लागू होगी। आप अन्दाज लगाइये कि जुलाई निकल गया, अगस्त निकल गया, सितम्बर, अक्टूबर और नवम्बर में छः महीनों के बाद इस प्रकार का ऑर्डर निकलता है। ६ महीनों तक जब कि बच्चे स्कूलों में साल में, ६ महीने तो पढ़ते हैं, बिना पुस्तकों के रहे, मजबूर होकर क्लासों में आकर बैठते थे और इन सबजेक्ट्स को पढ़ाने के लिए जो अध्यापक निर्धारित करते थे, अध्यापकों के पास किताब नहीं, लड़कों के पास किताब नहीं और उनका पूरा का पूरा समय सरकार की इस व्यवस्था के कारण, सरकार की इस गलत नीति के कारण, सरकार का उचित प्रबन्ध न होने के कारण छात्र बैठे रहे, मास्टर बैठे रहे। हमारी सरकार फीस जरूर लेती है, मास्टर पढ़ायें या न पढ़ायें, लडके पढ़ें, या नहीं पढ़ें, पढ़ने के लिए किताब हो या न हो लेकिन फीस तो अवश्य ही ली जाती है। जोधपुर से आने वाले मित्र ने बताया कि सरकार को चाहिए तो यह था कि यह फालतू खर्चा छोड कर राजस्थान सरकार यह प्रबन्ध करती कि छोटे २ बच्चों के लिए यह आवश्यक बना दे, उनके लिए कम्पलसरी कर दे कि किसी आस पास के स्कूलों में जाकर विद्या अध्ययन करो। हमारा कदम दूसरी तरफ जा रहा है, हमारी सरकार का कदम दूसरी तरफ जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा स्कोलर शिप के नाम पर लोगों पर टेक्स इम्पोज कर सकें तो करें। खेद इस बात का है कि यह जो सरकार टेक्स इस तरह से इम्पोज कर रही है उसमें भी असमानता है। जोधपुर में फीस और हैं, तो जयपुर में और हैं, जोधपुर में और हैं तो जैसलमेर में और हैं। जैसलमेर दूर पड़ता है, इसलिये ज्यादा लेते हैं। इसका कोई कारण नहीं है कि क्यों जयपुर में कम लेते हो और जोधपुर में और जैसलमेर में ज्यादा लेते हों। सरकार का इसमें जो लोजिक है, वह नजर नहीं आता मुझे। मंत्रीजी कहेंगे कि यह तो जनरल बात कहदी। मैं बताऊं कि जोधपुर में जो जशवंत कालेज है उसमें इन्टर मिडियेट में जो असफल छात्र होते हैं उनसे ८॥) फीस ली जाती है और यदि वैसे ही असफल छात्र जयपुर में हों तो यहां ३॥) फीस ली जाती है। दोनों में पांच रुपये का फर्क है। दलील जो दी जाती है वह यह दी जाती है कि जोधपुर में प्राध्यापक नहीं है और एक्स्ट्रा टायम अलाट करने के लिये पांच रुपया अधिकलेते हैं। यदि यह भी मान लिया जाय कि अधिक लेते है लेकिन छात्र पढ़ते है एप्रिल तक। मई,

[श्री भैरूसिंह]

जून और जुलाई इन तीन महीनों में वे नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हमारी सरकार ८) के हिसाब से अप्रेल, मई और जून इन तीन महीनों के २४) वसूल कर लेती है। एक दलील यह भी दी जाती है कि इसलिए फीस ली जाती है कि उनकी एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ती है और इस वजह से एक्स्ट्रा प्राध्यापक लगाने पड़ते हैं और उनको अलाउन्स किसी प्रकार देते हैं।

(श्री सुखाड़िया, मुख्य एवं शिक्षा मंत्री के सदन से बाहर जाने पर)

माननीय सभापति, आपकी आज्ञा हो तो मैं बैठ जाऊं, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है।

श्री सभापति (श्री हिम्मतसिंह) : Continue.

श्री भैरूसिंह— तो मैं निवेदन कर रहा था कि वैसी सूरत में दुगुनी, ढाई गुनी फीस ली जाती है अध्यापकों को अलाउन्स देने के लिए। लेकिन अध्यापकों को इस प्रकार से वसूल की गई फीस में से अलाउन्स नहीं दिया जाता है, इसके लिए मैं आपको जसवन्त कालेज के फीगर्स दे दूं, जानकारी हो तो मुख्य मन्त्रीजी बतावें। ३॥ के बजाय ८॥ फीस ली जाती है लेकिन फिर भी उन अध्यापकों को अलाउन्स नहीं दिया जाता है और सरकार तो उनको गर्मियों की छुट्टियां अलग दे देती है जब कि फीस के रूप में उनसे फीस तो वसूल कर ही ली जाती है। फीस में इस प्रकार का वर्गीकरण करना, इस प्रकार की असमानता रखना छात्रों में, यह एक असंतोष का कारण बन सकता है इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि स्कोलरशिप लगाने का एक आधार मानें, इसको लगाने में लोगों की आर्थिक स्थिति को सामने रखें, कितनी दी जा सकती है इस चीज़ को सामने रख कर कोई फीस लगावें तो उचित होगा, लेकिन टैक्स ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करके,स्कूल ज्यादा खोलेंगे तो मैं समझता हूँ कि सरकार अपने कर्तव्यों से च्युत होगी और अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेगी।

तीसरी बात जो मैं निवेदन करूंगा इस सम्बन्ध में वह यह है कि आज इन दो में ही असंतोष हो ऐसी बात नहीं, लेकिन अध्यापकों को आप जाकर पुछिये, इन्स्पेक्टरों को आप जाकर पूछिये, डिप्टी इन्स्पेक्टरों को आप जाकर पूछिये, डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर हैं उनसे पूछिये औरउनसे पूछने परआपको पता लगेगा। न अध्यापकों मेंसंतोष है, न इन्सपेक्टर्स से सन्तोष है, न डिप्टी इन्स्पेक्टर्स में संतोष है, न डिप्टी डायरेक्टर में संतोष और न डायरेक्टर में संतोष है। जिस विभाग के अन्दर छोटे से कर्मचारीसे लेकर उच्चाधिकारी तक असंतोष हो वह विभाग सफलता से काम करसकता है, यह बिलकुल संभव नहीं है। आप एक अध्यापक से जाकर पूछिये तो उससे पता चलेगा कि तनख्वाह कम है और जो कुछ मिलता है वह भी समय पर नहीं मिलता है और समय पर तनख्वाह देने के सम्बन्ध में इन्स्पेक्टरों के यहां कोई व्यवस्था नहीं है, इन्स्पेक्टरों के पास एक महीने की १५ तारीख को तनख्वाह आयी तो वह तनख्वाह उस अध्यापक को दूसरे महीने तक जाकर कहीं मिल पाती है और यदि अध्यापक तनख्वाह लेने आवे तो उसको लड़कों को टी. ए., डी.ए

[श्री भैरूसिंह]

अपनी जेब से देना पड़ता है। इसके लिए सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार की ओर से कोई इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है कि अध्यापक कार्य कर रहा है, छात्रों को पढ़ा रहा है, अगर वह आता जाता है तो छात्रों की पढ़ाई में हर्ज होता है, उनको उनकी तनख्वाह डिप्टी इन्स्पेक्टर्स या इन्स्पेक्टर्स के जरिये शीघ्र मिल जाय। एक तरफ तो उनको ६५) रुपये की तनख्वाह मिलती है, एक तरफ छोटी २ तनख्वाहों में वे अपना खर्च चलाते हैं और इस पर भी यह हाल है कि उनको समय पर वेतन नहीं मिल पाता। उनकी तनख्वाहें बढ़ाना तो दूर रहा लेकिन जो कुछ भी मिलता है वह भी समय पर नहीं मिल सकता है, यह सरकार के लिए शोभनीय नहीं कहा जा सकता है।

अध्यापकों में असंतोष चरम सीमा तक पहुँच रहा है। उनको प्रोमोशन्स और इन्क्रीमेन्टस के बारे में बड़ा असंतोष है। आज जितने ट्रन्ड नोन मेट्रिकुलेट्स हैं जो कि ट्रेन्ड हैं, ट्रेनिंग हो चुकी है लेकिन अनट्रेन्ड मेट्रिकलेट्स ही कहलाये जाते है और उनको ट्रेन्ड मेट्रकुलेट होने का प्रोमोशन नहीं मिलता है सरकार से पूछता हूं कि यह क्या हाल है? यदि बजट, आंकडे और एजुकेशन डिपार्टमेन्ट का स्टेटमेन्ट देखें तो आपको पता चलेगा कि इन्स्पेक्टर्स में अलग अलग एलोकेशन्स हो रखा है। उसको देखें तो मालूम होगा किसी इन्स्पेक्टर के बारे में क्या है और किसी में क्या। ट्रेन्ड मेट्रिकुलेट्स होने चाहिए वहां अनट्रेन्ड मेट्रिकुलेट्स हैं, नोन मेट्रिकुलेट्स ट्रेन्ड बैठे हैं तो अनट्रेन्ड मेट्रिकुलेट्स चल रहे हैं। किसी को प्रोमोशन दे दिया, किसी को नहीं दिया, ट्रेन्ड इन्टरमिडियट हो तो ग्रेजुअट की जगह खाली पडी है और जगह की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। प्रोमोशन नहीं मिला, इन्क्रीमेन्ट नहीं मिला। ऐसी सूरत में यदि हम सरकार के उच्च अधिकारियों के पास जाते हैं तो सभी कहते हैं कि मामला अंडर कंसीडरेशन है: एक कमीशन बैठनेवाला है, एक हाई पोवर कमीशन की नियुक्ति हो चुकी है, कमेटी बनाई गई है जल्दी ही काम शुरू करनेवाली है। सन् ४७ से आज तक ६ साल का अरसा गुजर चुका है। इस विभाग के अध्यापकों के अलावा राजस्थान सरकार का कोई भी कर्मचारी अभागा नहीं होगा जिसकी तनख्वाह नहीं बढ़ी हो, प्रमोशन नहीं हुआ हो और उसके साथ बुरी तरह से बरताव किया गया हो। हम उम्मेद करते है कि वे अध्यापक हमारे देश के नवनिमाण के लिये अच्छे नवयुवक पैदा करें, उनमें राष्ट्रीय भावना जाग्रत करें, फलां फलां कार्य करें। यदि इस प्रकार का असंतोष रहा उन अध्यापकों में तो मैं मान नहीं सकता कि यह नवयुवक पैदा करनेवाली मशीनरी किसी ढंग से काम चलायेगी। यदि उसके ठीक ढंग से तेल लगता गया, अच्छे अच्छे पुर्जे लगते गये तब तो ठीक ढंग से यह मशीनरी काम कर सकेगी। वरना इस मशीनरी से अच्छे नागरिक पैदा हो सकेंगे, ऐसी आशा नहीं करनी चाहिये।

मुख्य मंत्रीजी ने बजट पर आम वाद विवाद का उत्तर देते समय बताया कि हमने प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स की तनख्वाह इसलिये बढ़ाई कि जब कभी आर. ए. एस., आर. पी. एस., आर. जे. एस. आदि के इम्तहान होते हैं तो उनमें जो लोग देखने को मिलते हैं वे हैं अधिकांश लेक्चरार्स और प्रोफेसर्स; इसलिये यदि हम उनको यहीं ज्यादा तनख्वा दे देंगे तो वे लोग आर. ए.

Page No 57

[श्री भैरूसिंह]

एस., आर. पी. एस. आदि में नहीं जायेंगे और यहीं बैठे रहेंगे इसलिये उनका वेतन बढ़ाया गया है। यदि आपका ऐसा दृष्टिकोण है तो ऐसा दृष्टिकोण उन अध्यापकों के लिये भी क्यों नहीं बनाया ? मैं अर्ज करूंगा कि असंतोष के कारण वे लोग अध्यापक के कार्य को सेकन्डरी बिजनेस या साइड बिजनेस मानते हैं। वे सोचते हैं कि मेट्रिक पास हो गये ३०-३५ रुपये जो कुछ मास्टरी में मिलते हैं वह ठीक है, जब तक दूसरा काम नहीं मिलता है। मेट्रिक पास करके आगे पढ़ने कि सोचते हैं और बी. ए. आदि पास करने के बाद वे कोशिश करते रहेंगे और ज्यों ही अच्छा काम मिलेगा वे दूसरे महकमों में चले जायेंगे। यदि आप आंकड़े देखें तो आपको महलियत होगी कि कितनी नयी नियुक्तियें दूसरे महकमों में होती है उनमें अध्यापक कितने आते हैं और दूसरे लोग कितने आते हैं। यदि हमें सच्चे नागरिक भविष्य में पैदा करते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है तो यह आवश्यक होगा कि अध्यापकों को भी हम ऐसी तनख्वा दें जो उनको ऐज्युकेशन डिपार्टमेन्ट में ही मिल सकती है दूसरी महकमो में नहीं मिल सकती। दूसरे महकमों में उससे कम मिले। हमें ऐसा ही करना चाहिये ताकि अध्यापक लोग यह महकमा छोड कर दूसरी जगह नहीं जावें।

एक और खामी इस विभाग की मुझे जबरदस्त नजर आती है। एक अध्यापक मैट्रिकुलेट है। उसको ३५.१.४० या ४०.१.५० के ग्रेड में वेतन मिलता है। नौकरी करने के दो साल बाद वह इन्टर पास हो गया और फिर दो साल बाद वह ग्रेजुएट हो गया, उसने आगे और पढ़ाई की और वह एम० ए० पास हो गया। वह तो ६ साल में एम० ए० बन गया तो कोई चिन्ता नहीं उसको तो मेट्रिक के ग्रेड में तनख्वाह मिलेगी और नया आदमी जो कालेज से नया ही निकल कर एम० ए० पास होकर नौकरी में आता है तो उसको तो एम० ए० के ग्रेड की तनख्वाह मिलेगी लेकिन जिसको ६ साल का एक्सपीरियेन्स टीचिंग का हो गया है और ड्युरिंग अध्यापन काल उसने एम० ए० पास किया है तो उसको एम० ए० को ग्रेड नहीं मिलेगी, उसको तो वही मेट्रिक या इन्टर की ग्रेड मिलेगी। यह कितनी जबरदस्त एनोमोली है। इसके अलावा और भी जो अध्यापक है या नीचे के चपरासी आदि कर्मचारी हैं उनके बारे में सदन जागरुक है और इस बारे में सरकार का ध्यान सदन ने आकर्षित किया है। इसलिये उनके बारे में कुछ कह कर मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता।

इस विभाग में उच्चाधिकारी जितने हैं उनको भी असन्तोष है। इन्सपेक्टर्स ऑफ स्कूल्स का जो ओहदा है वह इन्सपेक्टर्स का ओहदा डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर के ओहदे से कम नहीं है। यह इसलिए कम नहीं है कि यहां पर नवयुवक पैदा करने का जो काम अध्यापक वर्ग करते हैं उन सब का कंट्रोल इन इन्सपेक्टर्स के पास होता है। नये रिवीजन ऑफ ग्रेड्स के अन्दर इन्सपेक्टर्स ऑफ स्कूल्स को अच्छी तरह से देखें तो पता चलेगा कि और ऑफिसर्स के मुकाबले में विशेष परिवर्तन हुआ हो ऐसी बात नहीं है। अब ऊपर चलिये। डाइरेक्टर और डिप्टी डाइरेक्टर के बारे में भी राजस्थान अभागा रहा है। राजस्थान में इस बात की भी चर्चा है कि डिप्टी डाइरेक्टर और

[श्री भैरूसिंह]

डाइरेक्टर में सरकार का विश्वास नही है। जहां डाइरेक्टर और डिप्टी डाइरेक्टर के बीच में नीति के कारण नहीं बल्कि और किसी कारण से मतभेद हो तो वहां शिक्षा विभाग अभागा ही है, इसके सिवाय अभागा और कोई काम नहीं हो सकता। राजस्थान के शिक्षा विभाग में एक डाइरेक्टर है और तीन डिप्टी डाइरेक्टर हैं। एक प्लानिंग का डिप्टी डाइरेक्टर हैं, एक टेक्स्ट बुक के लिए डिप्टी डाइरेक्टर है, एक डिप्टी डाइरेक्टर और नियुक्त किया जाने वाला है। एक एडीशनल डाइरेक्टर की नई नियुक्ति होती है जिसको सारा काम दिया गया है और डाइरेक्टर के पास कोई काम नहीं है सिवाय स्कूल्स का इन्सपेक्शन करने के। वह स्कूलों का इन्सपेक्शन करेगा और उसकी नजर में यदि कोई कर्मचारी काम नहीं करता है इसलिए उसको सजा दिलानी है तो डाइरेक्टर अपने मातहत के एडीशनल डाइरेक्टर को लिखेगा। अगर किसी अध्यापक की ट्रान्सफर करनी हैं तो वह स्वयं नहीं कर सकता लेकिन उसके मातहत जो अफसर हैं उनको लिखेगा और उसकी मर्जी होगी तो उच्चाधिकारी की बात मानेगा नहीं तो नहीं मानेगा।

अब डाइरेक्टर और डिप्टीडाइरेक्टर्स की पे स्केल के बारे में जरा सोचिये। यदि राजस्थान में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेन्ट कोई अधिकारी है तो वह है डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन। आज राजस्थान में ही नहीं बल्कि दूसरे प्रान्तों में भी जितनी डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन की इज्जत होती है उतनी दूसरे किसी अधिकारी की नहीं होती है। एक डाइरेक्टर के नीचे २००,२५० गजटेड ओफिसर्स का काम करने वाले होते हैं और वह २०० रु० मासिक वेतन तक के आदमी को नौकर रख सकता है। लेकिन उसका वेतन समानान्तर हैड ऑफ डिपार्टमेंट्स के वेतन से भी कम रखा गया है। डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन का वेतन दूसरों से कम नहीं होना चाहिये। यदि उसकी कम तनख्वाह है तो उस डाइरेक्टर को कभी संतोष नहीं हो सकता। राजस्थान के डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन की यह हालत है कि यदि हम चीफ इंजीनियर, डाइरेक्टर ऑफ मेडिकल एण्ड हैल्थ सरविसेज या अन्य विभागों के उच्चाधिकारियों की ओर देखें तो पता चलेगा कि एज्युकेशन के डाइरेक्टर की कितनी कम तनख्वाह रखी गई। एक आई० ए० एस० कलेक्टर की तनख्वा ८०० से १८०० की और एक कमिश्नर की तनख्वा १२०० से १८०० है तो डिविजनल कमिश्नर और चीफ इन्जीनियर या डाइरेक्टर ऑफ मेडिकल और हैल्थ सरविसेज़ से जिम्मेदारी में डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन किसी भी हालत में कम नहीं है। लेकिन उसकी तनख्वाह इन सब से कम रखी गई है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि डाइरेक्टर, डिप्टी डाइरेक्टर, इन्सपेक्टर्स ऑफ स्कूल्स और अध्यापकों में यदि इसी प्रकार का असन्तोष रहा तो मेरी मान्यता है कि इससे ठीक तरह से काम नहीं चल सकेगा। यदि इस विभाग में कोई अयोग्य आदमी है तो उसको निकाल दीजिये लेकिन शिक्षा विभाग में अच्छे आदमी रखिये और उसको अच्छी तनख्वाह दीजिये। ऐसे आदमियों को आप मत रखिये जिनको गांधीजी के पिता का भी नाम मालूम नहीं है और किताब में गलत नाम लिख दिया गया, है ऐसी पुस्तकें आज यदि पढ़ाई जाती है बच्चों को तो यही कहा जा सकता है कि एज्युकेशन विभाग का प्रबन्ध ठीक नहीं है। असन्तोष और काम में अरुचि ये दोनों फेक्टर हैं जो शिक्षा विभाग में अच्छी तरह से काम नहीं करने देते।

[श्री भैरूसिंह]

इसके अलावा मैं दो मिनिट में सदन का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि इस डिपार्टमेंट को इस मांग की दृष्टि से अच्छी तरह से देखें तो यह आवश्यक है कि देश के नागरिकों के चरित्र को हमें ऊंचा करना हैं। आज जो शिक्षा दी जाती है उसके बारे में यदि मैं अपने मुंह से कहूंगा तो लोग समझेंगे कि कैसी बात कह रहा है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति। उप राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री और अन्य शिक्षा शास्त्री जो हैं उनका यह कहना है कि करेक्टर को ऊंचा उठाने के लिए शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। एक बात की ओर संकेत है कि चरित्र कैसे ऊंचा हो। सभी लोग यह राय देते हैं कि हम लोगों को धार्मिक ज्ञान की ओर ध्यान देना चाहिये और उसके लिए संस्कृत की ओर हमारी प्रवृति होनी चाहिये लेकिन बदकिस्मती है कि राजस्थान में ४० से आज ५६ तक केवल ७५ पाठशालायें खोली गई हैं। आगामी वर्ष में हम ६०० नई पाठशालायें खोल रहे हैं लेकिन संस्कृत की एक भी पाठशाला नहीं खोली जायगी।

मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि हमारी सरकार संस्कृत के प्रति इस प्रकार की उपेक्षा नीति नहीं अपनाए। अगर सरकार संस्कृत की पाठशालाओं को खोलने के बारे में कोई नीति नहीं बनाती है तो संस्कृत का जो स्टेंडर्ड है उसको तो बनाये रखे। हमने यह सुना है कि सरकार ने संस्कृत की पाठशालाओं के लिए क्या क्या करना चाहिये, उसके लिए एक बोर्ड की स्थापना की जरूर है जिसके एल० एल० जोशी अध्यक्ष बने हैं और यह बोर्ड भ्रमण भी कर रहा है और इसका निर्णय ऐसा करने वाला है कि संस्कृत के प्रिंसिपलों को शिक्षा विभाग के बोर्ड के नीचे रख दिया जाए। मैं इस सम्बन्ध में यह अर्ज करूंगा कि यदि महाराजा कालेज के या जसवन्त कालेज के प्रिंसीपल को डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन के नीचे लगाते हैं तो वे चिल्ला उठेंगे और कहेंगे हमारा एफीलिएशन युनिवर्सिटी से होना चाहिये। इसी तरह से संस्कृत की पाठशालाओं की चर्चा भी युनिवर्सिटी के तत्वावधान में होनी चाहिये। यह तो गलत है कि उनको किसी बोर्ड के नीचे लगा दिया जाये।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करूंगा कि जो लोग संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करते हैं और संस्कृत पढ़ते हैं उनको नौकरी में लेनो की व्यवस्था की जानी चाहिये। आपने जो नौकरी के लिये योग्यता रखी है वह इस तरह की है कि एक तरफ तो संस्कृत का जानने वाला साहित्य रत्न और दूसरी तरफ एक मिडिल अंग्रेजी का जानने वाला हो, दोनों को बराबर रखा है। अमूमन यह कहते हुए सुना जाता है कि संस्कृत का ज्ञान है मगर अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है इसलिये नौकरी नहीं मिल सकती। मगर आप देखेंगे कि उसको अंग्रेजी का ज्ञान नहीं, मगर मिडिल वाले से तो बहुत ज्यादा चरित्र ज्ञान, भूगोल का ज्ञान, हिन्दी का ज्ञान होता है। अगर अन्य सारी बातों की दृष्टि से देखा जावे तो उस संस्कृत के जानने वाले के मुकाबले में मिडिल वाले को एक प्रतिशत भी ज्ञान नहीं होता और वह उसकी काबलियत के मुकाबले में ठहर नहीं सकता। मगर कम्पीटिशन में जावेगा तो मिडिल क्लास वाले को प्रिफरेन्स मिलेगा और संस्कृत वाले को नहीं। इसलिये सरकार से प्रार्थना है कि वह संस्कृत के प्रसार के लिए उनको नौकरी में लेने की व्यवस्था करे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य कट मोशन पर बोल रहे हैं या जनरल डिबेट कर रहे हैं।

श्री भैरू सिंह—अगर आप पहले कहते तो ज्यादा अच्छा होता। अब तो मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं।

मैने जो कुछ बातें शिक्षा के बारे में किताबों के बारे में और फीस लगाने के सम्बन्ध में कही हैं मैं समझता हूं कि सरकार इस पर विशेष ध्यान देगी और इससे जो अव्यवस्था फैली हुई है उसको बन्द करेगी। इतना ही कह कर मैं अपना कटौती का प्रस्ताव जो अध्यापकों का क्लिकेशन नहीं होने के कारण प्रस्तुत किया गया है, कटौती के रूप में सदन की सहमति के लिये प्रस्तुत करता हूँ।

श्री सभापति—श्री घासीराम।

(अनुपस्थित)

श्री श्रीदास गोयल।

श्री श्री दास गोयल—माननीय चेयरमेन, जहां तक शिक्षा का प्रश्न है मैने ११६,१२२, १२६ और १३२, चार कटौती के प्रस्ताव पेश किये हैं। इन चारों कट मोसन्स के सिलसिले में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ।

सबसे पहले मुझे इस विषय में कहना है कि जो चीज हमें हमारे देश की राष्ट्रियता की नींव को मजबूत बनाने में बाधक है, जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया कि विद्यार्थियों में जिस प्रकार का वातावरण आज कल चल रहा है वह सोचनीय है और शिक्षा विभाग की बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है उसको मिटाने के लिये। हमारे मित्रों ने कहा, हमने देखा। मेरे एक मित्र ने कहा कि विद्यार्थियों के युनियन के चुनाव होते हैं तो उसमें आपस में चैतावनियें दी जाती हैं लेकिन मैं इस विचार धारा का खुले तौर से विरोध करता हूँ और यह कहना चाहता हूँ कि विद्यार्थी को विद्यार्थी ही रहने दिया जावे, तो शिक्षा विभाग और बालकों का भला होगा। लेकिन हमारे कुछ मित्र अपने राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विद्यार्थियों का उपयोग करते है और मै यह कहूंगा कि राजस्थान का बड़ा अहित करते हैं। इसके अलावा मैं देखता हूं कि जब लड़कों में आपस में चुनाव होते है तो युनियन आदि के अलग अलग पोलिटिकल पार्टीज के एफीलिएशन बनते है और आपस में चुनाव लड़ते है और चुनावों में सैकड़ों रूपया खर्च करते हैं। अभी थोड़े समय पहले ही मेरी महाराजा कालेज के वाइस प्रेसीडेन्ट से मेरी बात चीत हुई। दो व्यक्ति गंभीरता से आपस में बैठे बैठे विचार और चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से किस रूलिंग का मुकाबिला किस रूलिंग से किया जावे। इसलिए वे शिक्षा की ओर पूरा ध्यान

[श्री श्रीदास गोयल]

नहीं देते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इससे न तो राष्ट्रों का भला होगा न बालकों का ही भला होगा और न वे राष्ट्र की सेवा ही कर सकेंगे। माननीय चैयरमैन, मैं आपके द्वारा सदन से निवेदन करूंगा कि जो लोग इस प्रकार का विद्यार्थियों में वातावरण पैदा करने वाले हैं और गड़बड़ी हो उसका मजबूती से मुकाबला करें और इसलिए विद्यार्थी का हितसोचना उसकी सबसे बड़ी जुम्मेदारी है। संस्कृत के लिए कहा जाता है कि इसको पढ़ने से हमारी भारतीय संस्कृति का उत्थान होगा जिसने हमें मानव बनाया, मानव से देवता बनाया, हमें संस्कृत की तरफ ध्यान देना चाहिए। इससे हम जनकल्याण की ओर आगे बढ़ेंगे और सुन्दर कार्य कर सकेंगे। मैं तक्षशिला में जिस प्रकार से शिक्षा चलती थी, जिसके पीछे हम आज अशोक चक्र चला रहे हैं। जिसके पीछे चन्द्रगुप्त मोर्य के कोटल्य ने जिसे जन्म दिया था, उसकी तरह चलावें तो टीक होगा। लेकिन मैं, आज हमारे यहां कालेजों में शिक्षा को देखता हूँ कि सैंकड़ों लड़के पढ़ते हैं। केम्ब्रिज और ओक्सफोर्ड में भी युनिवर्सिटीज में पढाई होती है। मेरी एक वहां के प्रोफेसर से बात हुई थी उन्होंने कहा कि वहां पर १००० लडकों के पीछे १०० प्रोफेसर हैं यानि १० लडकों के पीछे एक ट्युटर होता है। वहां के पढ़े लिखे लोग सोसायटी के लिए बहुत हित कर होते हैं। मगर यहां पर हम देखते है कि ३५०० विद्यार्थी हैं, जिनके लिए १०० से कम अध्यापक होते हैं। प्रोफेसर जब अटेण्डेन्स लेता है तो सब के नाम नहीं जानता। प्रोफेसर अपने से संबंधित विद्यार्थी को जान नहीं सकता। वहां पर सब को जानता है। मैंने प्रोफेसर साहब से पूछा कि क्या फीस है तो उन्होंने बताया कि एक विद्यार्थी की १०० रुपये माहवार पड़ती है। मगर हमारे यहां तो बजट को देख कर ही खर्च किया जा सकता है। तेल तो तिलों से ही निकलता है। यहां पर यह कहा जाता है कि फीस कम की जावे और इसके लिए लोगों को उकसाया जाता हैं तो यह अच्छा नहीं कर रहे हैं। व्यवहारिकता को देखते हुए मैं यह निवेदन करूंगा कि विद्यार्थी जो ओक्सफोर्ड और केम्ब्रिज से निकलते हैं वे अच्छे और संसायटी के लिए हित कर होते हैं। केम्ब्रिज से हमारे पंडित नेहरु जैसे व्यक्ति हुए। मैं तो हमारे शिक्षा मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि जितना कपडा तैयार है उसको ध्यान में रखते हुए उन रूपयों का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग किया जा सकता है, किया जावे।

अब जैसा कि शिक्षा में मूलभूत परिवर्तन की बात हो रही है और यह कहा जाता है कि जो शिक्षा दी जाती है वह उस प्रकार की शिक्षा है, जो गुलामों के तौर पर पहले दी जाती थी। मल्टी परपज स्कूल खुले हैं जिनमें हमारे विद्यार्थियों को दस्तकारियों की शिक्षा मिलती है लेकिन जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने कहा आगे की शिक्षा में इसके लिये बड़ी रुकावटें होती हैं। तो मेरा यह निवेदन है कि इन रुकावटों को हटाने के वास्ते गम्भीरता से सोचना हैं, हाई स्कूलों में जो नये परिवर्तन हुए हैं उनको आगे की शिक्षा के लिये उचित प्रबन्ध करना चाहिये। इसमें किसी प्रकार की अड़चनें पैदा न हो, इस प्रकार का मार्ग निकालना निहायत जरूरी है।

अंत में मैं दुबारा यह दोहराना चाहता हूँ, यह निहायत जरूरी है कि पहले हम जब पढ़ते थे, उस समय जो लड़के सच्चरित्र होते थे, अनुशासन में रहने वाले होते थे जो परम्परायें सुन्दर

[श्री श्रीदास गोयल]

रखते थे उनको प्राइजेज दिये जाते थे। उस समय डिबेट्स वगैरह होती थीं। इस तरह से लड़कों को प्रोत्साहित किया जाता था। मैं यह भी निवेदन करूं, धार्मिक विचार धारायें पैदा करना सांस्कृतिक और सामाजिक उच्च विचार सम्बंधी समय समय पर डिबेट्स उच्च शिक्षण संस्थाओं में, हाई स्कूलों और मिडिल स्कूलों में, बड़ी लाभकारी होती हैं। इससे बहुत अच्छी भावना पैदा होकर जीवन में बहुत लाभदायक सिद्ध होती हैं। इसी तरह कालेजों में बड़े बड़े ग्रुप्स जाकर इस प्रकार का वातावरण पैदा करें। मैं ऐसा मानता हूँ कि आज जो कालेज जीवन में खलबली मची हुई है, इन डिसीप्लिन की जो दौड़ लग रही है उसको रोकने के वास्ते बड़ी गम्भीरता से विचार करना चाहिये। नहीं तो हमारे भावी नागरिक, ये विद्यार्थी इनडिसीप्लिन्ड सोल्जर की भांति निकलेंगे। अगर वे इसी रास्ते पर चलते रहे तो यह बड़ा अहितकर होगा समाज और देश के लिए। मैं इस सम्बन्ध में हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि आप इस प्रश्न पर स्वयं विचार करें और ऐसी व्यवस्था करें ताकि भविष्य में निकलने वाले ये नागरिक अनुशासन और समाजिक चेतना से ओत प्रोत होकर निकलें। आज हम द्वितीय पंच वर्षीय योजना की ओर अग्रसर हो रहे हैं हम समाज को सामाजिक पेटर्न की ओर ले जानाचाहते हैं, आज हमें हमारी इस नव प्राप्त स्वतन्त्रता की ओर व्यक्ति स्वतंत्रता का दावा रखते हुए आगे बढ़ना है। इसमें विद्यार्थियों की जिम्मेदारी बहुत अधिक हैं क्योंकि आगे चलकर देश की बागडोर उन्हें सम्भालना है हमें इस प्रकार की नीति शिक्षा की रखनी चाहिये ताकि उन भावी नागरिकों के लिए हितकर साबित हो और हमारे देश के वास्ते।

इसके साथ साथ मैं यह निवेदन किये बिना नही रह सकता कि जो वास्तव में वेतन बृद्धि हुई हैं, उससे सन्तोष तो नहीं है किन्तु यह ठीक है कि जिस हद तक हमारे पासकपड़ा है उसी को काट काट कर हम कपड़े बना सकते हैं, उसी के मुताबिक आज जो हमारा बजट है उसी के मुताबिक वेतन बृद्धि हुई है। बह ठीक है मेरे ख्याल से इसमें थोड़े से सुधार को आवश्यकता थो। मैं आशा करता हूँ जब भो मोका आयेगा इस प्रकार का सुधार जल्दी से किया जाना चाहिये। लेक्चरार का जो ग्रेड २५० से कायम किया गया है वह ठीक है किन्तु जो व्यक्ति दो, तीन, चार साल से काम कर रहे हैं जो २०० से स्केल चालू होता था, उनको अब ग्रेड इनक्रीमेंट मिल कर करीब २४० रुपये हो गये अब जो नये आने वाले हैं वे भी २५० से शुरू होंगे और जो दो चार साल से काम कर रहे हैं उनको भी २५० रुपया मिलेगा यह ज़रा ठीक नहीं है। इस लिए मेरी यह मान्यता है कि जो पुराने लेक्चरार कार्य कर रहे हैं उन्हें एक दो इनक्रीमेंट दिया जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। और उनको भी सन्तोष हो जाता। जहां तक अध्यपकों का प्रश्न है मैं यह निवेदन करूंगा कि आज कल किसी भी अध्यापक से मिलें वह अपने आपको यही कहता पायेगा कि जब तक कोई दूसरी नौकरी नहीं मिल जाती इसी में पड़े हैं और जब दूसरी नौकरी मिल जाती हैं फौरन ट्रांसफर करवा लेते हैं। यह क्यों होता है इस लिये के अध्यापन कार्य में तो कम वेतन मिलता है और दूसरी जगह क्लर्कस वगैरह में जगह मिल जाय तो ज्यादा वेतन मिलता है। इसलिये इस अध्यापक क्लास में कोई आकर्षण नही रहता। और वास्तव में यह ठीक बात भी है कि अध्यापकों के जो ग्रेडस हैं सन्तोषप्रद नहीं है। इस लिए यह कहा जा सकता है कि जिस प्रकार

[श्री श्रीदास गोयल]

एक चपरासी के वेतन में एक रुपये की वृद्धि करते हैं तो लाखों रुपयों का असर पड़ता है उसी प्रकार यदि अध्यापकों के वेतन में वृद्धि होनी है तो लाखों का असर पड़ता है बजट पर। यह ठीक है, मेरा यह निवेदन है कि अगर बजट में इतनी रकम का प्रोवीजन नहीं है तो आप लड़कों पर फीस बढाइये, कालेजों में फीस बढ़ाइये लेकिन यह बात अवश्य ध्यान में रखिये कि प्राइमरो एज्यूकेशन बिल्कुल फ्री हो। और आप अध्यापकों को इतना वेतन दीजिये ताकि वे अपने कुनबे के साथ एक मध्यम श्रेणी के व्यक्ति की तरह जिन्दगी बसर कर सके।

एक बात मैं और निवेदन करूं, मैं इस बात की व्यक्तिगत रूप से जानकारी रखता हूँ कि मौजूदा जो डाइरेक्टर शिक्षा विभाग हैं उनको मैं कई वर्षों से जानता हूँ। उस आधार पर कह सकता हूं ये बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत एफीशियेन्ट हैं। इनके एज्युकेशन डिपार्टमेंट में काम करने से काफी लाभ इस विभाग को हुआ है। और आगे भी होने की पूरी सम्भावना है। मैं आशा करता हूँ कि ये आइ. ए. एस, में आ गये फिर भी ऐसे अनुभवी व्यक्ति को यह विभाग नहीं छोड़ेगा और इनके अनुभवों से फायदा उठाने की कोशिश करेगा। कुछ दिनों से यहां जो सुनने में आ रहा है कि इनका तबादला हो रहा है, लेकिन मेरी यह मान्यता है कि जब हम शिक्षण संस्थाओं में मूलतः परिवर्तन करने जा रहे हैं तो इनका इस विभाग में रहना और इनके अनुभवों का फायदा उठाना इस विभाग के लिए अत्यन्त अनिवार्य है। इस लिए मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि ऐसे अनुभवी डाइरेक्टर को इसी स्थान पर रहने दिया जाय और मुझे आशा है कि वे रह रहे हैं, इस पर गम्भीरता से विचार करेंगे और उनके अनुभव का फायदा उठायेंगे।

अन्त में यह निवेदन करते हुये चेअरमैन महोदय, जिन टेक्स्ट बुक्स के बारे में यहां कहा गया, मैंने भी इक किताबों को देखा जिस प्रकार मेरे मित्र मेहता ने जिक्र किया इन किताब के लिखने वाले ने एक ही जगह नहीं कई जगह ऐसी गल्तियां की हैं। एक जगह तो १३ आने को १० आने फलाने में गलती की है दूसरी जगह तोला माशा के हिसाब में गलती की है। वास्तव में यह देखने से साफ जाहिर होता है कि टेक्स्ट बुक्स के स्वीकार करने में हमें बहुत सतर्कता बरतनी चाहिये पेज दर पेज देखी जानी चाहिये इस तरह से काम के लिए जो कमेटी नियुक्त की है उसमें भी जिम्मेदार व्यक्ति होना बहुत आवश्यक है नहीं तो विद्यार्थियों का बड़ा अहित होगा। इस संबन्ध में एक दिलचस्प और छोटा सा किस्सा है वह भी मैं सुनाना पसंद करूंगा। मेरे घर में भी ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ने जाते हैं उनमें से एक बच्चा जो छटी क्लास में पढ़ता है एक दिन उससे एक सवाल नहीं हुआ। वैसे तो वह बहुत इन्टेलीजेन्ट है किन्तु उस दिन उससे वह सवाल बैठा नहीं तो मैंने उससे कहा ला मुझे दे, मैं तेरे सवाल को हल कर देता हूँ। मैंने उस सवाल को हल किया एक बार नहीं दो बार चार बार लेकिन जब उससे उत्तर को मिलाया तो उत्तर मिला नहीं। मैंने देखा या तो इस किताब लिखने वाले ने भांग पी है या मैं भंग पिये हुये हूँ। There is either Some-thing wrong in my bead or Sone thing wrong in the answer. मैंने इस सवाल को कई बार हल किया, वह का वह उत्तर ही आया। वह उत्तर जो

Page No 64

[श्री श्रीदास गोयल]

उस किताब में दिया था, वास्तव में गलत था। वास्तव में यह गम्भीर बातें हैं इस ओर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिये। आशा है माननीयमंत्री महोदय इस प्रकार की जो गलतियां टेक्स्ट बुक्स में रह गई हैं इनको दुरुस्त करवायेंगे। मेरे से पूर्व, और आज से दस वर्ष पूर्व तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने एक ही गणित की किताब पढ़ी है। वह गणित था चक्रवर्ती का अंकगणित, जो इस मायने में पूरी कम्पलीट बुक है मिडिल क्लास तक के वास्ते। मेरे ख्याल से इससे अच्छी दूसरी पुस्तक गणित की आज तक मुझे देखने में नहीं आई। मैं निवेदन करूं, वैसे मैं गणित में हमेशा अच्छा रहा हूँ, मैंने जब यह देखा कि इन किताबों को बदलने से लाभ क्या हुआ सिवाय कुछ व्यक्ति विशेष को फायदा होने के, जायज या नाजायज। इस फायदे को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाना चाहिये। साथ में जिन लोगों ने इस तरह की किताबें लिख कर विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया है उनके खिलाफ कार्यवाही भी की जानी चाहिये। इस प्रकार या तो इन किताबों में दुरुस्ती करें, नहीं तो इन सारी टेक्स्ट बुक्स का ओवर हाल करना बहुत जरूरी है।

माननीय उपाध्यक्ष गये सेशन में यह आश्वासन दिया गया था कि सवाई माधोपुर में साइन्स की किलासें खोली जायेंगी। अगर ५५ में साइन्स की किलासें खुल जातीं तो कोई कारण नहीं वहां के विद्यार्थी जो साइन्स में रुचि रखते हैं वे या तो इनका ज्ञान प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं या उनको दूसरी जगह जाकर अपना ज्ञान हासिल करना पड़ता है। गये वर्ष जो आश्वासन दिया गया था इस वर्ष तो वह अवश्य पूरा होना चाहिये। इसके साथ साथ में यह भी निवेदन करूंगा कि सवाई माधोपुर की जो स्कूल है उसकी बिल्डिंग की हालत भी बहुत गई गुजरी है वहां यह हालत है कि यदि एक क्लास में कोई पढ़ता है तो दूसरी क्लास में काफी हो हल्ला होता है, काफी डिस्टरबेन्स दूसरी क्लासों को होता है जब कि सरकार काफी रुपया खर्च कर रही है इसलिये इस ओर खास तौर से ध्यान दिया जाना चाहिये। वहां पर जो गर्ल्स मिडिल स्कूल है उसकी भी अच्छी हालत नहीं है ऐसी ऐसी अध्यापिकायें हैं जिनको पांच २ वर्ष पहले ही पेन्शन हो जानी चाहिये थी अभी तक वे ही चली आ रही हैं। इस ओर खास तौर से ध्यान दिया जाना चाहिये। इन के बारे में डिप्टी इन्सपेक्टर एज्युकेशन ने भी यह कहा था कि उनके जुरिसडिक्शन में ऐसी कई अध्यापिकायें हैं जो कि अध्यापिका के स्थान के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इस सम्बंध में कोई पोलिसी निर्धारित की जानी चाहिये या तो उनको पेन्शन दी जाय या अन्य कोई रास्ता अख्त्यार किया जाय। और बालिकाओं की शिक्षा के लिए उपयुक्त पात्रों को ही रखा जावे ताकि उनको शिक्षा ठीक मिल सके, खास तौर से उस हालत में जब कि हम स्त्रीशिक्षा को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। तो यह निहायत जरूरी है कि समाज के आज तक पिछड़े हुये और अब आगे बढ़ाये जाने वाले इस अंग को अच्छी शिक्षा सरकार दिलावे।

श्री लक्ष्मण हीरात—माननीय चेयरमैन महोदय, मेरा कटौती का प्रस्ताव इस प्रकार है कि मांग संख्या ५४ विषय शिक्षा में एक रुपये की कटौती कर दी जावे। माननीय चेयरमैन महोदय, वैसे तो हमारी सरकार आठ नौ वर्षों से शिक्षा के बारे में बहुत कोशिश कर रही है और बजट के

[श्री लक्ष्मण हीरात]

आंकड़ों को देखते हैं तो यही पता लगता है कि हम हर साल आगे होबढ़ते जा रहे हैं।

गत साल की अपेक्षा इस साल एक करोड़ १० लाख रुपया अधिक खर्च इस पर किया जावेगा। यह बड़ी खुशी की बात है। पर जो रकम खर्च कीजाती है वह अधिकतर शहरों की तरफ ही खर्च की जाती है, गांवों की तरफ उतनी नहीं खर्च कीजाती। अधिकतर सदस्यों ने भी यही कहा और मेरा भी ऐसा विश्वास हो गया है कि यह बात सही है। शहरों में हाई स्कूलें, कालेज आदि खोले जाते हैं और गांवों में इसके लिए कोई खास व्यवस्था नहीं है। गांवों में तो मामूली प्राथमिक स्कूलें हैं जहां भी न पूरा सामान है और न पूरे अध्यापक हैं। यहां तक कि बच्चों को बैठने के लिए टाट पटियां भी नहीं हैं और न मास्टरों के बैठने के लिए अच्छी कुर्सियां ही हैं। और स्कूलों का सही और अच्छा रिकार्ड रखने के लिए रजिस्टर आदि भी नहीं हैं, जब कि शहरों में ये सब सहूलियतें भी हैं। तो मैं इस पर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। शहरों में सारे प्रबंध हैं, बैठने के लिए मास्टरों के लिए अच्छी कुर्सियां हैं प्रोफेसरों के लिए कुर्सियां हैं, और लड़कों के लिए भी है। जब कि शहरों में अधिकतर समय इधर उधर आने जाने में लगाते हैं वहां गांवों में अध्यापकगण लड़कों को पढ़ाने के बाद अपना अधिकतर समय ग्राम निर्माण में और ग्राम के रचनात्मक कामों में लगाते हैं।

मास्टरों के वेतन की भी समस्या है। इसको सुधार भी गया है। पर इससे समस्या हल नहीं होगी। इस पर सरकार और ध्यान से सोचे।

इसके अलावा एक समस्या और है। जो आदिवासी एरिया है, पिछड़े क्षेत्र हैं उनमें शहरों के अध्यापक भेज दिये जाते हैं, जो न वहां के लोगों की बोली समझते हैं और न अपनी बोली अच्छी तरह उनको समझा पाते हैं। इससे उनका मन भी वहां नहीं लगता और इससे लड़कों को वे अच्छी तरह पढ़ा भी नहीं पाते हैं। तो इसके बारे में भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। अगर उधर के ही या उसी जिले के अध्यापक वहां भेजे जावेंगे तो वे वहां की बोली भी समझ सकेंगे। और उनका मन भी वहां लगेगा और लड़कों को अच्छी तरह पढ़ा भी सकेंगे।

तो इस तरह चेयरमैन महोदय, जो जो बातें मैंने कहीं हैं उनके बारे में आपके मार्फत में शिक्षा मंत्री महोदय से यही निवेदन करना चाहता हूं कि उन पर वे पूरा ध्यान दें।

हाउस का समय अधिक नहीं लेते हुए इन्हीं शब्दों के साथ में अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री शंभुसिंह—सभापति महोदय, मेरा कटौती का प्रस्ताव इस प्रकार है "मांग संख्या १४, विषय २७ में जो रकम है उसमें एक रुपये की कटौती कर दी जावे।" गंगापुर जिला भीलवाड़ा में हाई स्कूल के प्रश्न पर विचार करने के लिये। माननीय सभापति महोदय, भीलवाड़ा जिले में गंगापुर एक अच्छा आबादी वाला कस्बा है और जिले भर में आबादी के लिहाज से

[श्री शम्भुसिंह]

भीलवाड़ा के बाद उसका दूसरा नम्बर आता है। वहां पर हाई स्कूल खुलवाने के लिए वर्षों से प्रयत्न हो रहे हैं, परन्तु न मालूम क्या वजह है कि बार बार प्रयत्न किये जाने के बाद भी यह काम नहीं हो रहा है। दो दो बार मंत्री महोदयों के आश्वासन भी मिले पर बेकार। यह कस्बा पहले ग्वालियर रियासत में था जब कि वहां एकतन्त्री राज था। इसके बाद राजस्थान का निर्माण हुआ और यह कस्बा इधर आ गया। राजस्थान जनतंत्री राज्य है और एकतंत्री राज्य के मुकाबले में होना वह चाहिए था कि शिक्षा और चिकित्सा आदि की सुविधायें अधिक बढ़तीं, पर देखा यह जा रहा है कि जो एकतन्त्री राज्य में हालत थी और विकास उसका हो रहा था वह भी राजस्थान होने के बाद रुक गया है। वहां ग्वालियर रियासत के समय से जो मिडिल स्कूल था वही उसी हालत में आज भी चला आ रहा है। वहां सब जगहों की हालत देखते हुये कभी की हाई स्कूल हो जानी चाहिये थी पर सरकार की उसी क्षेत्र की तरफ उपेक्षा दृष्टि होने की वजह से वह कस्बा उपेक्षित ही रहा है। वहां हाई स्कूल के लिए वहां के लोगों ने भवन का निर्माण भी कर दिया है और वह लगभग तैयार है। गंगापुर में आज के हमारे मुख्यमंत्रीजी, जो पहले राजस्व मंत्री थे तीन चार साल पहले वहां तशरीफ लाये थे और बिल्डिंग बनने के बाद सबसे पहले तशरीफ लाने वाले मंत्रियों में से हैं। उन्होंने भी बिल्डिंग को देखा और वहां हाई स्कूल खोले जाने की जरूरत को महसूस किया और आश्वासन भी दिया। यही बात भूतपूर्व शिक्षा मंत्रीजी ने भी कही जब कि वे वहां स्वयं पधारे थे। उन्होंने भी बिल्डिंग को देखा और अनुभव किया कि वहां हाई स्कूल खुलना चाहिये परन्तु न मालूम क्या वजह है कि वहां अभी तक स्कूल नहीं खुल पाया है।

(घंटी)

जब पिछले साल भीलवाड़ा जिले में हाई स्कूल खुलने के स्थान तय हुए थे तब भी वहां हाई स्कूल खुलने वाला था, पर वहां न खोलकर बाद में मांडलगढ़ में खोल दिया गया। वहां खोला गया इससे हमें नाराजगी नहीं है, खुशी ही है। पर गंगापुर में क्यों नहीं खुला यह हमारी समझ में नहीं आ रहा है। वहां आसपास में पोटला में, कोशीथल में मिडिल स्कूलें हैं। और भी आसपास में मिडिल स्कूलें हैं। और इन स्कूलों से निकलने वाले विद्यार्थी बहुत हैं जो गंगापुर में हाई स्कूल के लिये उपलब्ध हो सकते हैं और काफी संख्या में उपलब्ध हो सकते हैं, और इन मिडिल स्कूलों के विद्यार्थियों को लेने के वास्ते गंगापुर में हाई स्कूल खोले जाने को बड़ी भारी आवश्यकता है।

गंगापुर में हाई स्कूल खोलने के वास्ते अब यह एक प्रश्न किया जा रहा है कि वहां पर हाई स्कूल चलाने के वास्ते जनता एक अमुक राशि दे तब वहां हाई स्कूल खोला जा सकता है, । ऐसा सुना गया है। यह कितनी बुरी बात है कि एक कल्याणकारी राज्य की तरफ से शिक्षा जैसे कार्य के चलाने के वास्ते जनता से पैसा मांगा जाय और उनके सामने यह शर्त रखी जाय कि इतना पैसा दो तो तुम्हारे लिए स्कूल और शिक्षा का प्रबन्ध करेंगे। लेकिन जैसा कि गांव की शिक्षा

[श्री शम्भुसिंह]

के बारे में रवैया रहा है उसको देखते हुए यह कोई ताज्जुब जैसी बात नहीं है। शहरों में सरकार विद्यालय खोल रही है और जहां जरूरत नहीं है वहां विद्यालय खोल रही है, मगर गांवों में हाई स्कूल की जरूरत होती है तो वहां नहीं खोलते हैं, और वहां हाई स्कूल खोलने के वास्ते पैसा मांगा जाता हैं।

उदयपुर में कृषि कालेज खोल दिया गया और वह वहां काम कर रहा है। इसके वास्ते सरकार ने काफी दिलचस्पी दिखाई। तो क्या वजह है कि शहरों में ही सरकार दिलचस्पी दिखाती और गावों में इस प्रकार का उपेक्षापूर्ण रवैया अख्त्यार करे। इसके वास्ते कुछ लोगों का यह खयाल हुआ कि कुछ कांग्रेस के सज्जनों का डेपुटेशन संबंधित मंत्रीजी से मिले।....

(श्री अध्यक्ष पुन; पीठासीन)

तो शायद वे इस बात पर ध्यान दें। तो हमने यह प्रबन्ध किया कि कुछ कांग्रेसी मित्रों का डेपुटेशन यहां भेजा, लेकिन फिर भी दुर्भाग्य है कि अभी तक गंगापुर में हाई स्कूल नहीं खुल पाया। इसके वास्ते बारबार यहां प्रश्न पूछे गये, कटमोशन्स भी रक्खे गये और रिप्रेजेन्टेशन्स भी किये गये, मगर अभी तक वहां पर हाई स्कूल नहीं खुल पाया है।

अब गंगापुर में हाई स्कूल ही नहीं बल्कि इन्टर कॉलेज की भी आवश्यकता है। भीलवाड़े में डिग्री कॉलेज जल्दी खुल जाना चाहिए और भीलवाड़े के नजदीक ही गंगापुर में हाई स्कूल बहुत जल्दी खुल जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद डिग्री कालेज भीलवाड़े में खुलकर वहां इन्टर कॉलेज खुल जाना चाहिए। अब यदि गंगापुर में इसी वर्ष हाई स्कूल नहीं खुल पायेगा तो इसके वास्ते क्या यह समझा जा सकता है कि अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी जो कि शिक्षा मंत्री भी हैं, वे इस सदन में उनके ऊपर क्षेत्रीय भावना का आरोप लगाने से और क्षेत्रीय भावनाओं की आलोचना करने से शायद इतने डर गये हैं कि उदयपुर डिविजन में अब वे कोई स्कूल जल्दी खोलना नहीं चाहते। मगर मैं समझता हूं कि न तो उनमें क्षेत्रीय भावना है और न वे क्षेत्रीय भावनाओं की आलोचनाओं से डरने वाले हैं। इस वास्ते वे बगैर किसी बात का लिहाज किये उदयपुर डिविजन में गंगापुर का कस्बा है वहां शीघ्र से शीघ्र हाई स्कूल खोल देने की कृपा करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना कट मोशन सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष—श्री जगतसिंह झाला।

श्री जगतसिंह झाला—माननीय अध्यक्ष, मेरा कटोती प्रस्ताव इस प्रकार है—

"मांग संख्या १४, विषय ३७ शिक्षा में १) रु० की कटोती की जाय (भूपाल नोबल्स इन्टर कॉलेज, उदयपुर, को सरकारी सहायता नहीं देने पर बहस करने के लिए)"

[श्री जगतसिंह झाला]

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह संस्था ३० वर्षों से उदयपुर में जनता की सेवा कर रही है। यह चार साल से इन्टर कॉलेज बना दिया गया है लेकिन आजतक कोई सहायता नहीं दी गई। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री जी पर जो यह आरोप लगाया जाता है कि इनमें क्षेत्रीय भावना है, लेकिन यह बात तो यहां देखने को नहीं मिलती है। लेकिन जयपुर के अन्दर दो हाई स्कूल इन्टरमीजिऐट कालेज इसके बाद में बने हैं, सुबोध इन्टर कॉलेज और अग्रवाल कॉलेज, उन दोनों कॉलेज को सहायता दे दी गई है, लेकिन हमारे इस कालेज को सहायता नही दी गई है। इसलिए मेरा आक्षेप इन पर दूसरा है। वह यह है कि वे अपनी पार्टी के लोगों को प्रसन्न करने के लिए उदयपुर की जनता में वे उनकी संस्थाओं को उदयपुर के दूसरी संस्थाओं से ज्यादा सहायता देते हैं। और इस स्कूल को नहीं देना चाहते। यह मेरा खुला आक्षेप है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे वहां राजनैतिक कार्यकर्ता उन प्राइवेट संस्थाओं में काम करते हैं जिनको हजारों रुपयों की सहायता माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दी है और हमारे इस स्कूल को कोई सहायता नहीं दे रहे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विद्या भवन, विद्यापीठ, महिला विद्यालय और राजस्थान महिला पाठशाला, इन सब को सैंकड़ों हजारों रुपयों की सहायता दी गई हैं और इस स्कूल को जब कि हम एक दफा नहीं सैंकड़ों दफा उनको निवेदन कर चुके हैं, पत्रों द्वारा और डेपुटेशन द्वारा सहायता नहीं दे रहे हैं। हमने उदयपुर में भी माननीय मुख्य मंत्री जी के पास जाकर डेपुटेशन में निवेदन किया, और यहां पर उस स्कूल के प्रिन्सीपल और सेक्रेटरी महोदय आये और एक दफा नहीं कई दफा आगये और महीनों उसके बारे में ठहर कर निवेदन किया, लेकिन दो साल का अर्सा होगया इस स्कूल को कोई भी सहायता नहीं दी गई है। एक तरफ, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, कि जहां विद्या भवन को इस बजट के अन्दर २॥ लाख की रकम बगैर ब्याज के ३० वर्षों में चुकाने पर मिलने की हालत में सहायता दी गई है। भवन निर्माण के लिए वहां इस स्कूल को कुछ भी सहायता नहीं दी जाती है। यह खुला पक्षपात है और यह कहा जायगा कि राजनीति को शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय में भी लादना चाहते हैं। ऐसी चीज न हो यह हम क्यों माने जब कि बार बार सहायता का वचन दिया गया है, आपने कहा है कि सहायता देंगे, अग्रवाल कालेज और सुबोध कालेज को सहायता देते हैं, महाराणा भूपाल इन्टर कालेज को सहायता नहीं देते हैं। भूपाल नोबल्स इन्टर कालेज कोई जागीरदारों की संस्था नहीं है, वह केवल जागीरदारों के लिए ही नहीं है। इसको १०साल पूर्व ही पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया है और चार साल का अर्सा होगया है कि उसका बोर्डिंग हाउस भी पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया है, लेकिन आपकी इस स्कूल पर दुर्भावना है, इसलिए कतई भी सहायता नहीं देते हैं। मैंने केवल आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करने के लिए यह कटौती का प्रस्ताव रखा है, लेकिन मैं आशा करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी अवश्य ही इस पर ध्यान देकर हमारे इस स्कूल को सहायता देने का वचन देंगे। मैं केवल इतना ही कहकर अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—श्री मानसिंह महार।

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष, शिक्षा विभाग के विषय में मेरे ७ कटौती

[श्री मानसिंह महार]

के प्रस्ताव हैं। सदन के समक्ष में अपने कटौती प्रस्ताव करते हुए, अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले में जो कहना चाहता हूँ वह है कि मेरा जो १२४ नम्बर का कटौती का प्रस्ताव है जिसमें है कि "that the Demand No. 14. Major head 37-Education be reduced by Re. 1 (To discuss the failure of Govt. to start new High and Middle Schools in Tehils Jamua Ramgarh and Amber)."

माननीय अध्यक्ष, जयपुर जिले के अन्दर जिस प्रकार की नीति इन दो तहसीलों के बारे में बरती गई; आमेर तहसील के दो टुकड़े हो गये हैं, ए और बी, मैं बी क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूँ, यानी आमेर बी और जमुआ रामगढ़ के बारे में वह पक्षपातपूर्ण नीति बरती गई है। वह सर्वथा अनुचित है। जमुआ रामगढ़ एक बहुत बड़ी तहसील है। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि किशनगढ़ की दो तहसीलों, सरवाड़ और अराई को मिला लीजिये चाहे किशनगढ़ और सरवाड़ को मिला लीजिये, मैं तो यहां तक कहता हूँ कि कुछ लिहाज से किशनगढ़, सरवाड़ और अराई, इन तीनों को मिलाकर जमुआ रामगढ़ के बराबर कर सकते हैं। इतनी बड़ी तहसील होते हुए भी आज तक वहां कोई हाई स्कूल नहीं है। पूरी तहसील भर के अन्दर कोई हाई स्कूल न होना एक बड़े अन्याय की बात है। और तहसीलों में जहां कि कांग्रेस पक्ष के आदमियों को वोट दिये गये थे वहां पर तरह तरह के हाई स्कूल्स वगैरा खोल दिये हैं। और अब भी मैं आशा करूंगा क्योंकि मैं भी उसी कोड़ में आ गया हूं इसलिए मेरे क्षेत्र में भी एक दो हाई स्कूल खोलने की सरकार महरबानी फरमाये। जमुआ रामगढ़ वह तहसील है जिसका पिछले तीन वर्षों से वादा हो रहा है अध्यक्ष महोदय, कि वहां हाई स्कूल खोल दी जावेगी, वहां पर दो तीन जगह तो बिल्डिंग्स बन कर तैयार हो गई हैं हाई स्कूल के लिए, गांव वालों ने अपने पास से पैसा इकट्ठा करके, उस पैसे से बिल्डिंग्स बना कर खड़ी कर दीं उसके बावजूद भी हमारे प्रति अन्याय हुआ है।

उसी प्रकार मैं सामोद की मिसाल सदन के समक्ष रखूंगा। पिछले वर्ष शिक्षा विभाग के डिप्टी इन्सपेक्टर वहां गये थे, उन्होंने जनता से कहा कि आप दो हजार रुपया फौरन जमा करा दो बैंक में हाई स्कूल खुलवाने के लिए, यह राइटिंग में मौजूद है अध्यक्ष महोदय। वहां के बेचारे कार्यकर्ताओं ने वे रुपये जमा कर दिये और जब रुपया जमा हो गया और हाई स्कूल के खोलने की बात आयी तो कहा कि अब के हमारी लिस्ट में हवाला नहीं हैं, इसलिए नहीं खोल सकते। अगर अगले वर्ष भी नहीं खुलेगा तो जनता से जो दो हजार रुपये ले लिये उनका क्या होगा? इस बात की बड़ी चर्चा है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह फरमाया था कि हाई स्कूल खोलने में पैसा नहीं लेंगे तो वे दो हजार रुपये सामोद वाले सार्वजनिक काम में लगावेंगे, उसको स्कूल बिल्डिंग में लगादेंगे। सामोद, जमुआ रामगढ़ और अचरोल में तीन चार हाई स्कूल नहीं तो इतना जरूर है कि इस इलाके में हाई स्कूल हो इससे अधिक मैं क्या निवेदन करूं। यह मेरी व्यक्तिगत मांग है इसलिए जोर देकर मांग करता हूं। तो एक कटौती प्रस्ताव तो यह था।

दूसरा कटौती प्रस्ताव जो है अध्यक्ष महोदय, वह इस प्रकार है।

"To discuss appointment of Divisional Director",

Page No 70

[श्री मानसिंह महार]

मानननीय अध्यक्ष, कुछ दिनों पूर्व इधर उधर होस्टल में घूमते हुए मैंने यह सुना कि शिक्षा विभाग में बड़ा भारी परिवर्तन होने जा रहा है, बड़ा सुधार होने वाला है तो मैंने यह आशा की कि वाकई माननीय मुख्य मंत्रीजी को समय मिल गया होगा, इस ओर ध्यान देने का और बहुत बड़ा काम होगा, तो थोड़े दिन बाद मालूम हुआ कि वह महत्वपूर्ण काम यह हुआ कि उस विभाग में एक एडीश्नल डायरेक्टर और चिपका दिये गये। एडीश्नल डायरेक्टर और डायरेक्टर का तरीके से काम का बंटवारा हो जाता तो किसी हद तक उचित मानते। लेकिन आपके द्वारा येन केन प्रकारेण डायरेक्टर शिक्षा विभाग को हटाने की तजवीज है उसको अमल में न लेकर के और दूसरी तरह इस तरह लगा अध्यक्ष महोदय, मै यह नहीं कहता कि मुख्य मंत्रीजी की ऐसी नीयत हो, उनकी गलती हो सकती है, ओर्डर में इधर उधर शब्द हो गये हों, डायरेक्टर को कठपुतली सा बना दिया गया है, उनको कोई पावर्स नहीं रहे। डायरेक्टर का केवल यह काम रहा कि शिक्षा संस्थाओं में भ्रमण करो, हिन्दू धर्म में एक तरह साधू बना दिये जाते हैं, उसी तरह से उनको कर दिया। आपके किसी अध्यापक की अगर कोई शिकायत हैं तो डायरेक्टर उसको निकाल नहीं सकता, इन्तजामी मामले में शिकायत हो तो वह कुछ नहीं कर सकता। वह तो रिपोर्ट भेज दे ऐडीश्नल डायरेक्टर को। अगर एडीश्नल डायरेक्टर का यह काम होता है तो उसको उचित भी मानते लेकिन डायरेक्टर को यह काम दे दिया कि वह उस के पास रिपोर्ट भेजे। उसको हटाना न हटाना एडीश्नल डायरेक्टर की मर्जी पर है। यह एक प्रकार का अन्याय होगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी ऐसी गलती तो नहीं करते हैं, एक स्लिप ऑफ पेन हो जाता है, इसको मैं मान कर चलता हूं। मैं आशा करता हूं कि यह काम जो हो गया है वह गलत हो गया है, नीचे से नोट गलत पुट अप हो गया होगा इसको सुधारने की कोशिश करें।

तीसरी बात यह है कि राजस्थान में अनिश्चित काल से यह बात चली आ रही है कि डायरेक्टर का तबादला हो रहा है, बार बार सुनने में भी और चर्चा में भी आया, न तबादला होता है, अखबारों में आया और हमारे नवयुग में जिसको मैं सरकारी गजट मानता हूं उसने एक दिन यह लिखा कि डी. के. बनर्जी दिल्ली से डायरेक्टर होकर आ रहे हैं। मैंने सुना कि वे नट गये कि मैं राजस्थान में तो डायरेक्टर के पद पर नहीं आऊंगा। सुना है बाहर से आदमी बुलाने के पक्ष में मैं नहीं हूँ। राजस्थान के आदमियों को ही रखें। जयपुर का एक तो हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट है और फिर उसके पावर्स भी छीन रहे हैं और फिर हटाने को कहते है तो जयपुर को आघात पहुँचता है और कम से कम मेरे को भी।

(हंसी)

जयपुर की भावना पर कुठाराघात जरूर होता है। आपकी जानकारी का सवाल है, इस पर भी यह शिकंजे जमाना चाहें, इसलिये मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, करेंगे तो वे चाहेंगे जो ही। हमारी भावना की नागवारी प्रकट करना चाहते है और आज यह मौका है। हमारे डायरेक्टर हैं उनको रखना है तो साल दो साल का एक्स्टेन्शन देकर रखें ताकि हम लोगो को और उनके भी दिमाग में यह हो कि मैं रहूंगा। यह जो वातावरण बन रहा है पूरे दो वर्ष से

(श्री मानसिंह महार]

कि डायरेक्टर चले, डायरेक्टर चले, इससे शिक्षा विभाग को नुकसान हो रहा है। यहबात हो तो यह मुख्य मंत्रीजी के लिए अच्छी नहीं। मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी जितनी गारंटी दे सके दें, इधर उधर को बातें कहें तो वह बात अलग है। हां, अगर इसको बदलना है तो बदलें, अगर अयोग्य हो तो बदल दें, लेकिन जब योग्य है और अक्सपीरियन्सड है तो क्यों ? अखबारों में यह छाप देना कि डो० के. बनर्जी आ रहे हैं, यह तो और भी मामले को पेचीदा बना देता है। दूसरे कटौती के प्रस्ताव के बारे में यही निवेदन था कि एडीशनल डायरेक्टर से डायरेक्टर को अधिक पावर्स होने चाहिए और वर्तमान डायरेक्टर के एक्सपीरियन्स को देखकर और जयपुर के मोह को को देखकर भी। आई. ए. एस, में भी ट्रेनिंग में भेजना है तो जलेबी चौक में थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट को भेजना है, तो यहां तो साल दो साल बाद भी आ सकते हैं, ट्रेनिंग ही करानी है तो साल दो साल और कोई एडीशनल रख लो, करा देना जल्दी नहीं है। यह मेरा छोटा सा निवेदन है। हालांकि यह बात जरूर कह दूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी इस बात की ताईद करेंगे कि वर्तमान डायरेक्टर का मैं समर्थक नहीं हूं, लेकिन जहां न्याय की बात हो तो कहना पड़ता है। मुख्य मंत्री पर यह लोग आक्षेप करें तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है। मैं समझता हूं कि स्पेसिफिक जवाब तो हो ही जायगा। जवाब की टालमटूली और हमें आप पूरी तरह नाराज करते हैं, यह नहीं करते हैं कि इन बेचारों को जवाब तो दें।

तीसरी बात है कि to "discuss the unsatisfactory pay scales of teachers."

माननीय अध्यक्ष—इसके बारे में मेरे मित्र ने बहुत कुछ कहा है। मैं ज्यादा क्या दोहराऊं यही निवेदन करूंगा कि हमारे यहां के बच्चों की पढ़ाई के लिये जो मास्टर रखे जांय उनको आप जितना अधिक दे सकते हैं उतना ही थोड़ा है। फिर भी हम यह आशा करके चलते हैं कि वर्तमान पे स्केल्स और बाद में रिवाइज्ड पे स्केल्स जो रखी है वे एल. डी. सीज. से भी कम है और यह बात बहुत अनुचित है। मैं सरकार से आशा करता हूं कि वे शिक्षा विभाग के मास्टरों की तनख्वाहों के बारे में विचार करेंगे। इस सिलसिले में एक बात यह निवेदन करूं कि मास्टरों के साथ यह अन्याय हो रहा है कि पुराने मास्टर हैं वे पुरानी ग्रेडस के हिसाब से कम तनख्वाह पा रहे हैं और उसी क्वालिफिकेशन के जो नये मास्टर रखे जाते हैं उनको नयी तनख्वाएं दी जाती हैं।

इसके अलावा मैं एक ड्राइंग मास्टर की मिसाल लाया हूँ। मैं यह नहीं कहता कि कुछ सिफारिश के कारण असंतोष का काम हो जाता है। एक सतोषकुमार है जो जुलाई ५५ में मॉडल स्कूल, जयपुर में अपोइन्ट हुए हैं। वे मैट्रिक पास है और बम्बई से ड्राइंग का इम्तहान देकर आये। ४, ६ महीना रहने के बाद उनको महाराजा मल्टी परपज हाई स्कूल में हायर ग्रेड ७०. ४. ६० में ट्रान्सफर किया जाता है, ट्रान्सफर कर दिया तो कर दिया कोई बात नहीं लेकिन बम्बई का जो ड्राइंग का डिप्लोमा पास है उनसे भी अधिक योग्यता वाले और उनसे सर्विस में पुराने मास्टर उसी

[श्री मानसिंह महार]

मिडिल स्कूल में है उनको नहीं लिया गया। एक्सपीरिएन्स का ध्यान रखा जाय तो अच्छा हो। इस प्रकार की बातें असंतोष पैदा करती है।

आप ग्रेडस के बारे में और विचार करें। जो थोड़ा बहुत किया उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम नहीं कहते कि कुछ नहीं किया, समथिंग इज बेटर देन नथिंग और बढ़ायेंगे लेकिन राजस्थान में गुंजाइश है चाहें तो बढ़ा सकते हैं। यहां ओफिसर्स के लिये नयी पोस्ट्स कायम हो जाती हैं, चाहे पैसा हो या न हो।

मेरा अगला कटौती का प्रस्ताव है प्रिंसिपल्स के बारे में, प्रिंसिपल्स को इतना ऊंचा ग्रेड दिया जाता है! मैं निवेदन करूं कि जो नये पे स्केल्स आये हैं, यह मैं मेरे अगले कटौती प्रस्ताव पर बोल रहा हूँ, उसके अन्दर कालेज के प्रिंसिपल्स के ग्रेड पहले जो ५०० से ७०० तक के थे उसके बजाय-अब बढ़ाकर ७०० से १२०० तक के कर दिये। यह जरा अटपटासा महसूस होता है। जिस की तनख्वाह ७००पर खत्म हो जाती थी, उसका स्टार्ट अब ७०० पर कर दिया जाता है। करिये पैसा है आपके पास तो करने में हर्ज नहीं है लेकिन नीचे के तबके का जब बढ़ाने के लिये कहते हैं तो आपके सामने पैसे का प्रश्न आ जाता है लेकिन प्रिंसिपल्स का सवाल आता है तो उनका वेतन इतना बढ़ा देते हैं। उनका ६०० से १००० का कर देते तो भी काम चल जाता। इतने वेतन पर भी बहुत अच्छे आदमी मिल जाते हैं। मैं मुख्य मन्त्री जी पर आक्षेप नहीं करता। प्रपोजल बनते समय उनमें से कोई पहुँच गया होगा और बनाने वाले उनके शिष्य ही तो थे। मैं भी यदि महाराजा कालेज के प्रिंसिपल साहब के खिलाफ कहूँ तो अच्छा नहीं है, क्यों कि मैं भी उनका शिष्य हूं। लेकिन ७०० से १२०० तक करना मैं कुछ हद तक अन्याय पूर्ण मानता हूँ। अगर वाजिब हो तो कम करिये, थोड़ा ध्यान इधर दे दीजिये।

एक बात और कहूँगा, अध्यक्ष महोदय, प्रिंसिपल्स का जिक्र आया है. कालेज का मुझे कुछ तजुर्बा है इस लिये कहता हूं कि जब आप प्रिंसिपल्स को सिलेक्ट करें तब आप इस बात का ध्यान रखें कि वे स्पोर्टिंग एक्टिविटीज और सोशियल एक्टिविटीज पर ध्यान दें, ऐसे प्रिंसिपल्स को सिलेक्ट करें तो अच्छा हो। यदि प्रिंसिपल महोदय स्पोर्ट्स आदि में इन्टेरेस्ट लेते है तो स्पोर्ट्स में उत्साह बढ़ेगा। स्पोर्ट्समेन पढ़ाई लिखाई में निल होते हैं ऐसी बात नहीं है। यदि इस ओर थोड़ा ध्यान दिया जाय तो अच्छा होगा। आज राजस्थान में स्पोर्ट्स की क्या हालत है यह आप से छिपी हुई नहीं है। यहां के लोग किसी भी खेल को ले लीजिये, बहुत पिछड़े हुए हैं। हिन्दुस्तान की किसी भी टीम में राजस्थान का एक भी खिलाड़ी नहीं है। मुख्य मन्त्री भी नहीं चाहेंगे कि ऐसी बात रहे। मैं समझता हूँ स्पोर्ट्स की तरक्की की जायगी तो अच्छा होगा। प्रिंसिपल्स के वेतन की ओर भी ध्यान दिया जाय।

अब में संस्कृत टीचर्स के वेतन के बारे में जो मेरा कटोती प्रस्ताव है उसके बारे में कुछ कहूंगा। राजस्थान में संस्कृत टीचर्स के साथ बड़ा भारी अन्याय किया जा रहा है। यह क्यो हो रहा

[श्री मानसिंह महार]

है । कभी संस्कृत की किसी डिग्री को मान्यता दी जाती है और साल दो साल के बाद कोई इधर उधर की बात होती है, न मालूम क्यों, तो उस डिग्री की मान्यता नहीं रखी जाती है, उठा दी जाती है । इस प्रकार के कई उदाहरण हैं । बेचारे संस्कृत टीचर्स को पे स्केल्स मिल रही हैं वे बहुत ही मीगर हैं । संस्कृत पाठशालाओं की गिनती तो राजस्थान में है ही नहीं और अगर एक दो टूटी फूटी हैं तो उसमें ग्रेड ग्रेड इतना कम देते है कि जो नहीं के बराबर है । तो संस्कृत के विषय में हमको यह तय करके चलना है कि यह एक ऐसी भाषा है जिसको जितना प्रोत्साहन दे सकते हैं, देना चाहिये । यदि आज भी हम इसको प्रोत्साहन नहीं दे पायेंगे तो क्या अंग्रेजी के जमाने में हम आशा करते थे कि उनको बढ़ावा मिलता । हमारे यहां संस्कृत के हायर ट्रेनिंग की व्यवस्था है लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि जयपुर संस्कृत कालेज के प्रिन्सिपल को आपसी किट किट के कारण अस्तीफा देना पड़ा । हमारी संस्कृत कालेज का पहले शर्माजी के टाइम में जो स्टेन्डर्ड था वह अब गिरता ही जा रहा है । संस्कृत कालेज की जो सही पोजिशन होनी चाहिये वह हमारे यहां नहीं है । सरकार को संस्कृत कालेज के अध्यापकों और संस्कृत पाठशालाओं के अध्यापकों को अंग्रेजी माध्यम की स्कूलों के अध्यापकों के बराबर वेतन देने का मौका देना चाहिये । यह नहीं होना चाहिये कि संस्कृत पाठशालाओं के मास्टरों की कम तनख्वा हो और दूसरों की ज्यादा हो । इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये । संस्कृत का पठन पाठन अंग्रेजी हिन्दी के पठन पाठन की अपेक्षा अधिक कठिन है । अंग्रेजी हिन्दी तो आसानी से पढ़ सकते हैं लेकिन संस्कृत की मेरे सामने किताब रखी गई उसको पढ़ना मुश्किल हो गया । यह तो विद्वानों की भाषा है । इसके लिये तो दूसरों की बनिस्पत २,४ रु० बेसी रखने चाहिये । मेट्रिक के बराबर संस्कृत की उपाधि उसके इक्वेलेन्ट हो तो उसको २,४ रू० अधिक मिलने चाहिये । उनके लिये विशेष ध्यान देना चाहिये । मैं आशा करता हूं कि संस्कृत की डिग्रियों को एक साल मान्यता देते है और दूसरी साल कैंसिल कर देते हैं, इस प्रकार की पालिसी है उस की ओर ध्यान देना चाहिये ।

एक कटौती प्रस्ताव मेरा स्पेसिफिक हैं । वह है तहसील जमुआ रामगढ़ और बैराठ को जयपुर के इन्स्पेक्टर ओफ स्कूल्स के नीचे नहीं रख कर किशनगढ़ के इंसपेक्टर के नीचे रखना अनुचित है । इन स्थानों में से किसी भी स्थान से आने वाले व्यक्ति को पहले जयपुर आकर किशनगढ़ जाना पड़ता है और इसमें उसको बहुत खर्चा करना पड़ता है, जयपुर आये बिना किशनगढ नहीं जाया जा सकता । जमुआ रामगढ तो जयपुर से १५. २० मील के फासले पर ही है । यदि जयपुर में इन्सपेक्टर नहीं हो और उस हालत में इनको किशनगढ़ के नीचे रखा जाय तब तो कोई बात नहीं है लेकिन जयपुर में इन्सपेक्टर होने के बावजूद भी जमुवा रामगढ़ को किशनगढ़ के नीचे किया गया यह ठीक नहीं है । शायद किसी का सुझाव नहीं होगा और किशनगढ़ में नया इन्सपेक्टर कायम हुआ इस लिए लगा दिया गया होगा । लेकिन अब उसे ठीक कर लिया जाना चाहिये । और यह तो हर हालत में उपयुक्त है कि उनको जयपुर के इंसपेक्टर के नीचे लगाया जावे । कोई भी यह कह नहीं सकता कि यह अनुचित है । यह तो मेरी एक ऐसी मांग है जिसको मैं कह सकता हूँ कि यह मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है । इस लिए इस पर मैं ज्यादा जोर नहीं देकर कहूँगा कि आप इस पर विचार करेंगे । अगर इन दोनों तहसीलों को जयपुर के इंसपेक्टर ओफ स्कूल के

Page No 74

[redacted]

[श्री मानसिंह महार]

नीचे लगा दिया जावे तो उन लोगों के १०), १०) आने जाने में लग जाते हैं, बच जावेंगे और जो आने जाने की दिक्कत होती है उससे भी बच जावेंगे।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूँ कि किशनगढ़ में इंसपेक्टर रह सकता है। लेकिन मैं यह कहूंगा कि हर एक कर्मचारी अपने मकान के नजदीक रहने की कोशिश करता है। इसलिए अगर आप आमेर के रहने वाले को बैराठ और बैराठ के रहने वाले को आमेर भेजते हैं तो उन दोनों को ही बड़ी दिक्कत हो जाती है। इस लिए मैंने यह निवेदन किया है कि इनको दोनों तहसीलों को जयपुर इंसपेक्टर ओफ स्कूल के नीचे लगा दिया जावे। एक तो मेरा कटौती का प्रस्ताव इस बारे में है।

दूसरा मेरा कटौती का प्रस्ताव है अध्यक्ष महोदय, "to discuss the step--motherly treatment shown by the Department to rural areas in the matter of opening new schools."

माननीय अध्यक्ष, यह एक ऐसा मामला है जिसको सदन के समक्ष रखते हुए मुझे दुःख होता है। एक टेन्डेन्सी वर्षों से चली आ रही है कि गांव को इतने साधन नहीं दिये जावें जितने की शहरों और कस्बों को दिये जाते हैं। आज भी आप देख लीजिये, अभी पिछले वर्ष मैंने जयपुर शहर में देखा, सी. स्कीम में सरकार की तरफ से प्राइमरी स्कूल खुला। उनसे सरकार ने बिल्डिंग की कोई मांग नहीं की थी। सी. स्कीम ऐसी जगह है और जहां ऐसे मालदार लोग रहते हैं कि अगर सरकार कहती कि चन्दा देकर बिल्डिंग बनाए तो मैं यह कहूंगा कि एक स्कूल नहीं, एक रात में दो स्कूल बिल्डिंग खड़े हो सकते थे।

मगर जयपुर में यह मांग कैसे हो सकती है। बाहर के लोगों का तो यहां पर कोई असर नही, यहां के लोगों का तो यहां असर है इसलिये यह मांग कैसे की जा सकती है? एक मिनिस्टर होगया और दूसरा डिप्टी मिनिस्टर हो गया और एक ऊंचे ओहदे पर जा रहे हैं। इसलिये मैं यह कहूँगा कि गांव वालों की यहां पर पहुंच बहुत कम है, इस लिये उनकी तरफ आप ज्यादा ध्यान दीजिये। मैं तो यह समझता हूं कि मंत्रियों की ऐसी बदनियती नहीं है कि गांवों के साथ अलग वर्ताव किया जावे। जयपुर से दो मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर आये। एक एडवोकेट जनरल होने जा रहे हैं। हमे इससे कोई इर्ष्या, नहीं हम तो उल्टे इससे खुश होते है कि हमारा एक मित्र ऊंचा पहुँच रहा है। इससे हमको तो खुशी है। मगर ऐसी बातें होती हैं तो लोग गांवों में चर्चा करते है कि जब हम गांवों में प्राइमरी स्कूल खोलने की मांग करते है तो हमसे आधा पैसा सरकार कम से कम चाहती है। अध्यक्ष महोदय कहीं कहीं पूरा पैसा भी मांगा जाता है। यह कहा जाता है कि बिलडिंग का इन्तजाम कर लो फिर हम प्राइमरी स्कूल का इन्तजाम कर देंगे। जयपुर में बिलडिंग के प्रबन्ध के लिये कोई मांग नहीं की जाती और न आप यह कहते है कि बिल्डिंग होगा तो प्रबन्ध किया जाएगा। इसलिये मैं यह निवेदन करुंगा कि आपको सबके लिये बराबर रुपया खर्च करना चाहिये। जयपुर में बिल्डिंग

[श्री मानसिंह मद्दार]

का इन्तजाम आप खुद इस लिये कर देते है कि यहां के रहने वाले और सदस्य आपके बहुत नजदीक होने से आपको आ कर कह सकते हैं और हम गांव के रहने वाले आपके पास आकर कह नहीं सकते।

(घंटी)

यह तो हम गांव वालों के जीवन मरण का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि यहां पर सब लोग बैठे हैं वे कहेंगे कि हम सब गांव वाले हैं, मैं समझता हूँ कि वे भी अपनी जबान खोलेंगे। वे लोग गांव वालों के वोट लेकर यहां आ जाते हैं और उनके दुख दर्द की चिन्ता नहीं करते। इस लिये मुझे निवेदन करना पड़ता है कि गांवों में स्कूल खोले जावें, उसके लिये भी वहां की पब्लिक से किसी प्रकार का पैसा नहीं लिया जावे और अगर आप लेते हैं गांव वालों से तो आपको शहर वालों से भी लेना चाहिये। क्या बात होती है जब कभी होस्पिटल खोलने की बात होती है तो आप कहते हैं कि बिल्डिंग दें। आयुर्वेदिक औषधालय खोलें तो कहते हैं कि बिल्डिंग दें। मैं यह साफ आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप गांव वालों को भुलावे में रखेंगे तो इसका परिणाम अच्छा नहीं रहेगा। यह बात मैं निश्चित सोच कर चलता हूँ।

अब अध्यक्ष महोदय, टैक्स्ट बुकों के बारे में बहुत चर्चा हुई। मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि इसको दुनिया जानती है कि इसमें घोटाला हुआ है और मैं यह निवेदन करूंगा कि शिक्षा विभाग में रियासतों के समय में भी शिक्षा में करप्शन नहीं था। यह दुनिया जानती है। मगर आज दुनिया जानती है कि शिक्षा विभाग में करप्शन फैला हुआ है और शिक्षा में करप्शन का होना मानों जनता जनदिन का नुकसान होगा। टेक्स्ट बुक ऐसी रद्दी आती हैं जिसके लिये मेरे एक माननीय मित्र ने पढ़ कर बताया कि उसमें महात्मा गांधी के पिता का नाम भी गलत है। एक पुस्तक का नाम न्यु 'इन्डिया इंगलिश रेपिड रीडर' तीसरा भाग। न मालूम किसकी महरबानी से यह हुआ है। इसमें एक पाठ मैं आता है जिसको मैं पढ़ कर सुनाता हूँ—"well Satish how far is mount Abu from Abu Road Station ?"

उसका जबाब देते हैं—"It is abuot a mile and a half from abu Road Railway Station."

आबू वहां से १७-१८ मील पड़ता है। आप लोग वहां पर गये होंगे, मैं तो गया भी नहीं और जाता भी नहीं हूं। मै जानता हूँ कि आबू, आबू रोड से १८ मील है और वह एक ही स्टेशन है। मगर यहां पर लिखा जाता है १॥ मील। फिर आप कहते हैं कि हमने यह कर दिया, वह कर दिया। क्या किया और किसके लिए किया? अगर सदन में इन सब की चर्चा की जाय तो सारा समय यों हीं चला जावेगा। यह सब बातें कहते हुए मैं यह कहता हूं कि टेक्स्ट बुकों में बड़ी गड़बड़ी हुई उसकी ओर माननीय मुख्य मन्त्री को ध्यान देना चाहिये। इसके अलावा मैं यह निवेदन करूंगा कि और विभागों में तो विभागी मन्त्री और होते हैं और अगर मन्त्री जी नहीं सुनते

[श्री मानसिंह महार]

तो माननीय चीफ मिनिस्टर से कह सकते हैं, मगर यह तो विभाग ऐसा है जो चीफ मिनिस्टर के खुद के पास ही हैं। मैं यह कमी महसूस करता हूँ कि अगर इसको किसी दूसरे मिनिस्टर को दे दिया जावे तो मन्त्री के बारे में कहने के बाद चीफ मिनिस्टर से भी कहा जा सकता है। सेक्रेटेरियेट में जाते हैं और मिल सकते हैं मगर एक छोटे से कार्य के लिये जो स्कूल के खोलने के सम्बन्ध में, उसके लिये मुख्य मंत्री जी का समय ले तो यह वाजिब नहीं क्यों कि उनके पास और भी बहुत काम होते हैं और मैं समझता हूँ कि यह कोई अच्छी परमपरा नहीं है। मैं तो बहुत कम मिलता हूँ। मैं यह निवेदन करूंगा कि गांवों से सरकार को बहुत आमदनी होती है मगर फिर भी वहां पर शिक्षा का प्रबन्ध नहीं। इसलिये गावों में उन्नति होनी चाहिये।

इसके अलावा कल माननीय मंत्रीजी ने बताया कि स्त्रियों से फीस नहीं ली जाती और उनको कॉलेजेज़ में और स्कूलों में फ्री शिक्षा दी जाती है। इसका कारण यह बताया कि अगर उनसे फीस ली जावेगी तो उनकी प्रगति धीमी हो जावेगी। मैं यह कहूंगा कि किसी भी प्रकार से लड़कियों के मां बापों का पैसा जरूर लगता है। अगर इसमें भी सुधार हो सकता हो तो जरूर किया जावे। यह माननीय चीफ मिनिस्टर से आशा करता हूं।

अब मैं ज्यादा बातें न कह कर यही निवेदन करूंगा कि मैंने अपना एक कटौती का प्रस्ताव रखा है उसमें स्पेशल मेटर रखा है। और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इसका स्पष्ट जबाब देंगे। वे अमुमन गोलमाल करके ऐसा जबाब दे देते हैं कि न तो वह हां में होता है और न ना में होता है। इसलिये हमें उनके इस प्रकार के जवाब को सुनकर दुख होता है।

(घंटी)

मैंने सदन का अधिक समय भी नहीं लिया है। मेरे कट मोशन का एक पोर्शन रह गया है।

मिडिल और हाई स्कूल के बारे में भी मेरा कटौती का प्रस्ताव था। उसमें से हाई स्कूल का तो मैंने जिक्र कर दिया, मिडिल स्कूल के बारे में नहीं कह सका। इसके लिये मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जमवा रामगढ़ और आमेर तहसील दोनों जगह मिडिल स्कूल के लिये शिक्षा विभाग के आदेश के ऊपर बिल्डिंग का इन्तजाम किया जा चुका है लेकिन इतना करने पर भी मिडिल स्कूल नहीं खोली जा रही है। आज हम यहां शहरों देख रहे हैं बिना बिल्डिंग के ही मिडिल स्कूल खोलने की इजाजत दे दी जाती है, लेकिन गांवों के संबंध में जो यह नीति बरती जाती है वह कतई न्याय संगत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सदन से मुख्य मंत्री से खास दबाव के साथ यह कहना चाहता हूँ कि गांव वालों के साथ जो स्टेप मदरली ट्रीटमेंट हो रहा है वह उचित नहीं है। मैं इस संबध में आपसे इतना ही आश्वासन चाहता हूँ कि ये दिक्कतें

[श्री मानसिंह महार]

आयन्दा दूर हो जायेगी। इतना आश्वासन भी आपके द्वारा हो जाता है तो फिर हम आपसे कार्य करवा लेंगे।

श्री गौरीशंकर आचार्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के मद में कुछ कटौती रखकर अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी सरकार का और माननीय सदस्यों का कुछ खास विषयों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इससे मेरी मंशा कदापि यह नहीं है कि शिक्षा के क्षेत्र में कोई कार्य नहीं हुआ। मैं आपका ध्यान १८३० के लार्ड मैकाले के समय की ओर लेजाना चाहता हूँ जब कि यहां अंग्रेजों की हकूमत थी, शिक्षा में भी जिस पालिसी का समावेश किया, जो नीति अपनायी गयी उसी नीति पर आज तक हम चले आरहे हैं। जबकि लार्ड मैकाले जैसे एडवाइजर नहीं रहे, अंग्रेजों का राज्य नहीं रहा, फिर भी कुछ डर ऐसा लग रहा है शिक्षा की नीति को देखकर वह यह कि अमेरीकी प्रभाव इस क्षेत्र में बढ़ता जारहा है। मैं बड़ी गम्भीरता से इस ओर हमारे शिक्षा मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जैसाकि हमारे राष्ट्रपतिजी ने, जिस मान्यता को डा. राधाकृष्णन ने सही बताया उनका कहना है कि चन्द अमेरिकी शिक्षा विशेषज्ञों का यह कथन है और सही है कि जो आज की शिक्षा पर अमेरिकी प्रभाव बढ़ता जारहा है उससे यह अन्देशा होता है, यह प्रभाव लार्ड मेकेले के प्रभाव से भी अधिक खतरनाक साबित न होजाय। जहां तक शिक्षा के देहातीकरण का प्रश्न है आज हमें बड़ी बातें नजर आती हैं। खेती करनेवाले देहातों में रहते हैं, पशुओं की संख्या देहातों में अधिक है लेकिन कृषि कालेज खुलेंगे शहरों में, पशु चिकित्सा कालेज खुलेंगे शहरों में। आखिर यह क्यों? अगर ये ही कालेज देहातों में खोले जांय तो उसका फायदा यह होगा कि आज जो देहाती भाई यह आवाज़ बुलन्द करते हैं, हमारे गांवों की ओर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जाता, इस तरह से उनकी मांग पूरी हो जायगी। सही बात यह है कि हमें इस ओर गौर करना चाहिये। आज यह देखने में आया है कि इन शहरों के कॉलेजों से निकले हुये स्नातक देहातों में जाना नहीं चाहते। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये कि वे स्नातक जो कृषि और पशु चिकित्सा कॉलेज में पढ़कर स्नातक बनकर बाहर आते हैं वे शहरों में ही रहकर कृषि और पशु-चिकित्सा का काम करेंगे वे देहातों की ओर मुंह भी नहीं मोड़ेंगे।

आज जो बातें राष्ट्रीयकरण की जारही हैं, मैं उनके विषय में माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हम और बहुत से कामों में व्यस्त रहते हैं इसलिये शिक्षा की ओर पूरा ध्यान नहीं दे पाते। इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान शिक्षा विभाग की ओर दिलाना चाहता हूँ, इस विभाग में जल्दी जल्दी दो तीन सेक्रेटरियों के तबादले हुए। दो तीन बार डिप्टी एजुकेशन सेक्रेटरी का तबादला हुआ और आज हम यह भी सुन रहे हैं कि डाइरेक्टर एज्युकेशन भी बदल रहे हैं। मैं यह सोच रहा था कि यह जो रिसर्च होरहा है अधिकारियों के तबादले का, क्या इसी विभाग में होरहा है? जहां इस विभाग में अन्वेषण, रिसर्च आदि होने चाहिये वहां यह होरहा है कि एक अधिकारी काफी समय तक रह नहीं पाता। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार शिक्षा के महत्व की

[श्री गौरीशंकर आचार्य]

ओर ध्यान दे। जो कोई भी गुलाम मुल्क स्वाधीन हुये उन्होंने सबसे पहले शिक्षा पर विशेष जोर दिया किंतु खेद है कि आज स्वतंत्र हुये आठ वर्ष होगये किंतु शिक्षितों की संख्या वही सौ प्रति व्यक्ति आठ ही है। वहीं आंकड़े हमें आज भी नजर आरहे हैं। यह हमें साफ बताता है कि हमने शिक्षा में क्या प्रगति की।

राजस्थान में महिलाओं की शिक्षा की ओर भी अधिक ध्यान दिया जाना अत्यंत आवश्यक है। इस सम्बन्ध में मैं हमारे गंगानगर के हालात का जिक्र करना चाहता हूँ। गंगानगर में लड़कियों का एक हाई स्कूल है जिसकी तीन तीन पालियां चलती हैं। आज तक वहां की लड़कियों की शिक्षा के लिये कोई इन्तजाम नहीं कर पाये यह हमारे लिये कोई गौरव की बात नहीं। आज हमें महिलाओं की शिक्षा के लिये भी प्रयत्न करना है।

इस विभाग में अगर कोई पिछड़ा हुआ वर्ग है तो वह है संस्कृत का अध्यापक। राजस्थान बनने के बाद सरकार को मैं इस बात की बधाई देता हूं कि उन्होंने अध्यापकों के वेतन में वृद्धि जरूर की है हालांकि वह असन्तोषजनक है, यह अवश्य है कि जितना जीवन निर्वाह के लिए उन्हें वेतन मिलना चाहिये नहीं मिल रहा है क्या आप उनसे यह उम्मीद करें कि वे अपने पेट पर पत्थर बांधकर राष्ट्र का निर्माण करें यह कदापि संभव नहीं। आज का अध्यापक भी एक इन्सान है उसके, रहने के लिए मकान की व्यवस्था हो उचित वेतन दिया जाय लेकिन यह व्यवस्था नहीं है। जब हम यहां पर देखते हैं कि एक व्यक्ति रेवेन्यू डिपार्टमेंट, में काम करता है या किसी अन्य विभाग में काम करता है उसी योग्यता वाले अध्यापक से इन विभागों में काम करने वाले व्यक्तियों को अधिक वेतन मिलता है और शिक्षा विभाग में उसी योग्यता वाले व्यक्ति को कम वेतन मिलता है। आज जब कि हम यह मानते हैं कि राष्ट्र निर्माण का बोझ अध्यापकों पर है तो कम से कम यह भी हमें मानना चाहिए कि अध्यापकों के भरण पोषण का भी तो भार राष्ट्र पर है। माननीय अध्यक्ष, हमने पहली पंच वर्षीय योजना में सड़कें बनाई, अस्पताल बनवाये, नहरें बनवाई, किसी न किसी प्रकार से तरक्की ही की है लेकिन इन सब चीजों का उपभोग करने वाले को जो बनाते हैं उस शिक्षा को तरफ हमने कोई खास तरक्की नहीं की। इन्सान के दिल और दिमाग को आज इतना संकुचित रखा गया है, जिससे इस तरह की धारणायें बनी रहे कि राजस्थान में नहरें खुदीं सड़कें बनीं नहरों से कितने ही अन्न के भण्डार भर जायें लेकिन राजस्थान का भविष्य तबतक उज्वल नहीं हो सकेगा जबतक कि हम इन्सान के निर्माण की ओर विशेष ध्यान नहीं देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये शिक्षा विभाग के मंत्री जी महोदय से कहना चाहता हूं वे और सब चीजों के निर्माण की ओर विशेष ध्यान देते ही हैं, इन्सान के निर्माण की ओर भी विशेष ध्यान देंगे। जहां हम संस्कृत के अध्यापकों का जिक्र करते हैं हमें एक बात अफसोस के साथ सुननी होगी वह यह कि हमारे यहां मिडिल स्कूल बढ़ गये हाईस्कूल बढ़े किन्तु संस्कृत की एक भी पाठशाला नहीं बढ़ाई गई। आज विकास की इतनी योजनायें चल रही है लेकिन संस्कृत के विकास के सम्बन्ध में हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं।

[श्री गौरीशंकर आचार्य]

भारत पर जब मध्य एशिया से आक्रमण हुआ तब तक हमारी संस्कृति फलती और फूलती रही उस समय तक हमारी संस्कृत की निधि सुरक्षित रही, आज जब तक कि हमारे देश की बागडोर हमारे नोनिहालों के हाथों आई तब से हमारी इस संस्कृत की ओर ध्यान कम जाने लगा। आज हमने पहली पंच वर्षीय योजना पूरी की दूसरी पंच वर्षीय योजना बनायी। मैं आज की हमारी सरकार से पूछना चाहता हूँ आपने हमारी संस्कृत भाषा के प्रचार और प्रसार के लिये क्या किया ? हमें उम्मीद थी जब हम आजाद होजायेंगे, विदेशी यहां से चले जायेंगे हमारी अपनी भाषा का सम्मान बढ़ेगा लेकिन मुझे तो उससे भी ज्यादा खतरा नजर आ रहा है। स्वाधीन है हम केवल राजनैतिक दृष्टि से सांस्कृतिक दृष्टि से, आज भी मेरी ऐसी मान्यता है हम स्वाधीन नहीं।

मैं और उदाहरण दूंगा। जो अध्यापक जाकर कल आपके प्राइमरी स्कूलों में पढ़ावेंगे उनकी शिक्षा का माध्यम आज भी, सन १९५६ में भी, जब कि देश को आजाद हुए काफी दिन हो गये, अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ाई की जाती है और की जावेगी।

मैं अपने पढ़े लिखे विद्वान भाइयों से कहना चाहूंगा कि दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई मुल्क नहीं मिलेगा, एक भी मुल्क ऐसा नजर नहीं आवेगा जो स्वतन्त्र होने के बाद, दासता की बेड़ियों से मुक्त होने बाद भी अपने होनहार बच्चों को, भावी पीढ़ी के नोनिहालों को, जिनके कन्धों पर उस स्वतन्त्र देश की जिम्मेदारियां डालने की हम तैयारी कर रहे हैं, उन हमारे देश के भाग्यविधाताओं को जिस भाषा के माध्यम से शिक्षित करेंगे, वह भाषा कोई विदेशी भाषा रही हो। पर आज हमारा दुर्भाग्य है कि जिस भाषा ने हमारी संस्कृति को कुचला, हमारी आत्मा का हनन किया, हमें दासता की बेड़ियों में जकड़े रक्खा वही भाषा आज हमारी शिक्षा का माध्यम बनाई जा रही है। लार्डमैकाले ने हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति को निर्दयता से कुचलते हुए जिस दास बनानेवाली शिक्षा पद्धति को शुरू किया था इस देश में और जो हमारी चिकित्सा पद्धति थी आयुर्वेद की उसको भी समाप्त किया था। सन १८३४ में तब उन्होंने कहा था कि आज भारत सही माने में गुलाम बना है और जैसे २ यह शिक्षा और चिकित्सा पद्धति यहां जड़ जमाती जावेगी वैसे २ ये दासता की बेड़ियां मजबूत होती जावेंगी। ये शब्द हैं उस लार्डमैकाले के। तो ऐसी स्थिति में मेरी समझ में यह नहीं आता कि आज अंग्रेजी को रखने की स्थिति को यह शिक्षा विभाग कैसे बर्दाश्त करता जा रहा है।

मैं यहां यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट में आया था। वहां सारा काम अंग्रेजी में। मेरा दिमाग यह देखकर फेल हो गया। मैंने सोचा मैं पागल होगया हूं या किसी पागलखाने में आ फंसा हूँ। मैं हिन्दुस्तान में हूँ या इंगलिस्तान में पहुंच गया हूं। यही हाल चिकित्सा विभाग का है। तो मैं यही अपनी सरकार से भी कह देना चाहता हूँ। और माननीय उपाध्यक्ष महोदय; आपकी मार्फत मैं उन महानुभावों से भी कहना चाहता हूँ जो कि इस देश के प्रति स्नेह रखते हैं कि धीरे २ जो यह जहर हमारे यहां फैलता जा रहा है उसे रोकने में हमें विशेष सतर्कता बरतनी चाहिये।

[श्री गौरीशंकर आचार्य]

कुछ नरमी से मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि हमने बेसिक पद्धति को अपनाया है, पर उस दिशा में भी जो हमारी प्रगति हो रही है वह मैं बेसिक पद्धति की प्रगति नहीं मान रहा हूं, वह बेसिक पद्धति को अपनाना है या हम उसका उपहास करते जा रहे हैं, इसमें सन्देह है। मैं चाहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह का उपहास बन्द हो। बेसिक पद्धति देश की मौजूदा परिस्थिति के लिये देखते हुए, समाज की परिस्थिती को देखते हुए और आज के समय को देखते हुए उपयुक्त है। पर आज जो इस क्षेत्र में एक तरह का उपहास हो रहा है वह बन्द होना चाहिये। स्कूल और कालेज भी बढ़ते जा रहे हैं पर उनसे कौनसी नई विभूतियां पैदा हो रही हैं। और उनके लिए उपयुक्त साधन जुटाये जाने चाहिये और बेसिक ट्रेन्ड टीचर्स काफी संख्या में हमें तैयार करने चाहिए। नई संस्था हमें तैयार करनी है ग्राम सेवकों की और इसके विशेषज्ञ भी हमें तैयार करने हैं। हमारे आज जो ग्राम सेवक तैयार हो रहे हैं वे न ग्राम सेवक होते हैं न सेविका। इनमें आज अनुशासनहीन सन्तानें पैदा होती जा रही हैं। यह है स्थिति उन संस्थाओं की जिन पर हम आज लाखों करोड़ों रुपया स्वाहा करते जा रहे हैं। यह कहना ठीक नहीं है कि मौजूदा शिक्षा पद्धति हमारे देश की संस्कृति की प्रतीक है। तो एक तरफ हम अपनी देश की संस्कृति की रक्षा की बात करते हैं और दूसरी तरफ ऐसी शिक्षा पद्धति में करोड़ों रुपया स्वाहा कर रहे हैं और उसे बनाये रखने की कोशिश कर रहे हैं तो ये दोनों साथ साथ चलाना उपयुक्त नहीं है।

अध्यापकों के वेतन के मामले में आप गौर करिये। कहा जाता है कि हम कितना ही बोलें सरकार पर उसका कोई असर नहीं होगा। अगर ऐसी बात है तो एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि यह जनतन्त्र है, या सेक्रेटरी तन्त्र है या नेता तन्त्र है, यह कौन तन्त्र है, इस सदन के सभी सदस्यों ने करीब करीब इस वेतन शृंखला को अनुचित बतलाया और स्वयं हमारे सदन के नेता ने यह कहा कि बहुत कुछ करना चाहते थे पर नहीं कर सके वे भी यह स्वीकार करते हैं कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है और बाकी सभी सदस्यों ने भी यह कहा कि इसमें परिवर्तन होना चाहिए पर मुझे मालूम पड़ा है कि इसके बावजूद इसमें कुछ नहीं होने वाला है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां जनता के इतने प्रतिनिधि बैठे हैं। जनतन्त्र के वे प्रतीक हैं पर उनकी कोई आवाज नहीं है यहां पर। सुनते हैं रामराज्य आ गया स्वराज्य आने के बाद यह रामराज्य हो गया है। रामराज्य में एक धोबी के कहने पर राम ने सीता को छोड़ दिया था। तो उस रामराज्य में, एक धोबी के कहने पर सीता सरीखी महान सती को भी राम ने छोड़ दिया तो आज के इस जनतन्त्र में आजके इस रामराज्य में यह हाउस और इस हाउस के सदस्य उस धोबी के बराबर नहीं। सब कहते हैं इस वेतनशृंखला में परिवर्तन होना चाहिए और वह न हो। एक विधान के सेक्रेटरी ने या मन्त्री ने जो तय कर लिया वह अपरिवर्तनीय है तो क्या यह प्रजातन्त्र का मखौल नहीं है? अगर ऐसी स्थिति है तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि प्रजातन्त्र की परम्पराएं किस तरह से पड़ेंगी और अगर ये परम्पराएं इसी तरह की पड़ेंगी तो मैं यह कहता हूँ आप से कि जब इस तन्त्र का इतिहास लिखा जावेगा तो उस इतिहास को पढ़ने वाला आगे का विद्यार्थी यही कहेगा, यही सोचेगा कि इस प्रजातन्त्र से तो और कोई तन्त्र होता तो अच्छा होता।

[श्री गौरीशंकर आचार्य]

कुछ दिनों से अनिवार्य शिक्षा के अध्यापकों को कई वर्षों का वेतन नहीं मिला और जब इस तरह की समस्या खड़ी होती है तो उसको तत्काल दूर तो करना दूर रहा यह सरकार उसको भी आगे ढकेलती रहती है। पर वे गरीब अध्यापक, जिन्होंने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिये अपनी सारी जिन्दगी अर्पण करदी है, वे आज दो २ वर्षों से अपने पेट में नाज गिराने के लिये अपने वेतन के पैसे को नहीं पा रहे हैं। यह किसी भी सरकार के लिए शोभाजनक बात नहीं है। लोगों ने प्रयत्न किया। कुछ वेतन मिल भी गया। पर दुर्भाग्य की बात है कि यह सरकार उनको उनका पूरा वेतन अभी तक नहीं दे रही है। उनका वेतन क्रम तक भी निश्चित नहीं है। उनको थोड़ा रुपया जो कुछ मिलता है वह तो समय पर मिल जाना चाहिये।

मैं कहूँगा कि जो प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं हैं उनकी ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। उन संस्थाओं की हालत खराब है। उनको भी कानून द्वारा सरकार को एक स्तर पर लाना चाहिए। मैं यह जानना चाहूंगा कि जब आप मिल मालिक और मजदूर की समस्याओं को हल कर सकते हैं तो उन अध्यापकों की समस्यों को, जो प्राइवेट संस्थाओं में अध्यापन-कार्य कर रहे हैं, आप क्यों नहीं सुलझा पाते, उन अध्यापकों ने कौनसा गुनाह किया है।

मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि आलोचना से मेरा मतलब सरकार की निन्दा करने का कतई नहीं है। बल्कि शिक्षा के बारे में जो बातें हो रही है उसमें जो खराबियां आ घुसी हैं उनको दूर करने की ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। शिक्षा द्वारा आज के ये अध्यापक इन्सानों के दिमाग का निर्माण करते हैं। पर अगर उनके दिमाग उन समस्याओं में उलझे रहे, हम उनको निश्चिन्त नहीं कर सके तो वे क्या सही दिमागों का निर्माण कर सकेंगे और अगर सही निर्माण नहीं कर सके तो राष्ट्र की बुनियाद बहुत अच्छी नहीं बन सकेगी।

श्री अध्यक्ष—श्री मोहम्मद इब्राहीम।

श्री मोहम्मद इब्राहीम—सदरे मोतरम, शिक्षा के मुतल्लिक मैंने भी एक कट मोशन रक्खा है। आज हमारा मुल्क आजाद हो गया है और तालीम के लिए किसी दूसरी जगह जाने की जरूरत उतनी अब नहीं रही जितनी पहले रहती थी। अपने ही मुल्क में काफी अच्छा इन्तजाम तालीम का हो रहा है और आज भी हमारे नोजवान कभी कभी दूसरी यूनीवर्सिटियों में और दूसरे मुल्कों में जिस तालीम के लिये जाते हैं उसका भी बहुत जल्दी इन्तजाम यहां हो जावेगा और इस तरफ खास तौर से हुकूमत ध्यान दे रही है।

एक बात जिसकी तरफ हमारे मुल्क के तमाम रहनुमा, जो ऐतबार से बहुत ऊंचे समझे जाते हैं जो तालीमी एतबार से बहुत काबिल, हैं जैसे हमारे मोतरम लीडर श्री राधाकृष्णन और राजगोपालाचार्य, बार बार इस तरफ ध्यान दिला रहे हैं कि तालिब इल्मों का कैरेक्टर और अखलाक इतना ऊंचा होना चाहिये जितना कि तालीम का तकाजा है।

श्री अध्यक्ष—आप अपना कट मोशन देख लीजियेगा और देख कर उसी पर बोलियेगा।

श्री मोहम्मद इब्राहीम—मैं उसी पर बोल रहा हूँ साहब। तो मैं तालीम के सिलसिले में अर्ज कर रहा था और इसी सिलसिले में अपने एजूकेशन मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि स्कूलों में तालीम का स्टेन्डर्ड ऊंचा होना चाहिये और तालिब इल्मों के अखलाक की तरफ खास तौर से ध्या देना चाहिये।

आज यहां हम तालीम को आम करने के लिये कोशिश कर रहे हैं और गांव गांव में, देहात देहात में सब जगह तालीम के लिये स्कूलें खोली जा रही हैं। उसमें सबसे ज्यादा इस बात की तरफ ध्यान दिया जावे कि तालीम के साथ २ बच्चों की तरबियत भी हो और असातिजा हतराज ताली के साथ २ तलबा के अखलाक व आदत को सुधारने की तरफ भी तवज्जोह रखें। देहातों में मास्टर साहिबान बच्चों पर कम ध्यान देते हैं, यह हम देखते हैं। जिस टाइम पर बच्चे स्कूल में पहुंच जाते हैं उस टाइम पर अगर मास्टर साहिब पहुँच जाते हैं तब तो कुछ पढ़ाई हो जाती है नहीं तो वहां खेल कूद ही होती रहती है। तो मास्टर पूरा वक्त देहातों में बच्चों की तालीम की तरफ लगावें इसकी तरफ पूरा ध्यान दिया जाना चाहिये। आज तो मदारिस की यह हालत है कि जब तक ट्यूशन पर मास्टर न रक्खा जावे तब तक बच्चे इम्तिहान में भी पास नहीं हो सकते। इसलिये इस तरफ खास तौर से ध्यान दिया जावे।इसके साथ ही जो हमारी हिन्दुस्तान की पुरानी तालीम हैं जैसे संस्कृत, तो संस्कृत के लिए मैं कहता हूँ कि बहुत ज्यादा इल्मी जखीरा और खजाना संस्कृत में हैं। उसकी ज्यादा से ज्यादा तरक्की की जाय जैसा कि हमारे शास्त्री जी ने अपका ध्यान दिलाया। और साथ ही फारसी भी है। संस्कृत और फारसी का चोली दामन का साथ है। और जो दूसरे मुल्कों में, एशिया के मुल्कों में जो हमारे मुल्क की शोहरत है और जो गैर मुल्कों के लीडर हमारे यहां आते हैं वे बतलाते हैं कि संस्कृत और फारसी के जरिये ही हम हिन्दुस्तान को जानते हैं। अभी शाहन्शाहे ईरान यहां आये तो उन्होंने भी कहा था कि ख्वाजा अमीर खुसरो के जरिये हम हिन्दुस्तान को जानते हैं। संस्कृत और फारसी के शायर थे वे। वे संस्कृत के बहुत बड़े आलिम फाज़िल थे और फारसी के भी बहुत बड़े जानने वाले थे।

इसके साथ ही मैं अपने चीफ मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि हिन्दुस्तान में उर्दू जबान एक मानी हुई ज्बान है। वह इसी मुल्क की पैदावार है। इसी मुल्क के हिन्दू, मुसलमान सिख और ईसाई मजहब की हजारों की तादाद में किताबें इसमें लिखी गई हैं। आज हजारों हिन्दू मजहब की, मुसलमान मजहब की और ईसाई मजहब की किताबें इसमें तब्दील हो चुकी हैं। आज भी आप देखेंगे कि हिन्दुस्तान में एक हजार अखबार उर्दू में निकलते हैं रोजाना और हफ्तावारी रिसाले अलग हैं और अखबार अलग हैं। हमारे यहां ही नहीं दूसरे मुल्कों में जाकर देखें तो बर्मा में रोजाना कई अखबार उर्दू में निकलते हैं। इसी तरीके से इन्डोनेशिया में उर्दू में रोजाना पेपर निकलते हैं। तो उर्दू को फरामोश नहीं करना चाहिए। जो कि राजस्थान में सन् ५० तक इस

[श्री मोहम्मद इब्राहीम]

स्टेट की जी कि राजस्थान की सबसे बड़ी स्टेट थी यानी जयपुर सरकार की सरकारी जबान थी, टोंक सरकार की सरकारी जुबान सन् ५० तक उर्दू की जबान थी, उनियारा सरकार की जबान थी, धौलपुर सरकार की जबान थी। उर्दू १४ जिन्दा जबानों में से एक जबान है ।

हिन्दूस्तान केआईन की मानी हुई जबान है। उसको नहीं भूल जाना चाहिए।....

श्री अध्यक्ष—आपका कट मोशन है क्षेत्रीय भावना के लिए और उसमें उर्दू, फारसी और संस्कृत कहां से आ गई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अध्यक्ष महोदय, यह तो ऐसा हो रहा है कि कटमोशन किसी के लिए दे दिया और वे किसी पर बोलें।

श्री इब्राहीम—तो मैं गुजारिश कर रहा हूं कि इस सिलसिले में ध्यान दिया जावे। आज हमारी इस सेक्यूलर स्टेट में तमाम जबानों को फलने फूलने का मौका दिया जाना चाहिए और देना चाहिए और इस सिलसिले में खास तौर से ध्यान रखा जावे। चीफ मिनिस्टर साहब का ध्यान दिलाता हूं कि उर्दू के लिए यहां अभी तक कोई गुंजायश नहीं है ! जिन राजाओं के लिए हम यह कहते हैं कि राजाओं के जमाने में अच्छा इन्साफ, अच्छी हुकूमत नहीं थी, लेकिन उनको भी उर्दू में दरख्वास्तें दी जाती थी, उर्दू में दस्तावेजें पेश की जा सकती थीं। आज होना यह चाहिए था कि हम उसको खोल देते और इसको राजस्थान इलाकाई जुबान तसलीम किया जाता।

(घंटी)

लिहाजा मैं मुतालबा करता हूं कि राजस्थान में उर्दू को इलाकई जबान तसलीम किया जावे। मैं थोड़े से में अर्ज करूंगा कि तालीम जहां हम लड़कों को देते हैं लेकिन लड़कियों की तरफ खास तौर से देहात में अभी तक, जबकि यहां शहर में बड़ी बड़ी स्कूलें लड़कियों की खोली गई हैं, कोई खास ध्यान नही दिया गया। इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए देहात के लिए खास तौर से। और हिन्दुस्तान की पुरानी तहज़ीब और तमदुन है, पुराना रिवाज़ है कि औरतें औरतों के फरायज़ अन्जाम दे, वह उनको पढ़ाना लिखाना सिखाना चाहिए। अगर आप औरतों को मर्दों के साथ खड़ा करेंगे तो फिर वह घर में रोटी पकाना, खाना पकाना छोड़कर दूसरी चीज़ पर चली जायगीं।

(हंसी)

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री **अध्यक्ष**—श्री कुम्भाराम.।

श्री **इब्राहीम**—मुझे तो अभी बहुत कहना था।

श्री **अध्यक्ष**—वह बाद में कहियेगा।

श्री **इब्राहीम**—मुझे दो मिनट की इजाजत दी जाय।

श्री **अध्यक्ष**—आप ७ मिनट बोले हैं, वह सब बिल्कुल आउट आफ स्कोप आफ दी कटमोशन बोले हैं।

श्री **इब्राहीम**—मैं तालीम के सिलसिले में बोला हूं। मैं ठीक कट मोशन के मुताबिक बोला हूं।

श्री **अध्यक्ष**—तालीम के सिलसिले में भी कुछ इधर उधर नहीं बोल सकते हैं। जिसके बारे में कट मोशन दिया है उसी पर बोल सकते हैं।

श्री बिशम्भरनाथ जोशी।

(अनुपस्थित)

श्री रामदयाल उपाध्याय।

(अनुपस्थित)

श्री कस्तूरचन्द।

श्री **कस्तूरचन्द**—अध्यक्ष महोदय, मेरा कटोती का प्रस्ताव इस प्रकार है—

"मांग संख्या १४ विषय शिक्षा में १) रू. की कटोती कर दी जाय (कोटड़ी जिला भीलवाड़ा के हिन्दी मिडिल स्कूल की समुचित व्यवस्था करने पर विचार करने के लिए)"

कोटड़ी तहसील, जिला भीलवाड़ा, के बारे में मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूँगा। जिला भीलवाड़े में कोटड़ी तहसील किस तरह की है कि जिसके बारे में ध्यान न तो सरकार का और न किन्हीं अफसर लोगों का है। मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि कोटड़ी तहसील में एक हिन्दी मिडिल स्कूल चलता है। उसके बाबत में माननीय मुख्य मंत्री साहब से प्रार्थना की थी। पहले भी जो मिनिस्टर साहब थे उनसे प्रार्थना की थी कि इस स्कूल की हालत इस तरह की है। मैं फिर से आज बताना चाहता हूं कि कोटड़ी तहसील की हालत यह है कि न तो वहां

[श्री कस्तूरचन्द]

पर मास्टर लोग पूरे हैं और न वहां पर कोई फर्नीचर है, न वहां कमरे हैं और न कुछ है। उस स्कूल की तरफ किसी तरह का कोई ध्यान किन्हीं अफसर लोगों का नहीं है। माननीय अध्यक्ष, मैं यह बताऊंगा कि आज जयपुर शहर में देखते हैं तो तरह तरह के स्कूल गली २ में खुल गये हैं मगर देहातों की हालत जैसा कि एक माननीय सदस्य ने अभी बताया था उसी तरह की हालत हमारी कोटड़ी के अन्दर हुई है। मैं बताऊंगा कि इस तरह की व्यवस्था देहातों के अन्दर अगर रहेगी तो यह देहाती लोगों के लिए अच्छा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसके बाद फिर बताऊंगा कि हमारे बनेड़ा में गत साल का ११ हजार का सामान स्कूल के मुतल्लिक सरकार ने जो खरीदा गया है उसे भेजने के लिए इत्तला मिली। हमको इस तरह की सूचना मिलती है कि स्कूल के लिए ११ हजार रुपये का सामान खरीदा गया है मगर आज तक उस सामान के आने का पता नहीं है। इस तरह की हालत, अध्यक्ष महोदय, साल भर से है........

श्री अध्यक्ष—आप कोटड़ी के स्कूल के बारे में बोल रहे थे।

श्री कस्तूरचन्द--उस पर वापिस आ रहा हूं।

श्री अयध्क्ष—जाते ही क्यों हैं कि वापिस आना पड़े। सारे जिले में मत घूमिये, कोटड़ी में ही रहिये।

श्री कस्तूरचन्द—साल भर से, गत साल से मल्टी परपज हाई स्कूल खोला गया है लेकिन वह नाम मात्र को खोला गया है। उसमें किसी तरह की सुविधा नहीं दी गई है। यह हालत हमारे यहां के शिक्षा विभाग की है।

श्री किस्तूरचन्द (जारी)—ठीक है, यह मैं मानता हूं कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर मुख्य मंत्री हुए हैं, यह संतोषजनक बात है कि आप हर तरह से जो प्रगति दे रहे हैं शिक्षा को वह मिलती रहेगी हमें इस बात का आश्वासन है। हमारे डाइरेक्टर सहाब जिनके लिए अभी चांदमलजी सहाब ने बताया कि प्रशासन में ठीक काम नहीं करते हैं। मैं कहता हूं कि डाइरेक्टर साहब बड़े इमानदार व्यक्ति हैं, मैं उनकी आलोचना नहीं करना चाहता। उनकी इस तरह की आलोचना करते हैं यह शोभा की बात नहीं है।

(घन्टी)

फिर भी मैं डाइरेक्टर साहब से और मुख्य मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि कोटड़ी तहसील में स्कूल के लिए मास्टर भेजने और सामान की पूर्ति की व्यवस्था करेंगे। इतना कहते हुए मैं अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष--श्री तेजमल बापना।

श्री तेजमल बापना—माननीय अध्यक्ष, मैं अपने दो कटोती के प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। प्रथम तो यह कि है भीलवाड़ा राजस्थान का एक बहुत महत्व का नगर है जो काफी तरक्की पर है और यदि वहां के कॉलेज की भी स्थिति देखी जाय तो मेरे खयाल से राजस्थान में जितने भी इन्टर कॉलेजेज़ हैं उनमें सबसे ज्यादा संख्या विद्यार्थियों की भीलवाड़ा इन्टर कॉलेज में मिलेगी। इतने बड़े कालेज में जहां पर प्रतिवर्ष १००, १५० विद्यार्थी इन्टर की परीक्षा में बैठते हों उस कॉलेज को डिग्री कालेज की स्थिति में नहीं लेना यह एक विचारणीय विषय है। माननीय अध्यक्ष, मैं थोड़ा सा ध्यान इस बात की ओर दिलाऊं कि आज दुनिया में शिक्षा के ऊपर कई मुल्क बहुत तरक्की कर रहे हैं और उन्होंने आश्चर्यजनक तरक्की की है। दो चार मुल्कों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा।

हंगरी में सन् १६०० में ३६.६ प्रतिशत अशिक्षा और अब वह सन् १६४१ में ६.४ प्रतिशत इल्लिट्रेसी रह गई। इसके साथ साथ फिनलैंड (Finland) छोटा सा मुल्क है वहां सन् १६०० में ६१.२ प्रतिशत थी जब कि १६३० में वह १५ प्रतिशत होगई। क्यूबा में १६०७ में ४३.६ प्रतिशत illiteracy सन् १६४३ में २३.६ परसेन्ट इल्लिट्रेसी रह गई। इसके बाद चिली (Chile) को देखें तो आपको पता लगेगा कि सन् १६०७ में ४६.६ प्रतिशत और १६४० में २६.४ प्रतिशत रह गई और बलगेरिया में १६०० में ७०.४ प्रतिशत और वही १६३४ में ३१.४ प्रतिशत रह गई एक छोटा सा मुल्क है पुर्तगाल (Portugal) सन् १६०० में ७३.४ प्रतिशत illiteracy वहां ४० में ५०.४ प्रतिशत रह गई। इन सब के मुकाबले में जब कि हम भारत को शिक्षा के संबंध में देखते हैं तो पता चलता है कि यहां कितनी इल्लिटरेसी हैं। सन् १६०१ में ६३.८ इल्लिटरेसी सन् १६३१ में ६०.६ प्रतिशत इल्लिटरेसी रही। यानी इतने अर्से में तीन प्रतिशत ही तरक्की हम कर पाये हैं। बहुत से मुल्कों ने २०.३० प्रतिशत इल्लिट्रेसी को खतम किया है। ऐसी स्थिति में हमारा शिक्षा की ओर जरूर विशेष ध्यान जाना चाहिये। यह मैं मानता हूं कि दो तीन वर्ष से शिक्षा का बजट तरक्की कर रहा है। उसके साथ साथ विशेष तौर पर जो स्थानीय संस्थायें हैं उनकी ओर भी ध्यान देना आवश्यक है। भीलवाड़ा में अगर डिग्री कॉलेज शुरू किया जाय, उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री कह सकते हैं कि खर्च का बड़ा सवाल है परन्तु मैं निवेदन करूंगा कि सब विषय एक साथ न शुरू किये जांय। प्रारम्भ में कोमर्स का विषय तो शुरू कर दिया जाय और उसके लिए मेरे खयाल से पहले वर्ष में तीन हजार रुपयों की खर्च की आवश्यकता पड़ सकती है। वह किस तरह से पड़ सकती है इस संबंध में मैं आपका थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। तीन लेक्चरार्स पार्ट टाइम डिग्री क्लासेज के लिए यदि रखे जांय तो उनके साथ साथ सब मिलाकर पांच हजार रुपयों का खर्चा हो सकता है। कम से कम ३० विद्यार्थी बी. काम प्रिवीयस में आ सकते हैं तो उससे तीन हजार रुपया प्रतिवर्ष फीस के तौर पर आमदनी हो सकती है और पहले वर्ष में दो हजार रुपया गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं और अगर सेकिंड इयर में तीन हजार रुपया और खर्चा बढ़ जाय तब भी इस

[श्री तेजमल बापना]

इस प्रकार पांच हजार रुपयों के खर्च में ही डिग्री क्लासेज शुरू हो सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि शिक्षा मन्त्री इस ओर ध्यान देंगे। मुख्य मन्त्रीजी स्वयम् भीलवाड़ा से अच्छी तरह से परिचित हैं। वहां विद्यार्थियों की कितनी ज्यादा संख्या है और डिग्री कालेज के सम्बन्ध में कितनी वहां मांग है। आपका यह प्रश्न हो सकता है कि हम स्थानाभाव के कारण वहां पर डिग्री क्लासेज नहीं खोल सकते हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि दर असल गवर्नमेंट ने उस पर बहुत ही साधारण सा खर्चा किया है जब कि वहां के नागरिक, एक सेठ महोदय ने करीब पचास (Fifty) हजार रुपये लगा कर भवन बनाया, उस पर अगर चालीस पचास हजार रुपया और लगा दिया जाय तो वहां डिग्री कालेज बना सकते हैं और मौजूदा जो बिल्डिंग है उसमें ईवनिंग क्लासेज शुरू किये जा सकते हैं और इससे बहुत कुछ वहां की समस्या का हल हो सकता है। आप यह भी कह सकते है कि जयपुर में तो ईवनिंग क्लासेज बन्द कर दीं, तो फिर भीलवाड़ा में क्यों स्टार्ट की जांय? माननीय अध्यक्ष, मैं यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यदि शिक्षा में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, अशिक्षा को मिटाना चाहते हैं तो ईवनिंग क्लासेज शुरू करना एक जरूरी विषय हो जाता है। गवर्नमेंट के जो एम्प्लोइज हैं उन पर आप किसी प्रकार का प्रतिबन्ध लगा सकते हैं, किसी को एक साल में दो साल में स्वीकृति दें लेकिन जहां उसके साथ साथ जो नागरिक बन्धुओं के लड़के हैं वे उनसे वंचित रहें यह उचित नहीं प्रतीत होता है और यदि ईवनिंग क्लासेज शुरू की जाती हैं तो स्थानाभाव का प्रश्न भी नहीं रहता है। काफी बड़ी बिल्डिंग है, शिफ्ट्स में काम चल सकता है और वहां अच्छी तरह से डिग्री क्लासेज खोली जा सकती हैं?

कालेज के साथ साथ वहां के गर्ल्स स्कूल के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। वह अब भी किराये के मकान में है और जिस मकान आज से पांच वर्ष पहले गर्ल्स मिडिल स्कूल चल रहा है जो खराब जगह पर है, छोटी सी गली में किराये पर ली हुई बिल्डिंग मे वह है जब कि संख्या गर्ल्स की काफी बढ़ रही है और इतने बड़े नगर के लिए गर्ल्स मिडिल स्कूल को हाई स्कूल की श्रेणी तक लेजाना परम आवश्यक है। उसके लिए भी स्थान की आवश्यकता है माननीय मुख्य मन्त्रीजी भीलवाड़ा पधारे थे और उनको यह सुझाव दिया गया था कि होस्पिटल में एक मेटरनिटी वार्ड अलग बनाया जाकर आज कल जो मेटरनिटी हास्पिटल है उसको गर्ल्स हाई स्कूल बना दिया जाय तो वह हाई स्कूल का काम दे सकता है।

अतः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी इन सुझावों को मानेंगे। भीलवाड़ा के इन्टर कालेज को डिग्री कालेज बना दिया जाय, वहां का जो गर्ल्स स्कूल है उसको स्थानान्तर कर दिया जाकर हाई स्कूल कर दिया जाय और यही मेरी इन दोनों प्रस्तावों की मंशा है।

श्री अध्यक्ष—श्री काला बादल

(अनुपस्थिति)

[श्री अध्यक्ष]

कुं० श्री जसवन्तसिंह—हियर, हियर।

(हंसी)

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो कटौती का प्रस्ताव है वह अध्यापकों के बारे में है। सरकार ने जो अध्यापकों का वेतन व ग्रेड बढ़ाया है उसके बारे में है।

श्री अध्यक्ष—यह आपने ही लिख दिया है या और ने लिख दिया है ?

(हंसी)

श्री मुक्तिलाल मोदी—कैसे दूसरा है। तनख्वाह के बारे में तो है, देख लो आप देख लो।

(हंसी)

अध्यापकों की जो तनख्वाह बढ़ायी है वह तनख्वाह जिस तरह से राजस्थान सरकार ने बढ़ायी है उससे अध्यापकों को आज से करीब पांच साल पहले, दस साल पहले, पन्द्रह साल पहले के जो अध्यापक हैं उनको इन तनख्वाहों से कोई फायदा नहीं हुआ है और जो नये अध्यापक लिये जावेंगे उनको थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है। काफी अध्यापक लोग हैं जो धीरे २ परीक्षायें देकर, स्कूलों को छोड़ कर दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें चले जाते हैं और स्कूलों के लिए जो अध्यापक लोग जाने चाहिए और शिक्षा की उन्नति करनी चाहिए वे इसलिए दूसरे डिपार्टमेंट्स में चले जाते हैं कि उनको शिक्षा विभाग में कम तनख्वाह मिलती है। लड़कों को पढ़ाये और स्कूल के बारे में कुछ सोचे, लेकिन वे सोचते हैं कि हमको तनख्वाह तो पेट भर कर नहीं दी जाती हैं तो फिर पढ़ाने से क्या फायदा है ? और दूसरे मुल्कों में तनख्वाह स्कूल मास्टरों की सबसे ऊंची रखी है और प्रोफेसरों की ऊंची रखी है इसलिये रखी हैं कि वे छोटे से लडके से लेकर बड़े आदमी बनने तक उनके दिमाग में जो बातें पहुंचाते हैं और जो बातें उनको पढ़ाते हैं वे हमेशा के लिये उनके दिमाग में बनी रहती हैं। तो सरकार इस चीज को देखे कि इन मास्टरों को कम तनख्वा देकर बच्चों को उन्नति के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं वह कहा तक ठीक हो सकता है। सरकार को यह चाहिये था कि उनका मंहगाई भत्ता जितना है उतनी ही उनकी तनख्वा और बढ़ा देनी चाहिये थी। और जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके बारे में मंत्रीजी ने कुछ जवाब दिया था। लेकिन मैं दुबारा दोहराता हूं कि जो स्कूलें चल रही हैं उनके मास्टरों को सरकारी स्कूलों के मास्टरों के बराबर तनख्वा नहीं मिल रही है और उनसे झूठे दस्तखत कराये जाते हैं। जिनके हाथ में मेनेजमेंट है वे लोग मास्टरों से झूठा दस्तखत कराकर सरकार के सामने झूठा हिसाब पेश करते हैं। जो लोकल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का है उसके द्वारा प्राइवेट स्कूल्स का निरीक्षण होना चाहिये। उन स्कूलों को सरकार

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

९५ परसेन्ट एड देती है तो उन स्कूलों को सरकार ही क्यों नहीं लेलेती उनको प्राइवेट स्कूल्स रखने से क्या फायदा है सरकार को, जब कि दूसरे लोग झूठे नाम से चलाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, छोटी तनख्वाह पानेवाले अध्यापकों को दूर दूर तक ट्रान्सफर करके भेज दिया जाता है। उन अध्यापकों को जितनी तनख्वाह मिलती है उसको देखते हुए वे उसी एरीया में रहे तो भी ठीक है थोड़ा गुजारा तो उनका हो सकता है लेकिन वह रहनेवाला तो है जयपुर का और काम करता है झुन्झुनू तहसील में तो इस तरह से इन अध्यापकों का गुजारा ४०, ५० रु० में कैसे हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, क्या आपके एम. एल. ए. या मिनिस्टर्स ४०, ५० रु० में गुजारा कर सकते हैं। यदि एम. एल. ए. इतने रुपयों में गुजारा नहीं कर सकता अध्यापक कैसे कर सकता है आखिर वह भी तो आदमी है, हम भी आदमी है यह सोचने की बात है। कम वेतन देने के कारण आज स्कूलों में काम भी पूरा नहीं हो पाता। ६ घंटे का यदि स्कुल होता है तो ३ घंटे तक पढ़ाई मुश्किल से होती है और ३ घंटे फालतू काम में देते हैं। वे लड़के जो पढ़ कर तैयार होते हैं वे बेकार फिरते हैं। राजस्थान सरकार ने जो मिडिल स्कूलों की ग्रेड लगाई है वह इन्टर पास मिडिल ग्रेड में बैठे रहते हैं और बी. ए. पास मैट्रिक ग्रेड पाते हैं। बहुत से लोग बेकार फिरते रहते हैं क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिलती है। तो मैं राजस्थान सरकार से, चीफ मिनिस्टर साहब से....

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मुझे एक मिनिट का समय और दें। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वे टेक्निकल ट्रेनिंग देने की स्कूलें खोलें बनिस्पत दूसरी तरह की स्कूलें खोलने के, जिससे राजस्थान की उन्नति हो सके और उन लड़कों को टेक्निकल शिक्षा देंगे तो राजस्थान की ज्यादा उन्नति होगी। और टेक्निकल स्कूलें खोलने के साथ साथ राजस्थान में फेक्ट्रीज और कारखाने भी अधिक लगाने की कोशिश करें ताकि टेकनिकल काम करने वाले काम पर लग सकें। यदि इस तरह की व्यवस्था की जायगी तो आज जिस तरह से बी. ए., एम. ए., एल. एल. बी. की पढ़ाई सभी लोग कर डालते हैं उसी तरह टेक्निकल पढ़ाई करने के लिये भी सभी लोग तैयार हो जायेंगे। टेक्निकल ट्रेनिंग की स्कूलें खोलकर राजस्थान की जनता और बच्चों को ऊंचे स्तर पर ले जावेंगे।

मास्टरों की कम तनख्वा है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिनकी तनख्वाह ३५. १. ४० का नया ग्रेड हुआ है उससे नये अध्यापकों को फायदा हुआ है लेकिन पुराने कितने ही मर गये होंगे ज्यादा होने से उनको क्या फायदा हुआ। ३५ या ४० जिनकी तनख्वाह है उनके ५ रु० और बढ़ाने चाहिये और जो मँहगाई है उसको भी तनख्वा मानकर ज्यादा बढ़ाना चाहिये। जो अंग्रेजी में मैट्रिक, बी. ए. पास हो गये हैं उनकी तनख्वा मैट्रिक ग्रेड की मिलती है तो मंत्रीजी इस हाउस के सामने बतायेंगे उन अध्यापकों के बारे में भी जो अभी बी. ए. पास हो गये हैं उनको इन्टर या बी. ए. की तनख्वाह देंगे, और फिक्सेशन करेंगे या तो कमेटी बना कर या पी. एस. सी. द्वारा होना

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

चाहिये। मैं इतना ही कह कर मंत्रीजी से उम्मीद करूंगा कि तीन चार बातें कही हैं उनका स्पष्टीकरण हाउस के सामने करेंगे और प्राइवेट स्कूलों के बारे में रूल्स बनायेंगे ताकि वे लोग किसी के भरोसे नहीं रहें और आज उनको कोई निकाल देता है, हटा देता है सो रूल्स बना दें ताकि ऐसा नहीं हो सकें।

श्री अध्यक्ष—श्री हरिसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री भैरवलाल कालाबादल। (अनुपस्थित)

श्री हरिसिंह। (अनुपस्थित)

श्री चुन्नीलाल बिड़ला।

(श्री भैरवलाल कालाबादल के बोलने के लिये खड़े होने पर)

The Hon'ble Member has no right to be absent when his name is called. He must be present.

श्री चुन्नीलाल बिड़ला—अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि मांग संख्या १३ में १ रुपये की कटोती कर दी जाय (मल्टी पर्पज-हाई स्कूल्स के बारे में विचार करने के लिये)।

अध्यक्ष महोदय, मैं जिस चुनाव क्षेत्र से आया हूं वहां एक मिडिल स्कूल बहुत पुराना मेवाड स्टेट के वक्त से चला आ रहा है और उसके बाद के कई मिडिल स्कूल्स हाई स्कूल्स बन गये हैं। हमारे यहां हाई स्कूल नहीं होने से हर साल काफी छात्र उच्च शिक्षा पाने से महरूम रह जाते हैं। आज मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि वहां की जनता ने हाई स्कूल के लिये काफी मांग की, डाइरेक्टर साहब से हम लोग मिले लेकिन किसी ने आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। वहां की जनता ने यह भी निवेदन किया कि वहां पर भवन बनाने के लिये अधिक धन राशि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि वहां की जनता धनराशि इकट्ठा करने का विचार रखती है पर इस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया।....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आप कहां की बात कर रहे हैं?

श्री चुन्नीलाल बिड़ला—११ तारीख की।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—कहां के बारे में कह रहे हैं ?

श्री चुन्नीलाल बिड़ला—मांडल के बारे में। गांवों की तरफ अधिक ध्यान देना जरूरी है क्योंकि ९० फी सदी मनुष्य गांवों में रहते हैं जहां कई प्रकार के अर्थाभाव है फिर भी हाई स्कूल के बाबत यहां की जनता ने बहुत धन संग्रह करने का भी तय किया है और मकान भी इस समय मौजूद है। यहां तहसील का हैड क्वार्टर, पुलिस स्टेशन, अस्पताल, एज्युकेशन का भी सेन्टर है। माइका का बड़ा सेन्टर है। यहां पर कन्या मिडिल स्कूल भी है। परीक्षा का भी सेन्टर है, छात्रों की संख्या भी काफी है इसलिये बहुधन्धी उच्च शाला हाई स्कूल बनाना चाहिये ताकि उच्च ज्ञान प्राप्त कर सकें और प्राथमिक बेसिक स्कूल, प्रौढ़ शिक्षा रात्रि शाला खुलनी चाहिये। गांवों की तरफ पूरा ध्यान नहीं दिया गया इसलिये देना चाहिये।

श्री रामरतन टिक्कीवाल—माननीय अध्यक्ष, मैंने जो कटोती का प्रस्ताव रखा है वह गांव में शिक्षा के विकास के लिये रखा है। अमूमन मिनिस्टर और दूसरे सभी अधिकारी शहरों की की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। शहरों में स्कूलें खोलते है मगर गांवो में इसके लिये कोई प्रबन्ध नहीं है। सारी आमदनी किसानों से लेते हैं और वह पैसा शहरो में लगाया जाता है। गांव वालों को सुविधा नहीं दी जाती। जिस समय गांवो में स्कूले खोली जाने का प्रश्न आता है तो आधा पैसा मांगा जाता है लेकीन किसानों के पास पैसा देने की कोई गुंजाइश नहीं होती और इसलिये स्कूल नहीं खुलते। गांव वाले तो आधा पैसा दें तब स्कूल खुलेगी और यहां शहर में जो लोग कुछ भी पैसा सरकार को आमदनी के रुप में नहीं देते हैं गांव वालों से ज्यादा फायदा उठाते हैं, उनसे पैसा नहीं लिया जाता। गांव वालों पर सारा राजस्थान निर्भर है। मैं यह चाहता हूं कि उनके लिये यही प्रबन्ध होना चाहिये।

दूसरी बात मैं यह कहन चाहता हूं कि टोंक बहुत पिछडा हुआ है। यहां पर गर्ल्स स्कूल पुराने टोंक में है वहां पर मकान पूरा नहीं हैं। वहां पर १००, १५० लडकियां पढ़ती हैं। मकान के लिये कई प्रार्थना पत्र सरकार के पास भेजे गये मगर कोइ ध्यान नहीं दिया गया। इसलिये जिस मकान में लडकियां पढ़ती हैं उनके लिये मकान का प्रबन्ध किया जाने चाहिये।

वहां पर लडकियों का हाई स्कूल तो हो गया परन्तु वह बहुत दूर पडता हैं और दो साल हो गये मगर अभी तक कोई बस का अच्छी तरह से प्रबन्ध नहीं हुआ वह आबादी से २॥ मील दूर पडता हैं और बस का सुचारु इन्तजाम नहीं होने से छात्रायें वहां पहुँच नही पातीं। इसलिये इसके लिए बस का ईन्तजाम होना चाहिये।

इसी तरह से कलेज हो गया मगर वहां पर साइन्स और कोमर्स नहीं होने से टोंक से आगे पढ़ने वाले पढाई से महरुम रह जाते हैं। मेट्रिक करके ही वे लोग रह जाते हैं और आगे पढ नही सकते। इसके लिये प्रबन्ध होना चाहिये। अगर किसो प्रकार से साइन्स व कामर्स कालेज खुलने में असुविधा हो तो डिग्री कालेज हो जाना चाहिये। इसके साथ साथ में यह भी निवेदन करुगां

[श्री रामरतन टिक्कीवाल]

कि वहा पर बोर्डिंग हाउस का होना भी बहुत जरुरी है क्यों कि बाहर आस पास के गांवों से पढ़ने वले लडकों को वगैर बोर्डिंग हाउस के बडी दिक्कत रहती है इसलिये बोर्डिंग हाउस का होना जरुरी हैं। इसकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिये।

इसी तरह से नीवाई की तहसील है। वहा पर हाई स्कूल है लेकिन वह बिल्डिंग कम पडती हैं अतः गवर्नमेंट को बिल्डिंग बढ़वा देनी चाहिये लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वहां पर जगह नहीं हैं इसलिये कमरे और बढा दिये जावें। बस इसी लिये मैंने कटोती के प्रस्ताव रखे हैं मैं आशा करता हूँ कि माननीय मुख्य मंत्री इस पर अवश्य ध्यान देंगे। इसके न होने से जो असंतोष फैला हुआ है इसको दूर किया जा सकता है। इसलिये मैंने यह कटोती का प्रस्ताव रखा हैं। बस इतना कह कर है अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया मुख्य मंत्री—अध्यक्ष महोदय, शिक्षा संबन्धी मांगों पर कल वाद विवाद हुआ और कटोती के प्रस्ताव भी ४६ के करीब लये गये। सबसे पहले जो माननीय सदस्य जोधपुर से आये उन्होंने किताबों के नेशनेलाइजेशन के बारे में बताया। जो पुस्तकें करीब दो वर्ष पहले उसके अन्दर जो हार्ड टेक्स्ट बुक प्राईवेट प्रेस को छापने के लिये दी गई उसको छपाई देने के बारे में और उसके बाद उनको ही वितरण करने का अधिकार देने के बारे में उन्होंने यहां पर जिक्र किया। इस सबन्ध में मुझे अच्छी तरह याद हैं कि पहले भी उन्होंने इस सदन में अपनी बात कही थी। उसको जानकारी की गई। जानकारी में मुझे पहलेवालीं बातों की जानकारी नहीं होने से नहीं कर पाया। क्यों कि ६ आना और ९ पाई की बात जो उन्होंने अभी बताई वह किस प्रकार से बढ़ाया गया। इसके संबन्ध में यह कह सकता हूँ कि इस मामले में ज्यादा जानकारी करके अगर इस प्रकार की कोई बात हुई हैं जैसा अभी बताया गया है तो मैं आगे और डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करके क्या क्या किया जा सकता हैं ज़ांच करने के बाद ही कुछ कहने की स्थिति में हूंगा अभी मैं अपने आपको कुछ इस पर कहने की स्थिति में नहीं पातों।

दूसरी बात इसी प्रकाशन की कही गई कि उसी को वितरण करने के लिये इजाजत दी गई। किसी हालत में दी गई उसका भी आज उल्लेख करना मेरे लिये मुश्किल है। लेकिन इसके साथ साथ यह बात बताई की इन्क्वारी कम्पलीट क्यों नहीं हुई। मुझे निश्चित तौर से याद है कि कागजात भेजे गये थे। उसके बाद कागजात वापिस भी आये और ऐसा याद हैं कि सारे के सारे कागजात अभी तक वापिस नहीं आये। कुछ आये हैं। जब कगजात आवेंगे उस समय में माननीय सदस्य को उन पर की गई कार्यवाही से परिचित कर दूंगां। अगर वे चाहें तो बाद में बता सकता हूँ। मैं किसी प्रिन्टिग प्रेस को सुविधा मिले, इस बात को सोच कर अपनी तरफ से नहीं चलता। लेकिन पहले जो किताबें ली गई, मुझे इस संबन्ध में याद आता है कि पहले भी प्रश्न पूछा गया था। उस समय मैंने इसकी वजह बताई थी कि किताबें प्राप्त इस वजह से की गई थी। उसमें परसेन्टेज जो दिया गया उसमे आता है। क्या दूसरी एजेन्सी प्राप्त नहीं हो रही थी ? इन सब बातो की

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

जानकारी की तो मुझे ऐसा मालूम हुआ कि अधिकारियों ने आर्डर दिया यह जानकारी मुझे बताई गई है।

अभी इसके साथ साथ एक बात और बताई गई कि जयअम्बे नाम के प्रकाशन से उसका मतलब था कि आया उनको कोई आर्डर दिया गया है, मैं निवेदन करूंगा कि यह चीज मेरी जानकारी में कल आई है। इससे पहले मेरी जानकारी में नहीं थी। मगर जो माननीय सदस्य ने कहा वह कुछ हद तक ठीक मालूम होता है क्योंकि इसके लिए मुझे पूरी जानकारी मालूम नहीं। इसके लिए आर्डर दे दिया गया है कि इस प्रकार की कार्यवाही नहीं होनी चाहिए और डाइरेक्टर पब्लिसिटी के थ्रू पब्लिकेशन मंगाये जाने चाहिए। इससे परसेन्टेज ज्यादा मिलता है जिसके लिए आपने कल अर्ज किया उसके सम्बन्ध में इतनी कार्यवाही हम कर चुके हैं यह मैं आपको बता देना चाहता हूँ।

एक बात आपने उठाई जो बहुत महत्वपूर्ण है। आपने कहा कि प्राइमरी शिक्षा पर पर भी गवर्नमेन्ट फीस लगा रही है। यह राजस्थान में ही ली जा रही है और दूसरी जगह कहीं पर नहीं ली जाती है। इसके लिए मैं निवेदन करूं कि दरअसल बजट में जो प्राइमरी एज्युकेशन का हैड है उसमें ८ वीं क्लास तक सिर्फ है। प्राइमरी एज्युकेशन में यह कम्पलसरी हो सकता है। इससे यह मतलब निकलता है इस के बाद मैंने डिटेल्स वर्क आउट करने की कोशिश की प्राइमरी एज्युकेशन आम तौर से ५ क्लास तक मानते है। इसलिए इसमें कोई फीस लगाने का विचार नहीं है।

आपका जो इस ओर भ्रम है उसको स्पष्ट करना चाहता हूँ राजस्थान में प्राइमरी एज्युकेशन के लिए कोई फीस न अब तक लगाई गई है और न आगे लगाने का इरादा है और न कोई फीस लगाई जाने वाली है। ट्यूशन फीस जो बढ़ाने की बात कही जाती है उसमें भी प्राइमरी एज्युकेशन फ्री रहेगी। इस बजट में ८ वीं क्लास तक शरीक होने को वजह से जरूर कुछ भ्रम हुआ है लेकिन हमारे यहां प्राइमरी एज्युकेशन पांचवी कक्षा तक मानी जाती है जिसके लिए कोई ट्यूशन फीस नहीं लगाई गई है। मैं माननीय सदस्यो की जानकारी के लिए यह बतलाना आवश्यक समझता हूं अध्यक्ष महोदय, जिससे सदन में या बाहर किसी प्रकार का भ्रम न पैदा हो जो हम करने जा रहे हैं उसकी क्या परिस्थिति है, दूसरी जगह मैं आपको ज्यादा दूर नहीं राजस्थान के आसपास के जो राज्य हैं उसमें फीस की क्या पोजीशन है उसकी मैंने जानकारी प्राप्त की थी। उसके अनुसार बंबई में छठी क्लास के ३।। रुपया १ महीने की फीस है। पंजाब में १२ एग्लो वर्नाकुलर स्कूल में ३ रुपया प्रति माह, एग्लोवर्नाकुलर स्कूल में १।। रुपया।

सौराष्ट्र में २ रुपया, पेप्सू में २ रुपया, मध्यभारत में १।। रुपया, अजमेर में २ रुपया १२ आना प्रति माह इस वक्त भी अपने यहां अलवर में आठ आना लिया जाता है।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

कक्षा ८ के लिये यह फीसें हैं।

बम्बई में साढ़े चार रुपया, पंजाब में साढ़े चार रुपया, सौराष्ट्र में ढाई रुपया, मध्य-भारत में सवा दो रुपया, पेप्सू में ३ रुपया व अजमेर में ४ रुपया प्रतिमाह।

राजस्थान के अंदर जोधपुर में डेढ़ रुपया और अलवर में १२ आना।

कक्षा १० की फीस इस प्रकार है—

बंबई में ५॥ रुपये, पंजाब में ६ रुपया, मध्यभारत में ३ रुपया, सौराष्ट्र में ३॥ रुपया पेप्सू में ४ रुपया, अजमेर में ४। रुपया, राजस्थान में डेढ रुपया।

यह ट्यूशन फीस की जो कम्पेरेटिव पोजीशन है वह मैंने आपके सामने निवेदन की अब आप कालेज की फीस भी देखिये।

इन्टर साइन्स की बम्बई में ३० रुपया पर टर्न के हिसाब से फीस है साल में तीन टर्न होते हैं अर्थात् ९० रुपया प्रति वर्ष, पंजाब में १० रुपया एक महिने का, सौराष्ट्र में ४६ से पर ५० पर टर्न मध्यभारत में ६ रुपया प्रति माह, पेप्सू में ६ रुपया ८ आना प्रति माह, राजस्थान में ३ रुपया ८ आना प्रति माह।

इसी प्रकार आप बी. एस. सी. की लिजिये।

पंजाब में १२ रुपया प्रतिमाह प्लस लेबोरेटरी फीस, सौराष्ट्र में ८० रुपया पर टर्न, मध्यभारत में ८ रुपया प्लस लेबोरेटरी फी, पेप्सू में १० रुपया। और राजस्थान में ४ रुपया ८ आना।

एम. एस. सी. की लिजिये। बम्बई में १०० रुपया पर टर्न, पंजाब में १५ रुपया प्रति माह सौराष्ट्र में १५० रुपया, पेप्सू में १० रुपया, अजमेर में १२ रुपया और राजस्थान में ८ रुपया प्रति माह।

ये फीगर्स मैं इस लिये रख रहा हूं, कि इससे हमारे सामने आज की स्थिति स्पष्ट होजाय, कोई मुगालता न रहे। फीस की चर्चा जब हम राजस्थान में करते हैं तो यहां ऐसा वातावरण पैदा किया जाता है कि जैसे हम कोई अजीब परिस्थिति यहां कर रहे हों। इस सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण और विशेष महत्वपूर्ण चीज की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वह यह है कि आप यू. पी. को लें बंबई को लें कोई सी भी आप ए क्लास स्टेट को लें वहां पर गवर्नमेन्ट की तरफ से हाइयर एज्युकेशन के अन्दर बहुत कम खर्च किया जाता है ज्यादातर खर्चा प्राईवेट खर्चे

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

से प्राईवेट इन्स्टीटयूशन्स चलती है। आमतौर पर ऐसा है कि फीस देकर ही वे वहां तक पहुँच पाते हैं। इस कम्पेरिजन को राजस्थान में लागू करके देखें तो आपको पता चलेगा कि अधिकांश कोलेज गवर्नमेन्ट रन कर रही है इसमें पोस्ट ग्रेजुएट कालेज डिग्री कालेज और इन्टर कालेज भी हैं। इसका असर गवर्नमेन्ट के एक्सपेन्डीचर पर कितना पड़ता है इससे अंदाज चल सकता है। हमारे विधान के अनुसार यह जरूरी है कि प्राइमरी और सेकन्डरी ऐज्युकेशन की स्टेट पर रेस्पोन्सिबिलिटी है इसको तो हम भी समझ सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी की शिक्षा का भार स्टेट पर डालना यह ठीक नहीं कहा जासकता। एक तरफ तो हम फीस बढ़ाने की चर्चा करते हैं तो माननीय सदस्य यह कहते हैं यह उचित नहीं है दूसरी ओर ग्रेड में कमी रहती है तो कहा जाता है ग्रेड बढ़नी चाहिये। तो मैं यह नहीं समझ पाया कि दूसरे प्रान्तों से यहां की ट्यूशन फीस कम है। आज हमारे यहां पर जो फीस का लेवल है यह निश्चित बात है कि इसी के कारण प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन आगे नहीं बढ़ सकी है। क्योंकि जब तक गवर्नमेन्ट कालेजेज़ के अन्दर फीस का लेवल यह होगा तो प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स में कोई पढ़ने वाला नहीं जायगा इस लेवल पर। परिणाम इसका यह हो रहा है कि हर वर्ष डिग्री कालेज में नये नये सेक्शन चालू करने पड़ते हैं। आज किसी कालेज में चार सेक्शन हैं तो अगले साल ६ सेक्शन करने की नौबत आती है। और दूसरी तरफ प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन की जो इम्पोर्टेन्स होनी चाहिये वह नहीं हो पाती।

दूसरी स्टेट में हम देखते हैं कि कई जगह स्कूल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चलाते हैं कई जगह म्युनिसिपलिटियां चलाती हैं और इसके अलावा प्राइवेट इन्स्टीटयूशन भी बहुत चलती हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरी जानकारी है यू. पी. जैसी बड़ी स्टेट में पोस्ट ग्रेजुएट कालेज गवर्नमेन्ट का एक है। आज राजस्थान के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट कालेजों की संख्या ५ है। इसके अलावा इन्टर कालेज और हाई स्कूल चलते हैं। वह अलग बात है। यहां पर जितने ही हाई स्कूल हैं सारी स्टेट की रेस्पोन्सिबिलिटी है जब कि दूसरी जगह ऐसी बातें नहीं है। स्टेट की रेस्पोन्सिबिलिटी जब हम इन इन्स्टीटयूशनस पर मानते हैं और है तो जब हम वाजिब तौर से ट्यूशन फीस के अंदर इजाफा करते हैं तो कम से कम हमारे इस विधान सभामें बैठने वाले जो सदस्य हैं उनको तो समर्थन देते हैं तो इसमें वे गलती नहीं करते हैं। एक तरफ तो आप यह चाहते हैं कि हमारे यहां ट्यूशन फीस हिन्दुस्तान के सब जगहों से नीची हो उसमें इजाफा न किया जाय दूसरी तरफ आप यह चाहते हैं कि टीचर्स की तनख्वा मनमांनी बढ़ायी जाय। यह बात उचित प्रतित नहीं होती आज हम राजस्थान को आगे बढ़ा रहे हैं तो मैं माननीय सदस्यों से यह अपेक्षा नहीं करता कि वे इसका विरोध करेंगे। मैं समझता हूँ व्यवहारिक रूप से इस प्रश्न पर विचार करेंगे।

इस सम्बन्ध में एक माननीय सदस्य ने कहा कि हम जब सब सदस्य यह कह रहे हैं कि वेतन वृद्धि जो हुई अपर्याप्त है उस पर भी कोई सुनता नहीं तो क्या यह प्रजातंत्र है? मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि वे यह न सोचें कि हम सुनते नहीं, सुनने के बाद ही हम निवेदन करने चाहते हैं माननीय सदस्यों से हम भी उनसे दरख्वास्त कर रहे हैं आपने इतने दिन सुनाया हम सुनते रहे हमारी भी तो

Page No 96

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

कुछ दिक्कत हैं जिनको आप भी तो सुन हमारा भी तो अधिकार है आपके सामने हमारी दिक्कतों के रखने का। इसी दृष्टि से जो टीचर्स के सम्बन्ध में कहा जाता है उनके बारे में मैं कम्पेरेटिव फीगर्स रखना चाहता हूँ जिससे जो बहुत सी बातें कही गई उसमें तथ्य और वास्तविकता क्या है। इस विचार कर सकेंगे।

अनट्रेन्ड मिडिल टीचर्स हैं अब उनका ग्रेड

आन्ध्र में	३०	१	३५
आसाम में	३०	१	४०
बिहार में	३०	।।)	४०
मध्यभारत में	३०	१	३५
मद्रास में	३०	१	५५
नाम पढ़ा नहीं जा रहा है	२४	।।)	३४
पंजाब में	४० से शायद		६०

ये कुछ ग्रेड्स अन्य प्रान्तों की इस प्रकार हैं:—

यू पी में	२५	१	४०	१	४५
वेस्ट बंगाल में	५०	से	७०	या	८०
और एक स्टेट और है जहां	३५	से	४०		

और हमारे यहां पर ४०–१–५०) यह रिवाइज्ड ग्रेड है।

मैं समझता हूं कि यह अनट्रेन्ड नान मेट्रिक टीचर्स के बारे में सही स्थिति मैंने आपके सामने रख दी है। अब आप बताइये कि किस स्टेट से यह कम है। डीयरनैस के फिगर्स अलग हैं। पहले ३५ से ४० था उसको ४० से ५० किया गया है। डीयरनैस के सही फिगर्स इस वक्त मेरे पास नहीं है। पर ऐसा करने पर भी जो अनट्रेन्ड टीचर्स को ग्रेड दी है उसमें अन्तर नहीं होने वाला है।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

अब मैं आपसे मेट्रिक के ट्रेन्ड के बारे में भी निवेदन कर दूं तो गलत नहीं होगा !

मेट्रिक ट्रेड आन्ध्र में	४५	से	६०
आसाम में	५०	से	६०
बिहार में	४०	से	६०
बम्बई में	६५	से	६०
मध्यभारत में	३०	से	६०
मद्रास	४५	से	६०
यू० पी०	४५	से	८०
वेस्ट बंगाल	७०	से	१३०
टीक से नहीं पढ पा रहा हूं	५०	से	१२०
राजस्थान में	६०	से	१३०

तो यह फिगर्स मैंने आपके सामने इसलिये रखना पसन्द किया कि हम किसी भी चीज पर विचार करना चाहेंगे तो इन चीजों में लोजिक्ली दूसरी जगह आज क्या कम्पेरेटिव पोजीशन है इसको स्टडी करके देख लें तो सारी पिक्चर और तरह से नजर आने लगेगी कि जो किया गया है वह किस तरह से किया गया है ।

मैं निवेदन करूं और एक दो सदस्यों ने कहा कि सेक्रेटरी ने एसा कर दिया तो मैं कह दूं कि स्केलों को तै करने में माइनर एनोमेलीज में उनका कोई हिस्सा रहा हो तो सम्भव है पर मिनिमम और मैग्ज़िमम तै करने की रेस्पोन्सिबिलिटी मैं अपने पर लेना चाहता हूं, हमने यह सब कुछ सेक्रेट्रीज की सलाह के बेसिस पर तै नहीं किया है । हमने अपने आप सोच समझकर यह सब किया है और इतनी बड़ी चीज में किसी के लिखे पर बिना दिमाग लगाये दस्तखत हम. लोग कर देंगे यह विश्वास करके आपको नहीं चलना चाहिये ।

ये सारी चीजें सोची गई और सारी चीजों को सामने रख कर यह सब तै किया गया है ।

प्रिन्सिपल की ग्रेड ८०० से तेरह सौ कर दी गई । राजस्थान में ५०० से ७०० की ग्रेड थी । पर आम तौर पर प्रिन्सिपलों की ग्रेड पोस्ट ग्रेजुएट कालेजेज की ग्रेड होती है और सब जगह करीब ८०० से ऊपर या २५, ५० कम ज्यादा पर काम कर रहे हैं और ज्यादातर तो यूनीफाइड ग्रेड में हजार के आस पास ही हैं और इस जगह कि जहां पोस्ट ग्रेजुएट कालेज रन करते हैं ३५०० या डेढ़ डेढ़ हजार लड़के जहां है वहां यह ग्रेड टीक हैं । अभी भले ही हम नहीं बढ़ावें तो ठीक है पर जब यूनीवर्सिटी काम करेगी तो उस समय अगर हमने अपने ग्रेड ठीक नहीं रक्खे तो गवर्नमेन्ट

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

कालेजेज सेकन्ड ग्रेड कालेज बन जावेंगे और अधिक वेतन के लालच में हमारे यहां के प्रिन्सिपल दूसरी जगह चले जावेंगे । फिर प्रिन्सिपल की और लेक्चरार की ग्रेड ज्यादा क्यों हैं, मैं निवेदन करूं कि वहां पर हमें कम तादाद में अधीक अच्छे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है । इसका कुल मिलाकर इन्क्षीलियेशन होता है वह कम होता है । और साथ साथ वह जो पढ़ाई करावेंगे, जिनको पढ़ावेंगे, और जिनको तैयार करना है वे विद्यार्थी अल्टीमेटली रेस्पोन्सिबल पोजीशन आपके एडमिनिस्ट्रेशन में लेने वाले हैं । तो इस पर ध्यान दिया जा सकता हैं, ध्यान देने की आवश्यकता रहती है ।

राजस्थान में शिक्षा विभाग और शिक्षा के सम्बन्ध में जो स्थिति है वह एक गम्भीर प्रश्न है । आज रास्थान में १७ हजार, मेरा खयाल है कि शिक्षक हैं और क्षमा करें मुझे ११,६०० ऐसे शिक्षक हैं जो कि अनट्रेन्ड हैं । अब जहां पर इतने अनट्रेन्ड शिक्षक हैं उन ११,६०० अनट्रेन्डों को ट्रेन्ड करना अत्यन्त आवश्यक है और यह निश्चित है कि हमने अपने ग्रेड में इस बात का खयाल रक्खा है कि ट्रेन्ड टीचर का ग्रेड ज्यादा हो इसलिये कि ट्रेनिंग की इम्पोर्टेन्स है । अगर यह भेद नहीं रहता है तो ट्रेनिंग के लिये बहुत से व्यक्ति जल्दी जाने वाले नहीं हैं । पर दोनों के बीच का मारजिन ज्यादा होता है तो ट्रेनिंग में जाने के लिए जल्दी सोचेंगे । इस तरह से मैंने जो निवेदन किया मैट्रिक ट्रेन्ड टीचरों का ग्रेड ६० से १३० का होगा । तो जो लोग यू. डी. सी. के ग्रेड की चर्चा कर रहे थे कि एल डी सी का और मैट्रिक ट्रेन्ड टीचर का ग्रेड एक है जब कि एल डी सी में अब ग्रेजुएट और उसके आस पास के व्यक्ति आने जाने वाले हैं और टीचरों में मैट्रिक ही होंगे । फिर भी इन दोनों को ६०-१३० का इक्विवेलेन्ट ग्रेड दिया गया है । फिर भी निवेदन किया था मैंने कि जहां तक अध्यापकों के जीवन स्तर में और ज्यादा तरक्की की जा सके इसमें मैं सोचता हूं कि दो रायें नहीं हो सकतीं ।

अभी मैंने निवेदन किया कि २१ हजार टीचर काम करते हैं जो ये उनको मिलती थी पिछले बजट के हिसाब से वह २५ रुपया थी । वहां हमने इस साल ४० किया है । उनको १५ रुपये का इन्क्रीज मिलने वाला है । कोई ३५ पाता है तो उसे तीन दो या पांच रुपया का इन्क्रीमेन्ट मिलेगा । और इसमें सबसे ज्यादा रिविजन किया गया है । २४ लाख रुपया इसमें सरकार को अतिरिक्त रखना पड़ा है । नान गजेटेड स्टाफ शिक्षा विभाग का जो है उसके रिविजन पर इतना रुपया इन्क्रीज होने वाला है आने वाले दस सालों में । तो मैं आपके द्वारा अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करते हुए आशा करूंगा कि माननीय सदस्य हमने जो जो ग्रेड रिवाइज किये उनमें जो कुछ इन्क्रीज किया गया है उस प्रश्न को राजनैतिक दृष्टि से कभी न देखा जावे । अगर राजनैतिक दृष्टि से हम देखना चाहेंगे तो बहुत आसान है कुछ भी कहना क्योंकि हरेक आदमी ज्यादा से ज्यादा पाना चाहता है । पर सदन पर जिम्मेदारी है इस प्रश्न पर सोचने की ।

आज अभी हमारे सामने बातें कही गई गांवों में स्कूलों के बारे में । कहा गया कि कहीं कहीं तो बैठने के लिये बच्चों के लिए टाट पट्टी नहीं हैं । सही बात है । मैं यह नहीं कहना चाहता कि

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

सब कुछ ठीक है। आज करीब १५ से २० लाख रुपया इसके लिये आवश्यक है। यूनिवर्सिटी के रिकग्निशन के लिए स्कूलों की या हाई स्कूलों की बिल्डिंग का जो कन्स्ट्रक्शन होना चाहिये वह कन्स्ट्रशन कई स्कूलों में नहीं हुआ है। इसकी भी पूर्ति करना आवश्यक है। कई जगह लेबोरेटरी के सामान की कमी है, कहीं कुछ। और इसके बावजूद भी हम शिक्षा के स्तर की बात करते हैं, अनट्रेन्ड और ट्रेन्ड टीचरों का सवाल खड़ा करते हैं, वेतन कम का सवाल करते हैं, लड़कों की ज्यादा तादाद का प्रश्न खड़ा करते हैं उन सारे प्रश्नों का एक ही स्टेन्डर्ड में सोचें कि जो फाइनेन्स है उसे इन पर भी खर्च किया जाय या जो कुछ पैसा है उसे वेतन वृद्धि पर खर्च कर दिया जाय, जोकि खुद में भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी वजह से इस साल कई वर्षों के बाद शायद पहली बार ३५ लाख रुपया इस बात के लिये रक्खा है कि बिल्डिंगों के अन्दर एडीशन किया जावे एल्टरेशन किया जावे।

हमारे सवाई माधोपुर से आने वाले सदस्य ने कहा कि वहां साइन्स की क्लासें खोले जाने की आवश्यकता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां तो बिल्डिंग की जरूरत पहले है।

आप साइन्स की बात करते हैं लेकिन हमारे पास प्रश्न इस बात का पहुँचता है कि आज जो हाई स्कूल में साइन्स क्लासेज खोलेंगे तो कहां साइन्स क्लासेज खोलेंगे? उस स्कूल में पूरा स्थान नहीं है। भीलवाड़े में डिग्री कालेज की आवश्यकता है लेकिन युनिवर्सिटी की रिपोर्ट में यह है कि इन्टर कालेज का एफिलियेशन न मिल सकता है जब कि वहां ४ कमरे बनेंगे। हम डिग्री कालेज करने की बात करते है लेकिन इन्टर कालेज के लिए ही उसमें चार कमरे चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता था इस सिलसिले में उसके साथ दूसरी कितनी सुविधाएं जुड़ी हुई हैं उन सुविधाओं पर विचार करना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष इस बजट में सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं उनकी ओर मैं ध्यान आकर्षित करूंगा कि १९६०-६१ के अन्त तक राजस्थान के अन्दर यह प्रयत्न करना चाहते हैं कि एक भी टीचर अनट्रेन्ड न रहे। ट्रेन्ड हों और वह भी आर्डीनरी ट्रेन्ड न हो बल्कि बैसिक एजूकेशन के अन्दर वह ट्रेन्ड हो। उस दृष्टि से १० ट्रेनिंग सैन्टर्स हम इस साल शुरू कर रहे हैं और १० के लिए अगले साल शुरू करने वाले हैं। १० के लिए इमारतें बनाना शुरू कर दिया है और अगले साल तक हमारे पास २० ट्रेनिंग स्कूल हो जायेंगे जिसमें हमारी योजना के अनुसार ५५-५६ में १२०० और ५६-५७ में २२०० और ५७-५८ में ३२०० और उसके बाद ३७०० टीचर्स ट्रेन्ड होकर उनमें से निकला करेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था हो जायगी। वह बहुत आवश्यक है। वह नहीं करते हैं, नहीं चलाते हैं तो जैसा कि बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि वह सिर्फ एजूकेशन न रहकर मामूली क्राफ्ट का इन्ट्रोडक्शन रह जाता है। लेकिन यदि हम चलना चाहते हैं उस पेटर्न पर तो सबसे पहली आवश्यकता है कि ट्रेन्ड टीचर्स हों। अगर ट्रेन्ड टीचर्स नहीं हों तो आप बैसिक एजूकेशन के अन्दर क्या आगे बढ़ सकते है? इसके मुताबिक हमने ध्यान दिया है और ध्यान देना चाहते हैं और इसी ख्याल से जितने ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न हो सकते हैं कर रहे हैं।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

एक माननीय सदस्य ने कहा था कि जो बाहर के राष्ट्र हैं उनमें शिक्षा की बड़ी तरक्को हुई है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान के अन्दर स्कूल गोई ग ऐज के जो लड़के और लड़कियां हैं उनके फीगर्स देकर आपको बतलाना चाहता हूँ कि फर्स्ट फाइव ईअर प्लान शुरू हुआ उसके पहले अन्दाज हम यह कर सकते हैं कि २० परसेन्ट के आसपास स्कूल गोइंग ऐज के लड़के और लड़कियां थे जो स्कूल अटेन्ड करते थे उनकी परसेन्टेज ३० तक इस फर्स्ट फाइव इअर प्लान के अन्त तक पहुंची है और सैकन्ड फाइव इअर प्लान के अन्त तक ४५ परसेन्टेज यहां राजस्थान के अन्दर पहुंच जायगी।

जो पत्र लिया उस पत्र के अन्दर रेकरिंग फाइनेन्स में डेवलपमेंट और रेवेन्यू साइड की इनकम दोनों के बीच के अन्दर रुकावट साबित होती है। एक्सपेन्डीचर जो आप करते हैं डेवलपमेंट वर्कस पर वह नान रेकरिंग होता है और इसका एक्सपेन्डीचर रेकरिंग टाइप का होता है। वह बराबर बजट में बढ़ता हुआ चला जाता है। उन लेटर्स की वजह से यह एक्सपेन्डीचर आगे नहीं बढ़ पाता है।

बहुत से माननीय सदस्यों ने, सबने, इस बात पर ध्यान आकर्षित किया कि गांव की तरफ कम ध्यान दिया जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पिछले कुछ वर्षों से, मैं समझता हूँ, ज्यादातर जो प्राइमरी स्कूल, मिडल स्कूल या हाई स्कूल्स खोले जाते हैं, ये हर साल १२००, १४०० के करीब प्राइमरी स्कूल गावों के अन्दर खोले जाते हैं। इस वर्ष भी आप व्यवस्था देखेंगे तो करीब १२०० प्राइमरी स्कूल्स गावों के अन्दर खोलने की व्यवस्था है, और मिडिल स्कूल्स भी आम तौर से जब प्राइमरी स्कूल्स खोजने जाते हैं तो मिडिल स्कूल की डिमान्ड खडी हो जाती है। मिडिल स्कूल गांवों के अन्दर काफी तादाद में हैं और हाई स्कूल भी काफी फैले हुए हैं। जमुआ रामगढ़ से आये हुए माननीय सदस्य की शिकायत है तो निश्चय ही हम इस फैसले को करें कि जिससे इस सदन के अन्दर जो चर्चाएं होती हैं इन स्कूल्स के खोलने के सम्बन्ध में कुछ आधार निश्चत कर दें और उस आधार के अनुसार जहां पर कि स्कूल खोलना आवश्यक हो वहां स्कूल आटोमेटिक रूप से खुल जांय। उन आधारों में एक यह है कि जहां बिल्डिंग हाई स्कूल के लिए नहीं हैं वहां नागरिक तैयार कर के दें। दूसरी चीज यह कि जहां आस पास इतने मिडिल स्कूल हों कि आगे नाइन्थ क्लास जो खोली जाय उसमें कम से कम २० विद्यार्थी पढ़ने वाले हों और जिसके आस-पास १५, २० मील के एरिया के अन्दर दूसरा हाई स्कूल न हो, उसको प्राथमिकता दी जाय और जिस तहसील में हाई स्कूल न हो उस तहसील को प्राथमिकता दी जाय। इस प्रकार का हमने कुछ दिनों पहले निर्णय किया है। (हियर, हियर) तो जो माननीय मित्रों को इस संबंध में बहुत भय है कि वे और तरफ से चुनकर आये हैं इसलिए नहीं खोलने की बात है तो किसी जिले में अब यह प्रश्न नहीं रहेगा। इसके अलावा प्राइमरी स्कूल्स और मिडिल स्कूल्स के लिए भी निर्णय किया है कि इतनी तादाद की पापुलेशन हो और दूसरे फेक्टर्स को तय करके जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटीज हैं उनको हम इन्टीमेन्ट कर देंगे कि इतने प्राइमरी स्कूल्स उस जिले में और इतने मिडिल स्कूल्स उस जिले में खुलना चाहिए

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

कौनसा स्थान वहां पर उपयुक्त हो सकता है वह डेवपलमेंट कमेटी वहां की सिफारश करके भेज देगी, और उस सिफारिश के आधार पर क्या करना है जिस हद तक और तरह की बात नहीं हो उसी को एडवाइस के तौर पर मानकर जितना हम लोग कर सकते हैं करने का प्रयत्न करेंगे कि जिससे भी उसमें ऐसी दिक्कतें आपके सामने न आये ।

एक प्रश्न और उठा था कि जो टीचर एपॉइन्ट किये जाते हैं तो टीचर्स एपॉइन्ट करने का तरीका ऐसा है कि जिसकी वजह से बहुत असंतोष है । असंतोष कितना है और कितना वाजिब हैं यह है नहीं कह सकता और न उसमें पडना चाहता हूं । लेकिन इस सिलेक्शन के संबंध में हम यह चाहते हैं कि आयन्दा हर जिले के अन्दर जहां तक प्राइमरी स्कूल्स के टिचर्स के सिलेक्शन का सवाल है, क्योंकि प्राइमरी स्कूलों का जिले से संबंध है, उनका सिलेक्शन वास्तव में वहां के रहने वालों, उस जिले के रहने वालों में से जो लोग रिक्वीजिट क्वालिफिकेशन को पूरा करते हैं वहां तो उन्हीं लोगों में से उन स्कूलों के लिए लिया जाय जिससे कि बाहार से प्राइमरी स्कूल्स के लिए टीचर्स भेजे जाते हैं वे आम तौर से वहां पर न रहकर दूसरी जगह जाने की कोशिश करते हैं । अब उसमें एक कमेटी बनाना चाहते हैं कि वह यह देखेगी कि अगर उस जगह के आसपास के रहने वाले मिलते हों तो ज्यादा अच्छा हो । वह इन चीजों पर विचार कर सकती है सिलेक्शन के मामले में ।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर कुछ किताबों को पढ़कर बतलाया गया कि जो टेक्स्टबुक्स के तौर पर पढ़ाई जाती हैं । मुझे खुद को दुख है कि जो पढ़कर बताया गया है उनमें दरअसल कमियां हैं । वे कमियां दूर की जा सकती हैं । हम जल्दी से जल्दी कार्यवाही करेंगे कि उस प्रकार की बातें उन टेक्स्ट बुक्स में न रहें । इस बात पर मैं इस संबंध में कुछ निवेदन करना आवश्यक नही समझता हूं ।

विज्ञान के संबंध में किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि विज्ञान के लिए कक्षाएं जितनी ज्यादा से ज्यादा जगह शुरू कर पायें उतना ही ज्यादा अच्छा है । इसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं, लेकिन प्रश्न जुडा हुआ है कि जहां शुरू की जांय वहां आवश्यक सुविधायें हो व जहां तक संभव होगा अधिक विद्यार्थी विज्ञान वाले होंगे, मकान की सहूलियत होगी वहां पर इन चीजों के करने में सरकार को एतराज नहीं होगा । जहां तक सिद्धान्त का सवाल है कि साइन्स की ज्यादा कलासेज हों इसमें दो राय नहीं है । इसी प्रकार टेकनिकल एजूकेशन के संबंध कहा गया कि वह ज्यादा होना चाहिए । जिस वक्त बजट की स्पीच पढ़ी गई, मैं समझता हूँ, उसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि इस वर्ष एक पोली टेकनीक इन्स्टीयूशन शुरू करने वाले हैं । उसके लिए ६ लाख रूपये की मकान व इक्विपमेंट के लिए व्यवस्था की गई हैं । इसके साथ साथ जुनीयर टेकनिकल स्कूल्स खोलने के बारे में व्यवस्था है जिसकी आगे कार्यवाही की जायगी । इस वर्ष के बजट के अन्दर उसके लिए ज्यादा हम कार्यवाही नहीं कर पाये हैं, क्यों औरचीजें ज्यादा आवश्यक थीं उन चीजों की व्यवस्था इसमें रखी गई है ।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

पुस्तकों की एक सूची के संबंध में यहां पर चर्चा की गई है। जिन माननीय सदस्य ने उसके बारे में जो दिक्कतें बताई हैं उन दिक्कतों से स्वयं मैं सहमति प्रकट करता हूं। यह ठीक बात है कि सूची कुछ देर से प्रकाशित होती है तो विद्यार्थियों की दिक्कत के अलावा और तरह से प्रकाशकों और बुकसेलर्स को लाभ उठाने का मौका मिल जाता है। आयन्दा इस प्रकार की बात नहीं हो उसका आश्वासन मैं माननीय सदस्य को देना चाहता हूं।

जोधपुर में डिग्री कालेज इसी वर्ष नहीं खोले जाने के सम्बन्ध में एक माननीय सदस्य ने कहा। यह सही बात थी कि वहां खोला जाना चाहिए था लेकिन बिल्डिंग की कमी की वजह से इस वर्ष नहीं खोल पाये हैं लेकिन बिल्डिंग की पूर्ति कैसे हो उसके लिये कुछ इसी वर्ष करना चाहते हैं यह आश्वासन मैं देना चाहता हूँ। उसको टालना चाहते हैं ऐसी बात नहीं है। बिल्डिंग की पूर्ति इसी वर्ष हो सके और आगे खोल सकें इसका प्रोविजन हम करना चाहते हैं।

यह कहा जाता है कि गांवों में रुपया मांगा जाता है। यह सही बात है, मांगा जाता है। मैं कहूँगा कि चाहे गांववाले हों या शहरवाले, हां, अधिक से अधिक रुपयों के लिये, मकानों के लिये आपको और हम सब को प्रयत्न करना है। गांवों में लोकल डेवलपमेन्ट फण्ड में रुपया देते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि अगर तेजी से काम करना है, ज्यादा स्कूल्स खोलने हैं, मिडिल स्कूल्स खोलने हैं तो यह तब ही होगा जबकि मकानों की व्यवस्था हो जायगी, मकान शहर में तो मिल जाते हैं लेकिन गांवों में कठिन रहती है उनकी व्यवस्था। एक माननीय सदस्य ने कहा कि ३५०० लड़के पढ़ते हैं, बड़ी तादाद है, नाम तक याद नहीं रहते। अभी थोड़े दिन पहले एक माननीय बाहर के व्यक्ति हैं उनसे बात की और करीब करीब यह तय है कि जयपुर में एक नया कामर्स कालेज शुरु कर देंगे जिसमें चार लाख रुपया उन्होंने देने को कहा है।

(करतल ध्वनि)

और गवर्नमेन्ट इक्वीवेलेन्ट देगी, इसकी पूर्ति हो सके क्योंकि काफी तादाद विद्यार्थियों की हो गई है।

मेड़ता से आनेवाले माननीय सदस्य ने ड़ेगाना में हाई स्कूल के सम्बन्ध में कहा। मैंने जनरल बात कहदी है और मैं समझता हूं कि उसी दायरे में ड़ेगाना भी आ जाता है तो ठीक है लेकिन एक बात माननीय सदस्य को स्पष्ट कर दूं कि १५ से ज्यादा नहीं खोल पायेंगे। इससे एक्सीड नहीं कर सकेंगे, अगर उसमें आजाते हैं तो ठीक हैं।

गंगापुर के बारे में एक माननीय सदस्य ने कहा। मैं भी वहां गया था, वहां एक हाईस्कूल की आवश्यकता है। तीन महीने पहले कह आया हूँ, मकान की आवश्यकता की बात हो सकती है, इन्कारी नहीं और जैसा मेरा खयाल है और मैंने जो क्राइटेरिया बताया है वह उस क्राइटेरिया में आ जायगा।

एक माननीय सदस्य—जमुआ रामगढ आ जायगा क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसमें समझ लें।

(हंसी)

मेड़ता से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा कि धार्मिक शिक्षा दें। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि धार्मिक संस्थायें देती हैं उनको भी धार्मिक शिक्षा न दें यह आमतौर पर कहते हैं। धार्मिक शिक्षा देना सेकुलर स्टेट में वाजिब नहीं है। यह ठीक है कि मोरल और नैतिकता के बारे में बातें होती हैं लेकिन कोई धर्म विशेष की उसमें प्रधानता रहती है, अमुक जगह जैन धर्म के बारे में प्रार्थना होगी, अमुक जगह पण्डित आते हैं तो उनकी पूजा करनी होगी और इस तरह खास तौर पर कोई बात रखेंगे तो वह उचित नहीं होगा, ऐसा आमतौर पर माना गया है।

जो दांता रामगढ़ से हमारे माननीय सदस्य आये हैं उन्होंने चारों तरफ असन्तोष बताया। विद्यार्थियों में असन्तोष है, स्टाफ में असन्तोष है, शिक्षक हैं उनमें असन्तोष है। सदन में ही इतना असन्तोष है तो मैं समझता हूँ कि वह असन्तोष तो थोडी-थोडी जगह फैलाया जा सकता है उस असन्तोष के सम्बन्ध में, जिसका आपने जिक्र किया, इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि विद्यार्थियों में जो असन्तोष की बात कही, आमतौर पर असन्तोष जैसी बात मैंने नहीं पायी और स्टाफ में असंतोष की बात बतायी वैसा भी मैंने सब में नहीं पाया। हो सकता है कि कुछ व्यक्तियों में हो और उसके अलग-अलग कारण हो सकते है। मुझे इस बात की खुशी है कि जमुआ रामगढ़ से आनेवाले माननीय सदस्य शिक्षा-अध्यक्ष के विरोध में बोलते रहे हैं आज जरूर तारीफ में बोले हैं। उसके लिये उनको जरूर मुबारिकबाद देना चाहता हूं और खुशी है कि शिक्षा-अध्यक्ष से इतनी प्रसन्नता रहती हैं लेकिन शिक्षा विभाग से उनकी नाराजगी जरूर है। यही निवेदन करना चाहता था। आपने एक बात पूछी कि शिक्षा-अध्यक्ष के बारे में क्या फैसला होने जारहा है ? आपको इस बहस के उत्तर में मैं भी उत्तर दूं यह आशा नहीं करनी चाहिए।

पे सेन्टर्स के बारे में दांता रामगढ़ से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा। उनकी बात ठीक है कि पे लेने के लिए काफी दूर आना-जाना पड़ता है। हम उसके लिये व्यवस्था कर रहे हैं, किसी जगह नजदीक में हाई स्कूल हो, वहां पे सेन्टर को बढ़ाया जाय, वह आलरेडी अण्डर एक्जामिनेशन है और जल्दी ही निर्णय कर लिया जायगा। इन्सपेक्टर्स और डिप्टी इन्सपेक्टर्स, डायरेक्टर्स और डिप्टी डायरेक्टर्स की ग्रेड बढ़ाने के बारे में जोर दिया, तरक्की की जानी चाहिए, मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने अपने ये विचार जाहिर किये कि उनकी ग्रेड बढ़नी चाहिये। इन्सपेक्टर्स की ग्रेड जहां तक मुझे याद है अभी कुछ दिनों पहले रिवाइज की गई थी और इस रिवीजन के साथ उसको नहीं लिया गया क्योंकि रिसेन्टली रिवीजन हो चुका था। डिप्टी डायरेक्टर्स की ग्रेड का रिवीजन दूसरी ग्रेड्स के साथ हुआ है। डायरेक्टर की ग्रेड जो राजस्थान में रखी है वह कहीं दुसरे राज्यों में नहीं है। राजस्थान में डायरेक्टर की ग्रेड १०००) से १५००) रखी है वह दूसरे राज्यों में नहीं है सिवाय टेक्निकल हैड्स आफ डिपार्टमेन्टस के। हैड्स आफ डिपार्टमेन्टस की जो ग्रेड है वही रखी है। कम

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

रखने की बात नहीं है। ऊपर के लेवल पर ग्रेड रखने की बात पर जोर दिया उसके लिए मुझे खुशी है।

अध्यक्ष महोदय, बहुत सा जो क्रिटीसिज्म हुआ है उसका कारण यह है कि यह फेक्ट है कि एजुकेशन डिपार्टमेन्ट में अभी तक इन्टीग्रेशन नहीं हुआ है और इन्टीग्रेशन नहीं होने की वजह से बहुत सी दिक्कतें हैं। फिक्सेशन भी एजुकेशन डिपार्टमेन्ट में नहीं हुआ। बहुत सी चीजें अधूरी चली आरही हैं और हमने जो एडीशनल डायरेक्टर का अपोइन्टमेन्ट किया है उसके पीछे और कोई भावना नहीं है, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मुख्य कारण यही एडमिनिस्ट्रेटिव साइड है जिसकी आवश्यकता हम बहुत अर्से से महसूस कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड को टाइड करना चाहते थे उसके लिये यह किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि फिक्सेशन और इन्टीग्रेशन का काम जो काफी अर्से से पेण्डिग है उसको हम तीन-चार महीने के अन्दर एजुकेशन डिपार्टमेंट में निश्चित तौर पर पूरा कर देंगे।काफी दिक्कतें हैं।

(करतल ध्वनि)

कम पढ़े-लिखों को ज्यादा हैं, ज्यादा पढ़े-लिखों को कम हैं, ट्रेण्ड को कम है; अनट्रेण्ड को ज्यादा है, सीनियोरिटी का डिसीजन होना है, सिनियोरिटी का क्राइटेरिया तय करना है और मैं समझता हूँ कि यह महीने-पन्द्रह दिन में कर देंगे और चार पांच महीनों में जो स्टाफ अलग-अलग है उनकी दिक्कतों के बारे में बहुत-सी बातें हल हो जावेगीं।

अध्यक्ष महोदय, मैं देख लूं, नहीं तो कोई कहेगा कि हमारी बातों का जवाब नहीं दिया है इसलिए विदड्रॉ नहीं करते।

(हंसी)

श्री भैरूसिंह—संस्कृत पाठशालाओं के विषय में बता दीजिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—स्पोर्टस के बारे में भी कहा गया था कि स्पोर्टस के लिए ध्यान देना चाहिये। इस बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस साल के बजट में भी इसका ख्याल रखते हुये व्यवस्था की गई है और आगे और उसके बाद में की जा सकती है। इस बारे में निश्चित तौर से एज्युकेशन डिपार्टमेन्ट चाहता है कि स्पोर्टस क्लब आदि है उनको इस डिपार्टमेन्ट की तरफ से ग्रान्ट इन एड दी जावे और दी गई भी है।

एक सज्जन ने यह फरमाया कि कोटड़ी की मिडिल स्कूल के बारे में व्यवस्था टीक होनी चाहिये। मिडिल स्कूल की व्यवस्था टीक होनी चाहिये इसके बारे में दो राय होने का प्रश्न नहीं

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

है। मैंने जैसा कि पहले निवेदन किया, इस वर्ष स्कूलों की इमारत आदि के काम को पूरा करना चाहते हैं। एक दो साल में इसका भी पूरा ख्याल रखा जायगा।

भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने भीलवाड़ा में डिग्री कालेज होने की जिक्र किया। मैं स्वयं वहां की स्थिति से जानकारी रखता हूं क्योंकि यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। जैसा भी होगा जल्दी ही निर्णय किया जायगा। वहां पर गर्ल्स हाई स्कूल की आवश्यकता है इस में भी दो राय नहीं हैं लेकिन मकान के बारे में फैसला होने पर निर्भर करता है।

माडल आने वाले सदस्य ने मल्टी परपज हाई स्कूल के लिए कहा लेकिन दुख के साथ कह रहा हूँ कि इस वर्ष इस तरह की स्कूल्स नहीं खोल रहे हैं इसलिए इसकी पूर्ति नहीं कर पायेंगे।

टोंक के माननीय सदस्य ने वहां के बारे में कहा था और यह भी कहा कि गांवों में पैसे कम खर्च किये जाते हैं। बिल्डिंग के बारे में कहा वहां कालेज की बिल्डिंग के बीच में हाल बना हुआ है पर उसके ऊपर छत नहीं बनी है। यह शायद ऐसा पहला ही उदाहरण हैं। नातमाम कालेज पहले ठीक हो जायं तो बाद में दूसरी चीज कर सकते हैं।

बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कंपलसरी एज्युकेशन के टीचर्स थे उनके वेतन के बारे में फरमाया। मैं निवेदन करूंगा कि उनका वेतन चुकाने का निर्णय किया जा चुका है और उनको पिछला एरियर चुकाने का भी आर्डर हो चुका है।

शिक्षा में संस्कृत का स्थान और अंग्रेजी का स्थान, इस सम्बन्ध में भी कुछ चर्चाएं चलीं हैं अध्यक्ष महोदय, पिछले ३-४ साल से संस्कृत के बारे में बहुत से माननीय सदस्यों को मालूम होगा, राजस्थान में संस्कृत को कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पर इन्ट्रोड्यूज किया गया है। अब आगे हायर सेकेन्ड्री स्टेज के बारे में यदि खुद संस्कृत के अलग स्कूल और कालेज के रूप में विकास हो यह अलग चीज रह जाती है। संस्कृत का विकास हो, परशियन का विकास हो, इस संबन्ध में सरकार की तरफ से ऐतराज नहीं है क्यों कि फारसी का भी विकास होता है तो खुशी है, ऐसी बात नहीं है कि उसका विकास नहीं हो, हमारे देश में उसका विकास होता है, राजस्थान में भी इसकी व्यवस्था रही है और अब भी आवश्यकता हो तो व्यवस्था की जा सकती है। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि जो यह समझ कर चलते हैं कि हम संस्कृत को नहीं चलने देना चाहते, यह बात नहीं है। ग्रेड रिविजन आदि के कारण और तरह २ का रूप बन गया है। मैंने निवेदन किया था कि ग्रेड रिविजन में कुछ एनामोलीज हुई हैं उनको ठीक करना है। वहां भी कुछ रह गये हैं उनको एडजस्ट करना होगा, एनामोलीज पर ध्यान देना पड़ेगा विकास के लिये यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें सहयोग अवश्य करेंगे।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

अंग्रेजी माध्यम का सवाल भी उठाया गया कि अंग्रेजी में शिक्षा क्यों दी जाती है। जहां तक प्राइमरी एज्युकेशन का प्रश्न है वहां तक मैं समझता हूँ, इसमें विवाद नहीं रहा प्राथमिक शिक्षा का माध्यम हिन्दी ही है। अब सवाल यह आता है कि सेकन्डरी स्टेज पर कौनसा माध्यम हो, कौनसी भाषा हो। जहां तक माध्यमका सवाल है हिन्दी ही माध्यम है और इसी में लडके पढ़रहे हैं। अंग्रेजी के बारे में भी माननीय मित्र ने कहा, पिछले दिनों एज्युकेशन मिनिस्टर्स की कांफ्रेंन्स हुई या और चर्चाएं चलती है उसकी वजह से ख्याल आया मालूम होता है लेकिन यह सवाल है कि सेकन्डरी एज्युकेशन का माध्यम अंग्रेजी में भी चल रहा है। हमारे देश में विचार हो रहा है कि सेकन्डरी में अंग्रेजी कंपलसरी हो या नहीं। यह अंग्रेजी या अमेरिकन दिमाग की वजह से नहीं है। बल्कि हमारे देश की इस समय जैसी परिस्थिति है उसके अन्दर दक्षिण निवासी भाइयों के दिलमें यह ख्याल है कि हिन्दी को केवल उत्तर मे रहनेवाले लाना चाहते हैं और वे ही लोग अंग्रेजी माध्यम को दूर करना चाहते हैं। इन चीज़ों की वजह से तीन भाषाओं की ओर विचार धारा जाती है, अपनी खुद की रीजनल लेंगवेज, अंग्रेजी और हिन्दी जिससे कि एक दूसरे का ज्ञान और एकता का अनुभव कर सकें। इसी दृष्टि से इस पर विचार चलता है। इस में अंग्रेजी और अमेरिकन दिमाग की विचार धारा का प्रश्न नहीं है। जैसी देश की परिस्थिति है और आवश्यकता के अनुसार इस पर विचार किया जायगा। मैं समझता हूं मेकाले के समय में अंग्रेजी भाषा किसी भी दृष्टिकोण से शुरू की गई हो लेकिन आज हमारा देश इतना जागृत अवस्था में अवश्य है कि जो दृष्टिकोण पहले था वह अब नहीं है। पहले शिक्षा इस दृष्टिकोण से दी जाती रही होगी कि जो लोग पढकर निकले वे केवल सरकारी नौकरियों के लिये हों। यही दृष्टिकोण सबसे ज्यादा बुरा था या है। उसमें परिवर्तन करके टेकनिकल चीजों की ओर हम ज्यादा बढ़ते हैं तो भाषाओं का झगडा इतना नहीं है जितना होना चाहिये। दृष्टिभेद है यह मानकर ध्यान दिया जा रहा है। मैं समझता हूं हमारे देश में हमारी राष्ट्र भाषा अधिक पनपे इस में कोई दो राय नहीं हो सकतीं। सभी इस चीज का ध्यान रखते हैं। लेकिन कैसे चलें इस ओर ध्यान रखना है।

बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बेसिक पद्धति की कमी बताई वह ठीक है। इसकी पूर्ति के रास्ते में मैं समझता हूँ सबसे पहले यह हो सकता है कि हम ट्रेनिंग फेसिलिटीज को बढ़ाकर बुनियादी तालीम के शिक्षक तैयार करें।

मैं काफी समय ले चुका हूं अध्यक्ष महोदय, कुछ पोइन्टस रह गये हों तो माननीय सदस्य और बता दें।

श्री जगतसिंह झाला—भोपाल नोबल्स स्कूल के बारे में कुछ नहीं फरमाया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसके बारे में अलग विचार किया जा रहा है। अभी मैं यह कह दूं कि इतना काम हो जायगा यह तो मुश्किल है। यह केवल जागीरदारों की ही स्कूल

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

है ऐसी बात नहीं है इसमें और भी विद्यार्थी पढ़ते हैं। इसका बड़ा मकान है इसका भी उपयोग करना चाहिये। इस दृष्टिकोण से मैं स्वयं विचार कर रहा हूं। जितना हो सकेगा उतना करेंगे।

मैं आशा करता हूं कि जिन जिन माननीय सदस्यों ने अपने कट मोशन्स मूव किये हैं वे विदड्रा करेंगे इस ख्याल से कि जो बातें मैंने कही हैं उनसे उनको संतोष हो गया होगा। जो बातें आपने कही हैं उनका उत्तर मैं दे चुका हूं।

श्री अध्यक्ष—मुक्तिलाल जी की बात आपने नहीं कही प्राइवेट स्कूलों के बारे में।

श्री मुक्तिलाल मोदी—प्राइवेट स्कूलों के हिसाब की जांच लोकल ओडिट द्वारा होनी चाहिये या इनको सरकार लेले इस बारे में नहीं फरमाया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं पहले ही निवेदन कर चुका था, यही सोच कर मैंने जिक्र नहीं किया। प्राइवेट स्कूलों के हिसाब का ओडिट होना चाहिये। ओडिट से मेरा मतलब गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है लेकिन अकाउन्टस का ओडिट होना चाहिये और जो टीचर्स प्राइवेट संस्थाओं में हैं उनके बारे में रूल्स फ्रेम करना चाहते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—पेमेंट का तरीका बदलने के बारे में क्या विचार है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह अलग से सोचने की बात है।

श्री मुक्तिलाल मोदी—मास्टरों को कम तनख्वाह मिलती है और ज्यादा के दस्तखत करा लेते हैं। इसके बारे में क्या?

श्री अध्यक्ष—पे स्केल्स एण्ड सिक्योरिटी।

श्री मुक्तिलाल मोदी—उनको सरविस जैसी गवर्नमेन्ट में मिलती है वैसी मिलनी चाहिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह बात मैंने अर्ज की कि प्राइवेट स्कूलों के अध्यापकों के बारे में रूल्स फ्रेम करना चाहते हैं उस समय इनके वेतन, सरविस आदि पर विचार कर लिया जायगा। वेतन के बारे में जो प्राइवेट स्कूलें हैं उनके लिये भी रूल्स जो सरकार की स्कूलों में हैं मानेंगे।

मैं वेतन के बारे में नहीं कह सकता कि वह किस प्रकार से लागू किया जावेगा लेकिन सर्विस रुल्स बन जावेंगे और जो पैसे मिलते हैं वे उनके पास पहुंच जावेंगे उसके लिए जितना चेक हो सकता है किया जाएगा।

श्री मुक्तीलाल मोदी—मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष मैं, सिर्फ इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि जिन बातों का मैंने डिटेल्स में जिक्र किया उनके बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी बताया कि जानकारी पूरी नहीं हो पाई है और जब जानकारी पूरी होगी उनके बाद में निर्णय होगा उसकी सूचना मुझे दे दी जावेगी। इस लिये इस विषय में तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं रह जाती है। हां अलबत्ता १॥ वर्ष में आपको जानकारी नहीं हुई है यह बात मैंने अपनी जानकारी में जरूर ले ली है आशा है अब वह उनके ध्यान में आ गई है अतः वे इस पर कार्यवाही करेंगे।

अब शिक्षा के लिए प्रश्न एक ही है वह यह कि आया राजस्थान शिक्षा में तेजी से आगे बढ़ने में भारत के दूसरे प्रान्तों के बीच बराबरी का दर्जा रख पावेगा या नहीं और जो शिक्षा में शुल्क की दरें हैं उनको देखते हुए शिक्षा में आगे बढ़ने के लिये अग्रसर होगा या नहीं। इसके लिये कम से कम मेरी मान्यता यह है कि सेकिन्ड्री एज्युकेशन तक कोई फीस नहीली जानी चाहिये और जो फीस ली जारही है उसको लगातार कम करते जाना चाहिये ताकि एक समय ऐसा आ जावेगा जब कि वह फीस खत्म कर दी जा सकेगी। हमारे यहां संविधान में डाइरेक्टिव पोलिसी ऑफ स्टेट पोलीसी में जहां पर शिक्षा का उल्लेख किया गया है उसमें साफ प्राइमरी शिक्षा का उल्लेख है। वह इस रूप में नही है जैसा आप मानते हैं। उसमें एक साल से १४ साल तक के लडकों का जिक्र है चाहे वह मैट्रिक में रहें और ७ वीं में रहें तो रहें लेकिन शिक्षा उस स्तर तक फ्री और कम्पलसरी है। और यही सिद्धान्त दुनिया के सभी मुल्कों में एक सा मिलता है और यह हमारे कोन्स्टीट्यूशन की भी देन है। इसको सिद्धान्तिक रूप से टाल ने की कोशीश करना मानो आप उसपर अमल करना नहीं चाहते हैं। आपने बजट में जो इस सबन्ध में आंकडे आय व्यय के प्रस्तुत किये है, मैं यह कहूंगा कि मुझे इन आंकडों को अध्ययन करने का मौका नहीं मिला। आपने यह बताया कि ८वीं क्लास से उपर २रु०से ७रु०तक फीस लीजाती है और कहीं कहीं १॥रु० भी है। राजस्थान में भी फीस है और वह २॥रु०और ४॥रु० भी है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह केवल जोधपुर में ही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अलवर में कोई फीस है और कोई जोधपुर में है जो मुझे मालूम हुआ है उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ। यह कि आपने शिक्षा के शुल्क के आंकडे जमा किये हैं लेकिन आंकड़ो के बारे में मोह किस को है ? अगर आपको आंकडे इकट्ठे करने थे तो हर चीज के आंकडे हर जगह के आंकडे इकट्ठे क्यों नहीं किये। अगर आप हिन्दुस्तान में अलग अलग मुल्कों के मुकाबलेमें राजस्थान की शिक्षा का हाल देखें तो आपको मालूम होगा कि हमारा नम्बर ४था फ्रोम दी बोटम आता है। इसके अलावा आमदनी में भी कोई फर्क नहीं पडा है अजमेरको छोड कर राजस्थानी के लोगों को देखें तो आपको मालूम होगा कि एक आध जगह ही आपको मिलेगा जहां पर कि लोगों की इनकम पर केपिटा बढ़ी हो। आपने इस प्रश्न पर कोई उत्तर नहीं दिया कि यहां के लोगों की आमदनी कितनी है। उन पर टैक्सेशन का बर्डनकितना है और कितना नया टैक्स प्रपोज़ करने की बात

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

करते हैं। इसको देखते हुए आपको ध्यान रखना चाहिये। यह राय मेरी नहीं है कि यहां के आदमी की आमदनी बहुत कम है यह राय है राजस्थान सरकार के फाइनेन्स मिनिस्टर की, उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये मेमोरेन्डम की। अगर मैं भूल करता हूँ तो मैं कहूंगा कि मेड़ते से आये हुए फाइनेन्स मिनिस्टर श्री नाथुरामजी उस जमाने में मिनिस्टर थे उन्होंने खुदने लिखा है कि राजस्थान में ७२ हैं और बम्बई में ७१ है, कहीं ६२ है। ऐसी स्थिति है अभी जो माननीय फाइनेन्स मिनिस्टर ने बजट पेश किया है उसमें ८४ लाख का बोजा बढ़ा है वह भी है, मगर मैं अभी की बात नहीं करता हूँ मैं १६५१ के आंकडों की बात कह रहा हूं। इसके अलावा शिक्षाके आंकडे हैं उनको आपने उलट पुलट कर रखा है इसके अलावा अगर आंकडों को देखेगे तो पहले तीन हजार का रिम० है वह अब जा रहा हैं ३॥ लाख यानी ६, ७,और ८ वीं कक्षा का रेमीशन फीस का होगा ३॥ हजार से ३॥लाख आप उसको पहले ३॥ हजार से अब ३॥लाख तक पहुँचाना चाहते हैं। यदि हाल मेट्रिक और सेकिन्ड्री एज्युकेशन का है जहां ४॥ लाख रुपये की आमदनी थी उसमें से ५० हजार फिमेल शिक्षा के (कन्सेशन टु गर्ल्स) काटलें तो ३॥। लाख होती है लेकिन अब १२॥ लाख की आमदनी होगी। यह बीच का इनक्रीज है।

मैं आंकडों के बारे में बता देना चाहता हूं किएक वैज्ञानिक नदी पार करने को आया। नदी की गहराई नाप ने का उसने आदेश दिया। किनारे के पास गहराई कम थी और बीच में २२ और २० फुट निकली। उसने सबका एवरेज निकाल लिया सारी नदी का एवरेज आया २॥ फुट। उस वैज्ञानिक ने कहा कि मैं ६ फुट का आदमी हूं नदी पार करजाऊंगा। वह नदी पार करने गया और बीच मे ही डूब गया। यह स्थिति राजस्थान सरकार की न हो जावे। इस लिये मैं फिर से कह देता हूं कि आज बजट प्रस्तुत किया गया है और अपने जो आंकडे रखे हैं वे किसी भी बुनियाद पर नहीं हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से यह जानना चाहता हूं कि वे कालेज की फीस बढ़ाने के पक्ष में है या नहीं?

श्री हरिकृष्ण व्यास—(जारी रखते हुए)

अध्यक्ष महोदय, अभी यह प्रश्न प्रस्तुत किया गया है, वैसे मेरा समय बढ़ाने का इरादा नहीं था किन्तु बीच में यह प्रश्न कर दिया गया....

श्री अध्यक्ष—आप यह चाहते हैं कि समय तो बढ़े, किन्तु शिक्षा-शुल्क नहीं बढ़े।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, आपने मेरी राय को अच्छी तरह से समेराइज कर दिया है। अभी माननीय मुख्य मन्त्री ने कहा कि कालेज की फीस बढ़ाने में आपकी क्या राय है; तो मैं कालेज के बारे में उल्लेख कर दूं। यहां यह कहा जाता है कि कालेज के अन्दर फीस बढ़ाई जाय, क्या एतराज है? मैं माननीय मुख्य मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूं सामान्य आदमी

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

का लड़का कालेज में पढ़ता नहीं है । मेरा ऐसा खयाल है कि कालेज में पढ़ने वाले लड़कों के गार्जियन की आमदनी देख कर फीस बढ़ाई जाय और वह भी ग्रेडेड रूप से बढ़ाई जाय । जिसको दो हजार रुपया मिलता है उससे पचास रुपया फीस ली जाय । चार हजार पाने वाले व्यक्ति के लड़के से १०० रुपया मासिक ली जाय । मेरा ऐसा कहना है कोई भी बात हो सिद्धांत की होनी चाहिये । लोगों का मुगालता आप दे सकते हैं किन्तु आपका इरादा है कि साधन सम्पन्न लोग हैं और एक गरीब आदमी है दोनों से बराबर शिक्षा शुल्क लिया जाय इसे कतई न्याय संगत नहीं कहा जा सकता । राज्य से जो सुविधा प्राप्त है उससे साधन सम्पन्न व्यक्ति भी उतना ही लाभ उठाता है जितना कि एक गरीब आदमी, आज आपने यह व्यवस्था कर रखी है कि लोअर डिवीजन क्लर्क आज कम से कम बी० ए० पास नहीं हो तब तक सरविस में नहीं लेते । एक सामान्य और मध्यम श्रेणी का व्यक्ति इतना ही चाहता है कि उसका लड़का भी कम से कम लोअर डिवीजन क्लर्क तो बने, ऐसी हालत में उसके लिए यह जरूरी हो जाता है कि वह अपने बच्चों को कालेज में भर्ती कराये । अगर सरकार यह निर्णय करती है कि कालेज में फीस ग्रेडेड होगी तो दस लाख रुपये जिस व्यक्ति के पास हैं उससे एक लाख रुपया साल में फीस लेली जाय इसमें मैं कभी एतराज नहीं करूंगा लेकिन आप चालीस और पचास रुपये पाने वाले से भी उतनी फीस लेंगे जितनी फीस उस लखपती के लड़के से लेते हैं यह कभी उचित नही कहा जा सकता ।

शिक्षकों के बारे में काफी बहस हो चुकी है मैं तो इस सम्बन्ध में केवल इतना ही कह देना उचित समझता हूं कि इस सम्बन्ध में जितने भी आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं और जो केवल वातावरण बनाने की दृष्टि से प्रस्तुत किये गये हैं और कहा यह गया कि अब आप क्या कहते हैं ? चारों तरफ ऐसी ही हालत है शिक्षकों की । मैं इस सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहता हूं कि इन आंकड़ों में एक छोटी सी 'जालसाजी' की गई है इस ओर संकेत कर दूं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह 'जालसाजी' पालयामेंटरी शब्द नहीं है ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—वे ऐसा करते हैं । There is a lie, there is a white lie and the third is statistics.

इस सम्बन्ध में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान में पहले जो स्टेटिस्टिक्स इस सम्बन्ध में लिये जाते थे स्कूल जाने वाले छात्रों के सिलसिले में एक साल से लेकर १४ साल तक की आयु वाले छात्रों की स्कूल जाने वाले छात्रों में गिनती करते थे । सन् १९५०-५१ के अन्दर स्कूल गोइंग एज एक से १४ साल तक की होती थी । अब क्या किया गया है कि उसकी जगह एक से १० तक की कन्डीशन कर दी गई । इससे १४ परसेन्ट तो बढ़ गई । लड़कों की कोई तादाद नहीं बढ़ी बल्कि हिसाब करने का तरीका बदल गया ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आपका यह मतलब है कि तादाद पांच सालों में लड़कों की नहीं बढ़ी ?

[श्री हरिकृष्ण व्यास]—(जारी रखते हुए)—

मैं तो यह कह रहा हूँ कि राजस्थान सरकार के कागजों में स्कूल गोइंग एज लड़कों की जो १५ साल तक थी उसके बाद जो दस साल करदी गई उससे २० प्रतिशत की वृद्धि हुई है और दी सेम टाइम एन्ड पीरियड । सन ५१ के मेमोरेंडम श्री स्वामी नाथ न की रिपोर्ट श्री नारायण के के दस्तखतों से जिस पर श्री नाथूरामजी की छाप लगी हुई है उसमें १५ साल तक की एक को स्कूल गोइंग एज माना गया था । मैं जो यह निवेदन कर रहा हूँ उस संबन्ध में माननीय मंत्री जी पता लगायें । मैं नहीं जानता कि अब जो एक से दस साल तक एज रक्खी गई है वह क्या गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया के स्टेंडर्ड के मुताबिक किया होगा । यह मैं नहीं कह सकता इस तरह से १५से २०परसेन्ट तक की वृध्दि कागजों में आंकडों से हो गई । माननीय मुख्यमंत्री भी इस बात का पता लगा लें अगर मैं गलत हूं तो वैसा कहें ताकि मैं सदन के सामने माफी मांग लूं अपने अधिकारियों से जानकारी कर लें । यह जो आंकड़े हैं जिसके आधार पर लगातार यह कहा जाता है कि हम जो दे रहे हैं उसको आप दूसरी जगह से तो मिलाइये । हिन्दुस्तान के दूसरे प्रान्तों की ओर भी तो देखें इन्डिस्ट्रीज के बारे में एम्पलायमेंट के बारे में जो तरक्की दूसरे प्रान्तों में हुई है उसकी ओर भी तो देखें लेकिन जिन चीज़ों की तरक्की की ओर हमें देखना है वह तो हम देखते नहीं अगर आपका किसी चीज में किन्हीं जगहों का अनुकरण करना हो तो अच्छा चीजों में अनुकरण करें । राजस्थान सरकार ने यह तय कर लिया कि जहां जहां हमें गलती मिलती है ढूंढ ढूंढ कर लागू करेंगे तो कम से कम इन बातों को लागू करने में या साथ देने में हम लोगों से उम्मीद करना गैर वाजिब है । इन शब्दों के साथ में सदन से यह निवेदन करता हूँ कि मेरे जो कटोती के प्रस्ताव है वे मंजूर करें ।

श्री **भैंरूसिंह**—माननीय अध्यक्ष, मुख्य मंत्री जी ने पे स्केल्स के बारेमें राजस्थान के पे स्केल्स का मुकाबला करते हुये दूसरे प्रान्तों के आकड़े इस तरह प्रस्तुत किये । और जिस तरह से जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया उन आंकड़ों पर भी यदि पूर्णतया विश्वास न किया जाय तो इस बात को छोड़ कर अपने ही प्रान्त में इस प्रकार की योग्यता वाले व्यक्तियों को पे स्केल्स दिये हैं, हम अगर उनको देखते हैं तो यह पता लगता है कि शिक्षा विभाग में मैट्रिक इन्टरमेडियेट और ग्रेजुएट को इनके मुकाबले लोअर डिविजन क्लर्क और अपर डिविजन क्लर्क की तौर पर काम करते हैं कितना अन्तर है ? यहां जो हमने ७० से १२० तक की तनखा दी हैं, वहां लोअर डिविजन क्लर्क और अपर डिविजन क्लर्क को १३० और २०० तक डिटरमीन किया है । अगर राजस्थान के ही आंकड़े हम देखते हैं तो हमें काफी अन्तर दिखाई देता है जब कि एक ही योग्यता वाले व्यक्ति दोनों जगह हैं तो फिर पे स्केल्स में असमानता क्यों ?

इसके अलावा इंस्पेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर की तनखाओं के बारे में भी मैंने विचार करने के लिये निवेदन किया । मुख्य मंत्री ने केवल एक बात की ओर संकेत करते हुए उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया कि मैंने डाइरेक्टर के वेतन वृध्दि में अपनी सहमती प्रकट की यह उन्होंने कहा इस बात को कहकर उन्होंने खुशी प्रकट की अगर इसको दूसरे रूप में देखा जाता तो विशेष लाभ दायक होता । अध्यापकों को तनखा के साथ साथ डाइरेक्टर की तनखा और डिप्टी

[श्री भैंरूसिंह]

डाइरेक्टर और इन्सपेक्टर की तनखा से तुलनात्मक रूप से विचार किया जाने के लिये मैंने निवेदन किया था और मैंने फीगर्स बताये थे कि तुलनात्मक दृष्टि से ये आंकड़े ठीक नहीं बैठते। आज जब किसी विभाग के अधिकारी की तनखा दो हजार करदी जाती है उस विभाग के नीचे से नीचे व्यक्ति की कम से कम तनखा १०० के अंदर करनी चाहिये। यदि इस प्रकार की बात होती तो मुझे ज्यादा खुशी होती वेतन कम से कम निर्धारित होकर ज्यादा से ज्यादा वेतन में १० गुने से या ५ गुने से ज्यादा फर्क नहीं होता तो मैं अवश्य खुश होता।

अध्यक्ष महोदय, मैं ने तीन किताबों का उल्लेख किया। उस पर माननीय मुख्य मन्त्री ने केवल यही कहा कि इस पर मुझे खेद है कि किताबों में इस प्रकार की गलतियां हैं। मैं जहां तक समझता हूं केवल खेद प्रगट करने से काम नहीं चलेगा, इन गलतियों के कारण जो गलत शिक्षा दी गइ जिन पर शिक्षा देने का दायित्व है उनके खिलाफ किसी प्रकार एक्शन लिया जायगा या नहीं। ये तीनों किताबें जिन्होंने लिखी है उनकी गलती है और उससे भी ज्यादा गलती है उस कमेटी की जिसने ऐसी किताबों को पाठ्यपुस्तकों में शामिल किया मैं समझता हूँ जब तक उनको सजा नहीं दी जाती खाली खेद प्रगट करने से कुछ होने वाला नहीं है। मैं माननीय मुख्य मन्त्री से यह निवेदन करूंगा कि इन लोगों के खिलाफ इस बारे में विशेष रूप से एक्शन लेंगे।

तीसरी बात मैंने संस्कृत के विषय में उठाई थी उस पर माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो उत्तर दिया उससे मुझे सन्तोष नहीं है।

इन तीन चार बातों को लेकर में सदन की स्वीकृति के लिये अपने कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए मांग करूंगा कि वह स्वीकार कर लिया जावे।

श्री चांदमल मेहता—माननीय अध्यक्ष, इसमें तो दो मत नहीं हो सकते कि माननीय मुख्य मन्त्री महोदय जवाब देने की कला में प्रवीण हैं। (हंसी एवं करतल ध्वनि) पर उसका हमारी आत्मा पर क्या असर होता है, यह देखने की बात है? वहां कुछ तथ्यों की बात का सवाल है वहां वे उन तथ्यों को बहुत ही होशियारी से नजर से ओझल कर जाते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह तो अलग अलग आत्मा के समझने न समझने पर निर्भर करता है।

श्री चांदमल मेहता—माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय के जवाब से यह ध्वनि निकली है कि अध्यापकों के सिलेक्शन के सिलसिले में उनके इन्टीग्रेशन की बाद कह कर उन्होंने इस मामले को फिर पांच, छः महीने आगे के लिए टाल दिया है और इस बीच जो सिलेक्शन अभी अगले मास में आनेवाला है उसमें फिर उन सरकारी अधिकारियों, सेक्रेटरियों आदि के हाथों में यह अधिकार फिर दे दिया गया है कि वे जो चाहें गड़बड़ी कर सकते हैं। तो यह उनके लिए गडबडी करने का रास्ता फिर खोल दिया है।

[श्री चांदमल मेहता]

मेरा ऐतराज यह था कि नये अध्यापकों की नियुक्ति के समय पहले जो अध्यापक काम करते आ रहे हैं उनको प्रोमोशन दिया जावेगा और इसके बाद कोई वेकेन्सी होगी तो इसके लिए मेट्रिक, इन्टर के नये अध्यापक लिये जावेंगे। पर माननीय मुख्यमन्त्री ने लपेट में कहा कि उनका फिक्सेशन कर रहे हैं, तब सब ठीक हो जावेगा। चार पांच महीने में फिक्सेशन होगा। उस बीच में जो नियुक्तियां की जाने वाली हैं उनमें शिक्षा अधिकारियों के हाथ खुले रहेंगे कि जो कुछ धांधली हमें करनी है वह करलो, जिस किसी को नया अपोइन्टमेन्ट देना है दे दो, जब फिक्सेशन होगा तो आगे की बात आगे देखी जावेगी। क्या ही अच्छा होता कि इस निर्णय के साथ यह भी आदेश दे दिया जाता कि नये अध्यापकों की नियुक्ति के बारे में सरकूलर होने के बावजूद अगर कोई नया अपोइन्मेन्ट करेगा और पुराने काम करने वाले अध्यापकों को प्रोमोशन नहीं देगा तो यह एक्शन उसके खिलाफ लिया जावेगा। अगर ऐसा आश्वासन दिया जाता कि इस बारे में हम कोई कार्यवाही करना चाहते हैं और आगे की कार्यवाही को जो गलत हो सकती है उसको रोकना चाहते हैं तो बडी खुशी की बात होती। पर इस बारे में वे मौन रहे। पर मेरे इन शब्दों के बाद में कुछ रास्ता निकालने की बात उनके ध्यान में आवेगी और इस उम्मीद के आधार पर अध्यक्ष महोदय, में अपने अपने सारे कटौती के प्रस्ताव वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूँ।

श्री मानसिंह महार—मेरे कटौती के प्रस्ताव का जो उत्तर दिया गया वह बहुत ही अच्छा है, यह मैं मानता हूँ। पर गांव वालों को फिर कहा गया कि स्कूलों के लिये पैसा नहीं तो कम से कम मकान तो बनाओ ही जब कि शहरों के लिये ऐसा कुछ नहीं फरमाया गया। शहरों में ऐसी कोई केन्द्र नहीं लगाना चाहते। अगर यह फरमा देते तो मुझे और भी खुशी होती।

इसके बाद में मेरे स्पेसिफिक मामले का जिक्र किया गया। जमवारामगढ़ और बोर्ड के इन्पेक्टर बाहर चले गये थे इसलिये उत्तर नहीं दिया, तो जिस रफ्तार पर मोड़ सको उसे मोड़ सके हैं और इस खुशी को व्यक्त करते हुए मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि मेरे अपने कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की मुझे इजाजत दी जाय।

श्री अध्यक्ष—सातो के सातों।

श्री मानसिंह महार—जी हां

श्री श्रीदास गोयल—जहां तक मेरे चार कटौती के प्रस्ताव का सम्बन्ध है मैं समझता हूँ कि तथ्यों को स्वीकार अवश्य किया गया है पर मैं चाहता हूँ कि इस तरह के भी कदम उठाये जावें कि उन्हें चेतावनी मिले इस प्रकार का आश्वासन दिया जाय। ये शब्द कहते हुए मैं अपने चारों प्रस्ताव वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—श्री श्रीदास गोयल, श्री मानसिंह महार, चांदमल मेहता के कटौती के जो प्रस्ताव हैं, क्या सदन की अनुमनि है कि उन्हें वापिस लेने की उन्हें स्वीकृत दी जावे।

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपने कटौती के स्ताव वापिस लेता हूं।

श्री मानसिंह महार—मैं भी अपने सातों कटौती के प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री श्रीदास गोयल—मैं अपने चारों कटौती के प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—श्री भोपालसिंह।

श्री भोपालसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मन्त्री ने जो आश्वासन दिया कि डेगाना में हाई स्कूल खुल जावेगी, पर यह भी कहना है मेरा कि अगर खुल जावेगी। तो वापिस लूं अपना प्रस्ताव नहीं तो वापिस नहीं लूं।

(हंसी)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैंने साफ निवेदन किया है कि १५ में आते हैं तो लिया जावेगा। पन्द्रह से ज्यादा हुए तो मैं निश्चित कुछ नहीं सकता।

श्री भोपालसिंह—इस पन्द्रह के अन्दर लाना न लाना आपके हाथ की बात है। मैं निवेदन कहता हूं कि उसे भी इन पन्द्रह के नम्बर में लाइये और खोलने की कृपा करिये इस आश्वासन के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें (श्री गोपालसिंह जी) अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति दी जावे।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री भोपालसिंह—मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—श्री लक्ष्मण हीरात।

श्री लक्ष्मण हीरात—माननीय मन्त्री महोदय ने मेरे कटौती प्रस्ताव पर विशेष ध्यान नहीं दिया पर बहुत सी बातें बताई हैं जिससे मुझे सन्तोष है और इसलिए मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूँ।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि श्री लक्ष्मण हीरात को उनका अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति दी जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई।

श्री लक्ष्मण हीरात—मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष—श्री शम्भूसिंह।

श्री शम्भूसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय मुख्य मन्त्री जी के शब्दों से आश्वासन का आभास मिला। (हंसो) इसके अनुसार में आशा करता हूं कि इस आश्वासन को कार्य रूप में शीघ्रतिशीघ्र परिणित किया जावेगा और रुपया पैसा मांगने का प्रश्न नहीं उठाया जावेगा इस आशा के साथ में अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूं।।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि श्री शम्भूसिंह को उनका कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति दी जावे ?

(स्वीकृत)

आज्ञा दी गई।

श्री शम्भूसिंह—मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—श्री जगतसिंह झाला।

श्री जगतसिंह झाला—माननीय मन्त्री जी ने जो आश्वासन फरमाया है, उससे मुझे सन्तोष हो गया है कि वे स्कूल के लिए अवश्य ठीक तवज्जोह देंगे इसलिए मैं अपना कटौती का का प्रस्ताव वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की यह अनुमति है कि श्री जगतसिंह झाला को उनका कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति दी जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई।

श्री जगतसिंह झाला—मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री गौरीशंकर आचार्य—मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा दी जावे।

(स्वीकृत)

आज्ञा दी गई।

श्री गौरीशंकर आचार्य—मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—श्री मोहम्मद इब्राहीम।

श्री मोहम्मद इब्राहीम—मुख्य मन्त्री महोदय पर मेरा पूरा २ यकीन है और मैं अपना रिजोलूशन (कटौती प्रस्ताव) वापिस ले लूंगा। मुझे मिनिस्टर साहब से उम्मीद है कि उर्दू जबान को जरूर तरक्की दी जायेगी····

श्री अध्यक्ष—इसमें उर्दू जबान कहां पर आती है। आप अपना प्रस्ताव देखिये।

श्री मोहम्मद इब्राहीम—मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की इजाजत चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की यह अनुमति है कि इन्हें अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की स्वीकृति दी जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा दी गई।

श्री मोहमद इब्राहीम—मैं अपना रिजोलूशन (कटौती प्रस्ताव) वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—श्री कस्तूरचन्द।

श्री कस्तूरचन्द—माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो मिडिल स्कूल के बारे में आश्वासन दिया है, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं और अपना प्रस्ताव वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है।

(स्वीकृत)

आज्ञा दी गई

Page No 117

श्री कस्तूरचन्द—मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री तेजमल वापना—मैं अपने दोनों प्रस्तावों को वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है।

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई है।

श्री तेजमल वापना—मैं अपने दोनों प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष—मुक्तिलाल मोदी।

(अनुपस्थित)

श्री चुन्नीलाल बिड़ला।

श्री चुन्नीलाल बिड़ला—मैं सदन से अपने कटौती प्रस्ताव को वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति दी जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई।

श्री चुन्नीलाल बिड़ला—मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री रामरतन टिक्कीवाल—मैं सदन से अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति दी जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई।

श्री रामरतन टिक्कीवाल—मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि श्री मुकिलाल मोदी को उनका उनका कटौता का प्रस्ताव वापिस लेने दिया जाय ?

एक माननीय सदस्य—वे तो हैं ही नहीं, चले गये।

श्री अध्यक्ष—श्री संतोषसिंह।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—माननीय अध्यक्ष, मैंने जो कटौती का प्रस्ताव रखा था उसके मुताल्लिक जो बातें मैंने बताई थी कि जोधपुर में डिग्री कालेज के खोलने के लिए वायदा किया था, लेकिन माननीय मंत्रीजी ने यह बताया कि उसकी एवज में बीकानेर में खोलेंगे। इस लिए जोधपुर वालों को इसका बड़ा अफसोस है। मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि उन्होंने जो मकान की दिक्कत बताई थी तो दो साल से यह मामला पेन्डिंग था तो वह इस साल तो पूरा हो जाना चाहिए था और कम से कम अगले साल में खुल जाना चाहिये।

वहां लड़कियों के स्कूल में कन्याओं से फीस आज कई नामों से ली जाती है, उसको बिल्कुल माफ किया जाना चाहिए। बाहर भी कन्याओं से कोई फीस नहीं ली जाती है। लड़कियों से फीस ली जाती है, वह कतई बन्द की जाय।

दूसरे, मैंने कहा था कि वहां बसों का इन्तजाम बराबर नहीं हैं। उनको बडी दिक्कत रहती है। दो, चार बसें और बढ़ाई जायं।

बसों का किराया बहुत बढ़ा दिया है। गरीब आदमी उसको दे नहीं सकते। ऐसी हालत में वहां किराये की फीस कम करनी चाहिए थी।

यह कह कर मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो कटौती के प्रस्ताव श्री एच. के. व्यास ने रखे हैं वे स्वीकार किये जांय।

(अस्वीकृत)

[श्री अध्यक्ष]

उनके छहों कटौती प्रस्ताव गिर गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव श्री भैंरूसिंहजी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

कटौती का प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १४,मुख्य शीर्षक ३७ शिक्षा के सम्बन्ध में ३१ मार्च,१६५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को ४, ४३,५०,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

(मांग स्वीकृत हुई)

(करतलध्वनि)

अब गुलेटिन लगा दिया जावे।

एक माननीय सदस्य—कल लगाया जावे, साहब।

श्री अध्यक्ष—इन शर्तों पर कि कल एप्रोप्रियेशन बिल पास किया जाय। There should be no re uest for time for discussion on the next day.

श्री चन्द्नमल वैद—The Appropriation Bill may be passed day after tomorrow, Sir.

श्री चांदमल मेहता—अभी २६ और ३१ मार्च की तारीख बाकी हैं।

श्री अध्यक्ष—It was due yesterday.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--अध्यक्ष महोदय, इसी ख्याल से तो यह तय किया था कि ११ से ५ बजे तक बैठा जाय। यदि कुछ ज्यादा बोलना चाहते हैं तो ७ बजे तक और बैठा जाय। कल भी बहस करना चाहते हैं तो कर ली जाय, लेकिन एप्रोप्रियेशन बिल कल पास हो जाना चाहिये, यह मैं चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष--कोई स्पेसिफिक डिमान्ड ले लीजिये। Within time-limit that demand will be discussed. The appropriation Bill will be introduced and passed tomorrow. On this assurance we adjourn for tomorrow at 11. oo A. M.

(सभा की कार्यवाही ५ बजकर १५ मिनट पर कल शुक्रवार दिनांक २३ मार्च, १९५६, के ११.०० बजे मध्यान्हपूर्व तक के लिए स्थगित हुई।)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक--२२ मार्च, १९५६।

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(प्रश्नोत्तर जो संबंधित प्रश्नकर्त्ताओं की अनुपस्थितियों में सदन की मेज पर रखे गये और जिन्हें प्रकाशित कराने की मन्त्री महोदयों की अनुमति है)

११. (८ ए. टी. एम.), श्री भोपालसिंह एम. एल. ए. डिविजन नंबर २०—क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) पुनलोता तहसील डेगाना के सर में बन्धा बन्धाने की कितने रुपये की मंजूरी हुई है ?

(ख) यह बंधा कब तक बन्धाया जा सकेगा ?

(ग) इस बन्धे के पेटे में जिन काश्तकारों की भूमि आवेगी उनके नाम क्या हैं और उनकी भूमि कहां कहां है ?

(घ) उपरोक्त काश्तकारों का लगान फी बीघा क्या है और बन्धा बन्धाने के बाद क्या होगा ?

(ङ) सरकार को इस बंधा के बंधाने से कितना फायदा होगा ?

(च) क्या यह सच है कि पुनलोता गांव के काश्तकार इस बंधे के बंधाने के खिलाफ हैं ?

उत्तर

(क) २१, ३७७ रुपया।

(ख) यह बन्धा पानी से अभी भरा हुआ है अतः पानी सूखने के बाद इसका काम हाथ में लिया जावेगा।

(ग) करीब ५.०० एकड़। जिन जिन काश्तकारों की जितनी जितनी भूमि बंध के पेटे में आवेगी उनकी फेहरिस्त तैयार की जा रही है। तैयार होने पर सदन के सम्मुख उसे पेश किया जावेगा।

(घ) अभी भूमि पर जो लगान लिया जाता है उसकी फेहरिस्त संलग्न है बंध बनने से जो जमीन पेटा काश्त होगी उस पर सिंचाईकर ४) रु० फी एकड़ होगा।

(ङ) इस बांध से सिंचाई विभाग को प्रतिवर्ष करीब २०००) रुपये आमदनी होने का अनुमान है

(च) नहीं।

सूची

गांव पूनलोता तहसील डेगाना में भूमि के लगान की प्रचलित दरें

किस्म जमीन	रेट फी बीघा रु०	आ०	पा०
कछार २+	०	१४	०
,, २	०	१२	०
,, २−	०	१०	०
,, ३+	०	६	०
,, ३	०	८	०
बारानी १+	०	१०	०
,, १	०	६	०
,, १−	०	८	०
,, २	०	५	६

	आवपाश रु०	आ०	बारानी अन्दर जाय रु०	आ०	उफतादा रु०	आ०
चाही २+	२	१२	१	०	०	२
,, २	२	१०	१	०	०	२
,, २−	२	८	१	०	०	२
,, ३+	२	४	०	१२	०	२
,, ३	२	०	०	१२	०	२
,, ३−	१	१२	०	१२	०	२

चाही ४+ }
चाही ५ } बिल मुक्ता लगान कायम है। क्लासवार रेट नहीं है

१०७ (२४। एच० एम०) श्री छतरसिंह, एम० एल० ए०, डिविजन नम्बर २८:—क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(क) क्या जालोर में भूस्वामी आंदोलन में कालूसिंह की मृत्यु मोटर के नीचे आजाने से हुई है ?

(ख) अगर हां तो सम्बन्धित व्यक्ति के खिलाफ सरकार ने क्या कदम उठाया है ?

उत्तर

(क) जी हां।

(ख) तारीख ११-२-५६ को इस सम्बन्ध में मुकदमा नम्बर ६ धारा ३०४: ए: भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत थाना उम्मेदपुर में दर्ज हुआ। मामले की तफ्तीश हो रही है।

१११. (३१।ए० टी० एम०) श्री भोपालसिंह एम० एल० ए०. डिविजन नम्बर २०— क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या सरकार पालडी तहसील तहसील डेगाना के कुदरती सर को पानी से भरने के लिये गोठडा के नाले को नहर द्वारा बांधने का विचार रखती है?

(ख) यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों नहीं?

उत्तर

क. नहीं।

ख. इसका उत्तर जांच पड़ताल करने के बाद दिया जा सकता है।

११३. (३२।ए० टी० एम) श्री भोपालसिंह, एम० एल० ए०; डिवीजन नम्बर २०— क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या सरकार भवाल चारणान तहसील डेगाणा, के बान्ध को बंधाने का इस वर्ष में विचार रखती है?

(ख) क्या इस बांध का तखमीना वगैरह सरकार तैयार कर चुकी है?

(ग) इस कार्य को कब तक सरकार पूरा करने का इरादा रखती है?

उत्तर

क. इस वर्ष इसके बनाने की कोई योजना नहीं है क्योंकि इस योजना की सर्वे व जांच पड़ताल अभी तक नहीं हुई है।

ख. योजना का तखमीना वगैरा जांच पडताल के बाद किया जावेगा।

ग. इस योजना की सर्वे होने के पश्चात बांध बांधने का निर्णय किया जा सकता है। कि यह योजना उपयुक्त है या नहीं।

११४. (३३।ए० टी० एम०) श्री भोपालसिंह, एम० एल० ए० डिवीजन नम्बर २०— क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या सरकार झंडा बांध, थावला, तहसील, डेगाना को इस वर्ष बंधवाने का विचार रखती है ?

(ख) यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

उत्तर

क. इस योजना की सर्वे और इनवेस्टीगेशन (Survey and investigahan) की जावेगी जिसके लिए दफ्तर हाल ही में जोधपुर में खोला गया है।

जांच पड़ताल के पश्चात निर्णय किया जावेगा।

११६ (३८।ए० टी० एम०) श्री छतरसिंह एम० एल० ए० डिवीजन नंबर २८— क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

पाली जिले की खारची तहसील में कौन कौन सी जगह लघु सिंचाई की योजना खारची तहसील द्वारा भेजी गई है ?

उत्तर

पाली जिले के खारची तहसील में निम्नलिखित योजनायें हैं जिनकी सर्वे का काम शीघ्र ही शुरू किया जाने वाला है—

१ कलादिया बन्ध

२ सिरीधारी बन्ध

३ सारा बन्ध

१२०. (४३।ए० टी० एम०) श्री लक्ष्मण सिंह, एम० एल० ए० डिवीजन नम्बर २५— क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या चम्बल के बांध से एक नहर तहसील पाटन में होती हुई इन्दरगढ़ जायगी ?

Page No 125

(ख) अगर हां, तो जिन जिन काश्तकारों की जमीनें उसमें आवेंगी, उनको मुआवजा कितना और किन किन आधारों पर मिलेगा ?

उत्तर

क. नहीं ।

ख. प्रश्न 'क' के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता ।

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या १०४ का उत्तर देखिये)

क्रम संख्या	नाम सहायक रजिस्ट्रार	तारीख सहायक रजिस्ट्रार के पद पर कार्य करने की	वेतन १-३-५६	योग्यता	प्रारम्भिक तिथि राज्य सेवा की	वर्तमान स्थान जहां कार्य कर रहे हैं
१.	श्री तुलसीराम शर्मा	१८-३-५०	२५० रु०	बी. ए. (ट्रेन्ड)	५-५-४४	निजी सहायक रजिस्ट्रार
२.	श्री राजमल सिंगवी	१६-१-५१	२५० रु०	बी.ए.एल.एल.बी. (ट्रेंड)	२१-४-४५	उदयपुर
३.	श्री रामनाथ कौल	१६-३-५०	२५० रु०	बी. ए. (ट्रेन्ड)	१५-११-४८	अलवर
४.	श्री इन्द्रनारायण पांडे	२७ मार्च १९५० से ११ मई सन् ५२ तक फिर १ मई ५५	२६० रु०	बी. ए. एल. एल. बी.	१-१२-५०	जयपुर दिनांक १२-५-५२ से ३०-४-५५ तक पंचायत विभाग में रहा
५.	श्री गंगाप्रसाद माथुर	११-७-५३	२३० रु०	मैट्रिक	१६-१०.२४	भरतपुर
६.	श्री गोपीचन्द काला	२८-२-५५	२०० रु०	बी. ए. (ट्रेंड इन्सपेक्टर)	२-६-५१	गंगानगर
७.	श्री रूपचन्द लुहाड़िया	२६ मार्च ५५	२२० रु०	बी. कॉम(ट्रेंड इन्सपेक्टर)	१८-६-४८	जोधपुर
८.	श्री गोविन्दकांत शर्मा	२८-१-५६	२०० रु०	बी. ए. (पूना में ट्रेनिंग पा रहे हैं)		सहकारी विभाग में नियुक्त होने से पूर्व श्री गो.का. एम्पलायमेंट एक्सचेंज आफीसर कोटा थे और इनका सर्विस रिकार्ड अभी प्राप्त नहीं हुआ है ।
९.	श्री महावीर प्रसाद राजवंशी	१-३-५६	२०० रु०	बी. ए. (ट्रेंड इन्सपेक्टर)	२८-१०-४६	जयपुर हैड ऑफिस
१०.	श्री भैरूंरतन व्यास	२६-२-५६	२०० रु०	बी. ए. (ट्रेंड इन्सपेक्टर)	२२-६-४८	कोटा

परिष्ट ३

(कृपया प्रश्न: संख्या ११० का उत्तर देखिये)

STATMENT OF INCOME AND EXPENDITURE OF THE AGRICULTURE FARMS & CATTLE BREEDING FARMS MANAGED BY THE AGRICULTURE DEPARTMENT.

AGRICULTURE FORMS

S. No. Name of the Farm	1952-53		1953-54		1954-55		1955-56		Remarks.
	Expenditure.	Income	Expenditure.	Income	Expenditure.	Income	Expenditure Estimated.	Income Estimated.	
1. Ganganagar.	10,069/-	19,621/-	32,506/-	38,260/-	38,439/-	47,908/-	50,244/-	68,762/-	
2. Padasoli.	20,799/-	24,844/-	23,648/-	42,265/-	25,657/-	21,052/-	16,272/-	13,000/-	
3. Durgapura.	23,203/-	12,137/-	22,631/-	20,003/-	33,772/-	11,414/-	26,287/-	21,369/-	
4. Bassi.	21,426/-	14,627/-	23,449/-	23,493/-	23,801/-	23,317/-	28,842/-	28,075/-	
5. Mandore.	13,421/-	4,592/-	23,170/-	4,701/-	22,746/-	8,657/-	25,836/-	12,785/-	
6. Raisinghnagar.	7,105/-	1,442/-	6,628/-	4,765/-	7,559/-	5,112/-	10,502/-	5,621/-	
7. Padampur.	7,841/-	3,069/-	7,344/-	8,210/-	6,728/-	5,741/-	7,209/-	8,000/-	
8. Jether.	6,667/-	3,398/-	6,760/-	5,178/-	7,032/-	5,060/-	5,822/-	3,116/-	
9. Karanpur.	5,819/-	2,305/-	4,395/-	3,348/-	5,242/-	3,814/-	5,000/-	5,500/-	
10. Bilara.	6,193/-	2,065/-	7,704/-	4,255/-	7,065/-	3,138/-	7,284/-	6,916/-	
11. Sadri.	6,662/-	867/-	4,800/-	1,011/-	7,103/-	4,408/-	6,000/-	3,200/-	
12. Tonk.	7,045/-	109/-	5,291/-	71/-	5,373/-	1,014/-	2,500/-	2,326/-	
13. Banswara.	7,312/-	792/-	6,505/-	819/-	6,115/-	1,113/-	5,500/-	1,782/-	
14. Donadi.	9,601/-	2,246/-	5,387/-	478/-	8,176/-	837/-	3,500/-	1,334/-	
15. Bundi.	7,111/-	3,134/-	8,389/-	3,770/-	5,372/-	2,298/-	7,800/-	1,300/-	

CATTLE BREEDING FBRMRS

1. Bassi.	29,975/-	23,004/-	34,507/-	32,329/-	36,365/-	22,173/-
2. Alwar.	18,527/-	1,888/-	18,265/-	3,370/-	21,096/-	3,247/-
3. Nagor.	11,875/-	1,887/-	11,601/-	3,398/-	13,681/-	5,760/-

परिशिष्ट ४

(कृपया प्रश्न संख्या ११५ का उत्तर देखिये)

नक्शा नियुक्ति कर्मचारियान जिनकी नियुक्ति १-१-५५ के बाद सहकारी विभाग में हुई

क्रमांक	नाम	योग्यता	पद	दिनांक नियुक्ति	प्रार्थना पत्र मांगे या नहीं	नियुक्ति आधार व किसके द्वारा हुई	रिमार्क
१.	२.	३.	४.	५.	६.	७.	८.
			निम्न श्रेणी लेखक				
१.	श्री परसराम	बी० कॉम	सब-अकाउन्टेन्ट	२१-७-५५	नहीं	सरकारी कार्य की आवश्यकतानुसार	
२.	श्री अवयश किशोर हजेला	मैट्रिक	निम्न श्रेणी लेखक	५-६-५५	,,	रजिस्ट्रार सहकारी विभाग द्वारा	
३.	श्री महेशचन्द्र जैन	बी० कॉम	,,	५-६-५५	,,	यह नियुक्ति की गई	
४.	श्री रामअवतार जैन	मैट्रिक	,,	५-६-५५	,,	,,	
५.	श्री रामचरण शर्मा	,,	,,	५-६-५५	,,	,,	
६.	श्री आनन्दीलाल तिवाड़ी	,,	,,	५-६-५५	,,	,,	
७.	श्री गिरिराज जोशी	,,	,,	१७-१०-५५	,,	,,	
८.	श्री श्रीनिवास	,,	,,	३-१२-५५	,,	अध्यक्ष ऋण समझौता समिति	
९.	श्री सोहनमल	,,	,,	१०-१२-५५	,,	,,	
१०.	श्री बिहारीमल	,,	,,	२१-१-५६	,,	रजिस्ट्रार	
११.	श्री आशाराम	,,	,,	२८-१-५६	,,	,,	
१२.	श्री मदनलाल	इन्टर	,,	१-३-५६	,,	,,	
१३.	श्री नरेन्द्र कुमार	ग्रेजुएट	निरीक्षक	१४-७-५५	,,	रजिस्ट्रार सहकारी विभाग द्वारा बाद में लोक सेवा आयोग द्वारा चुन लिये गये	

क्रमांक	नाम	योग्यता	पद	दिनांक नियुक्ति	प्रार्थना पत्र मांगे या नहीं	नियुक्ति आधार व किसके द्वारा हुई	रिमार्क
१.	२.	३.	४.	५.	६.	७.	८.
१४.	श्री विनोद बिहारी	बी० कॉम	,,	१४-७-५५	,,	रजिस्ट्रार सहकारी विभाग द्वारा	,,
१५.	श्री मोहन किशोर शर्मा	ग्रैजुएट	,,	३१-८-५५	,,	,,	,,
१६.	श्री शिवकुमार पथिक	,,	,,	१३-९-५५	लोक सेवा आयोग द्वारा आवेदन पत्र मांगे गये	,,	
१७.	श्री गनेशमल मेहता	बी० ए० कॉ ट्रेन्ड.	,,	२-४-५५	,,	,,	
	अंक परीक्षक (ऑडीटर)						
१८.	श्री केदारनाथ	बी० कॉम	,,	५-१-५६	,,	,,	
१९.	श्री अटलबिहारी माथुर	बी० ए०	,,	,,	,,	,,	
२०.	श्री भंवरलाल	एम० ए० बी० कॉम	,,	,,	,,	,,	
२१.	श्री ईसरदान	बी० कॉम	,,	,,	,,	,,	
२२.	श्री रामपाल	,,	,,	,,	,,	,,	
२३.	श्री युगल किशोर	,,	,,	,,	,,	,,	
म२४.	श्री शिवकुमार जैन	,,	,,	,,	,,	,,	
२५.	श्री पूरणमल	,,	,,	,,	,,	,,	
२६.	श्री शंकरलाल	,,	,,	,,	,,	,,	
२७.	श्री दिनेश चन्द्र	,,	,,	,,	,,	,,	

क्रमांक	नाम	योग्यता	पद	दिनांक नियुक्ति	प्रार्थना पत्र मांगे या नहीं	नियुक्ति आधार व किसके द्वारा हुई	रिमार्क
१.	२.	३.	४.	५.	६.	७.	८.
२८.	श्री किशन चन्द्र	,,	,,	,,	,,	रजिस्ट्रार सहकारी विभाग द्वारा	
२९.	श्री मांगीलाल शर्मा	,,	,,	,,	,,	,,	
३०.	श्री श्याम सुन्दर गुप्ता	,,	,,	,,	,,	,,	
३१.	श्री रामचन्द्र भाटिया	,,	,,	,,	,,	,,	
३२.	श्री निर्मल कुमार	ग्रेजुएट	,,	२१-६-५५	,,	,,	
३३.	श्री सोभागमल जैन	बी० कॉम	,,	१२-६-५५	,,	,,	
३४.	श्री महावीर प्रसाद	ग्रेजुएट	,,	१७-१०-५५	,,	,,	
३५.	श्री शिवलाल सिंह	,,	,,		,,	,,	
			सहायक निरीक्षक				
३६.	श्री जगमोहनलाल	बी० ए०	सहायक निरीक्षक	१-११-५५	लोक सेवा आयोग	रजिस्ट्रार सहकारी विभाग	
३७.	श्री हरिश्चन्द्र	मैट्रिक	,,	,,	द्वारा चुने गये	,,	
		साहित्य रत्न				,,	
३८.	श्री गिरिराज प्रसाद	मैट्रिक	,,	,,	,,	,,	
३९.	श्री बाबूलाल	,,	,,	,,	,,	,,	
४०.	श्री हरनाथसिंह	,,	,,	,,	,,	,,	
४१.	श्री कन्हैयालाल	,,	,,	,,	,,	,,	
४२.	श्री फूलचन्द	इन्टर मीजिएट	,,	,,	,,	,,	
४३.	श्री पूरणमल	मैट्रिक	,,	,,	,,	,,	

क्रमांक	नाम	योग्यता	पद	दिनांक नियुक्ति	प्रार्थना पत्र मांगे या नहीं	नियुक्ति आधार व किसके द्वारा हुई	रिमार्क
१.	२.	३.	४.	५.	६.	७.	८.
४४.	श्री नत्थीलाल	,,	,,	२२-१०-५५	नहीं	रजिस्ट्रार सहकारी विभाग द्वारा	
४५.	श्री रामदयाल	,,	,,	२८-६-५५	,,	,,	
४६.	श्री गिरराज प्रसाद शर्मा	इन्टर मीजिएट	,,	१-११-५५	लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गये	,,	
४७.	श्री राधेश्याम	,,	,,	,,	,,	,,	
४८.	श्री मोहम्मद शरीफ	मैट्रिक	,,	,,	,,	,,	
४९.	श्री किशोरसिंह	एम० ए०	,,	,,	,,	,,	
५०.	श्री मोहनलाल शर्मा	मैट्रिक	,,	,,	,,	,,	
५१.	श्री मोतीलाल	,,	,,	,,	,,	,,	
५२.	श्री रूपलाल	इन्टर	,,	,,	,,	,,	
५३.	श्री टिकट नारायण	मैट्रिक	,,	,,	,,	,,	
५४.	श्री गोपाललाल	,,	,,	,,	,,	,,	
५५.	श्री जसवन्तसिंह	इन्टर	,,	,,	,,	,,	
५६.	श्री रामेश्वरलाल	,,	,,	,,	,,	,,	
५७.	श्री बहादुरराम	मैट्रिक	,,	,,	,,	,,	
५८.	श्री ठाकुरदत्त	,,	,,	,,	,,	,,	
५९.	श्री नवल किशोर	इन्टर	,,	,,	,,	,,	
६०.	श्री शोभाराम	मैट्रिक	,,	,,	,,	,,	

क्रमांक नाम		योग्यता	पद	दिनांक नियुक्ति	प्रार्थना पत्र मांगे या नहीं	नियुक्ति आधार व किसके द्वारा हुई	रिमार्क
१.	२.	३.	४.	५.	६.	७.	८.
६१.	श्री देवीदयाल शर्मा	,,	,,	,,	,,	रजिस्ट्रार सहकारी विभाग द्वारा	
६२.	श्री गिरराज प्रसाद मिश्रा	,,	,,	,,	,,	,,	
६३.	श्री जोहरीलाल	,,	,,	,,	,,	,,	
६४.	श्री सूर्य प्रसाद	,,	,,	,,	,,	,,	
६५.	श्री प्रेमचन्द जोशी	,,	,,	,,	,,	,,	
६६.	श्री किशनलाल गुप्ता	,,	,,	,,	,,	,,	
६७.	श्री दीनदयाल शर्मा	,,	,,	,,	,,	,,	
६८.	श्री केदारलाल अग्रवाल	,,	,,	,,	,,	,,	
६९.	श्री जशपालसिंह तमवा	,,	,,	,,	,,	,,	
७०.	श्री महावीर प्रसाद माथुर	,,	,,	,,	,,	,,	
७१.	श्री दुर्गाप्रसाद शर्मा	,,	,,	,,	,,	,,	
७२.	श्री छगनलाल शर्मा	,,	,,	,,	,,	,,	
७३.	श्री गुलाबचन्द जैन	,,	,,	,,	,,	,,	
७४.	श्री जगन्नाथ प्रसाद	,,	,,	,,	,,	,,	
७५.	श्री मोहनलाल शर्मा	,,	,,	,,	,,	,,	
७६.	श्री दामोदरलाल गुप्ता	,,	,,	,,	,,	,,	
७७.	श्री राधेश्याम वैश्य	,,	,,	,,	,,	,,	
७८.	श्री हनुमान सहाय	,,	,,	,,	,,	,,	

क्रमांक	नाम	योग्यता	पद	दिनांक नियुक्ति	प्रार्थना पत्र मांगे या नहीं	नियुक्ति आधार व किसके द्वारा हुई	रिमार्क
१.	२.	३.	३.	५.	६.	७.	८.
७६.	श्री दुर्गाप्रसाद	,,	,,	,,	,,	रजिस्ट्रार सहकारी विभाग द्वारा	
८०.	श्री चन्द्र प्रकाश गर्ग	,,	,,	,,	,,	,,	
८१.	श्री हरगोविन्द शुक्ला	,,	,,	,,	,,	,,	
८२.	श्री शिवलाल गुप्ता	,,	,,	,,	,,	,,	
८३.	श्री पन्नालाल शर्मा	,,	,,	,,	,,	,,	
८४.	श्री दीनदयाल	,,	,,	,,	,,	,,	
८५.	श्री भंवरलाल गोतम	,,	,,	,,	,,	,,	
८६.	श्री मदनलाल गुप्ता	,,	,,	,,	,,	,,	
८७.	श्री प्रेमचन्द पनवार	,,	,,	,,	,,	,,	
८८.	श्री शरनदास वर्मा	,,	,,	,,	,,	,,	
८६.	श्री नरेन्द्र कुमार व्यास	,,	,,	,,	,,	,,	
६०.	श्री रामचन्द्र शर्मा	,,	,,	,,	,,	,,	
६१.	श्री शिवलाल त्रिवेदी	,,	,,	,,	,,	,,	
६२.	श्री पन्नालाल यादव	,,	,,	,,	,,	,,	
६३.	श्री कृपाशंकर	,,	,,	,,	,,	,,	
६४.	श्री नेकशमल मेहता	,,	,,	,,	,,	,,	
६५.	श्री सुरेश चन्द्र अग्रवाल	,,	,,	,,	,,	,,	
६६,	श्री रामदयाल ओझा	,,	,,	,,	,,	,,	

क्रमांक	नाम	योग्यता	पद	दिनांक नियुक्ति	प्रार्थना पत्र मांगे या नहीं	नियुक्ति आधार व किसके द्वारा हुई	रिमार्क्स
१.	२.	३.	४.	५.	६.	७.	८.
९७.	श्री जगन्नाथ प्रसाद ओझा	,,	,,	,,	,,	रजिस्ट्रार सहकारी विभाग द्वारा	
९८,	श्री प्रमोदराय आचार्य	,,	,,	,,	,,	,,	
९९.	श्री कन्हैयालाल ननावती	,,	,,	,,	,,	,,	
१००.	श्री रामेश्वर प्रसाद वर्मा	,,	,,	,,	लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं चुने गये	,,	
१०१.	श्री चन्द्र शेखर मेहता	,,	,,	,,	,,	,,	
१०२.	श्री रतनसिंह भार्गव	,,	,,	,,	,,	,,	
१०३.	श्री मदनलाल	,,	,,	,,	,,	,,	
१०४.	श्री राधेश्याम गुप्ता	,,	,,	,,	,,	,,	
१०५.	श्री मोहनलाल	,,	,,	,,	,,	,,	
१०६.	श्री गुलाबचन्द जैन	,,	,,	,,	,,	,,	
१०७.	श्री आत्मासिंह	,,	,,	,,	लोक सेवा आयोग द्वारा चुने ग[illegible]	,,	
१०८.	श्री मिश्रीलाल	,,	,,	,,	,,	,,	
१०१,	श्री राधेश्याम	,,	,,	,,	,,	,,	
११०.	श्री रामेश्वर प्रसाद वर्मा	,,	,,	,,	,,	,,	
	चपरासी (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियान)						
१११.	श्री कन्हैयालाल	,,	चपरासी	,,	,,	सहायक रजिस्ट्रार द्वारा	

क्रमांक	नाम	योग्यता	पद	दिनांक नियुक्ति	प्रार्थना पत्र मांगे या नहीं	नियुक्ति आधार व किसके द्वारा हुई	रिमार्क
१.	२.	३.	४.	५.	६.	७.	८.
११२,	श्री बाबूलाल	,,	,,	,,	,,	सहायक रजिस्ट्रार द्वारा	
११३.	श्री घेवरदास	,,	,,	,,	,,	,,	नौकरी से हटाया गया
११४.	श्री मंगलसिंह	,,	,,	,,	,,	,,	स्तीफा देकर चला गया
११५.	श्री बाबू खां	,,	,,	,,	,,	,,	
११६.	श्री देवीनारायण	कुछ हिन्दी पड़ा हुआ	,,	,,	,,	,,	
११७.	श्री सोहनलाल	,,	,,	,,	,,	,,	
११८.	श्री पन्नालाल	,,	,,	,,	,,	,,	
११९.	श्री रामचरन	,,	,,	,,	,,	,,	
१२०.	श्री वालाराम	,,	,,	,,	,,	,,	
१२१.	श्री मुग्ज्ञानसिंह	हिन्दी जानने वाला	,,	१-१२-५५	,,	,,	
१२२.	श्री छुट्टनलाल	,,	,,	२२-१२-५५	,,	,,	
१२३.	श्री मातादीन	,,	,,	२०-१२-५५	,,	,,	
१२४.	श्री टेजसिंह	,,	,,	१-६-५५	,,	सहायक रजिस्ट्रार व डिप्टी रजिस्ट्रार द्वारा	
१२५.	श्री करनसिंह	,,	,,	१-८-५५	,,		

क्रमांक	नाम	योग्यता	पद	दिनांक नियुक्ति	प्रार्थना पत्र मांगे या नहीं	नियुक्ति आधार व किं कि द्वारा हुई	रिमार्क
१.	२.	३.	४.	५.	६.	७.	८.
१२६.	श्री नन्दलाल	,,	,,	१-८-५५	,,	,,	
१२७.	श्री रामेश्वर प्रसाद	,,	,,	१७-१०-५५	,,	,,	
१२८.	श्री रामसहाय	,,	,,	२१-२-५६	,,	,,	
१२६.	श्री कल्यान सहाय	हिन्दी मिडिल	,,	२-३-५६	,,	,,	
१३०.	श्री अब्दुल लतीफ	,,	,,	२४-१-५६	,,	,,	
	असिसटेन्ट रजिस्ट्रार						
१३१.	श्री गोविन्दकान्त शर्मा	बी० ए०	असिसटेन्ट रजिस्ट्रार	२८-१-५६	नहीं	सरकारी कार्य की आवश्यकतानुसार गवर्नमेन्ट द्वारा की गई	

शुद्धि-पत्र

दिनांक २२ मार्च, १९५६

(१) जहां "मांग संख्या ५४- शिक्षा" अथवा अन्य इसी प्रकार से शीर्षक हो वहां "मांग संख्या १४- शिक्षा" पढ़ा जाय।

(२) पृष्ठ १४० के शीर्ष पर जो शीर्षक "तारांकित प्रश्नोत्तर" मुद्रित हुआ है उसके स्थान पर कृपया यह शीर्षक पढ़िये "जन लेखा व प्राकलन समितियों (१९५६-५७) के निर्वाचित सदस्यों की घोषणा"।

(३) पृष्ठ १४९७ के पश्चात् के पृष्ठ क्रमशः १४९८, १४९९, १५००, १५०१, १५०२, १५०३, १५०४, १५०५, १५०६, १५०७ व १५०८ पढ़े जावें।